पंचम माला, खंड 13, अंक 21
Fifth Series, Vol. XIII, No. 21

मंगलवार, 11 अप्रैल, 1972/22 चैत्र, 1894 (शक)
Tuesday, April 11, 1972/Chaitra 22, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र / Fourth Session]

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On 15-2-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 13 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/Eaglish translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 21, मंगलवार, 11 अप्रैल, 1972/ 22 चैत्र, 1894 (शक)

No. 21, Tuesday, April 11, 1972/ Chaitra 22, 1894 (Saka)

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता.प्र. संख्या S. Q. Nos.			
341	राज्यों में आम चुनावों के बारे में शिकायतें	Complaints regarding General Elections in States ...	1—5
342	लागोस में आयोजित भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी	Indian Industrial Exhibition at Lagos ...	5—6
343	प्रस्तावित साझी यूरोपीय मुद्रा का भारत पर प्रभाव	Effect on India of the Proposed Common European Currency ...	7—8
345	उत्तर कोरिया के साथ व्यापारिक समझौता	Trade Agreement with North Korea ...	8—9
346	उड़ीसा में कटक और पारादीप के बीच रेलवे लाइन	Railway Link between Cuttack and Paradip in Orissa ...	9—10
347	भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण	Electrification of Indian Railways ...	10—13
348	फरक्का बांध के कारण गंगा के बहाव में रुकावट पड़ना	Farakka Barrage causing Obstruction in the Flow of River Ganga ...	13—14
349	जल संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाना	Formulation of National Water Policy ...	14—16
350	गुजरात को कोयला भेजना	Coal Despatches to Gujarat ...	16—18
351	हिमाचल प्रदेश में स्योल परियोजना पर खर्च की गई धन राशि	Amount Spent on Seul Project in Himachal Pradesh ...	19—20
352	भारतीय रेलवे में रेलपथ कर्मचारियों (परमानेंट वे स्टाफ) को ट्रंक रूट भत्ता	Trunk Route Allowance to Permanent Way Staff on Indian Railways ...	20—21
354	केरल सरकार की रबड़ का बाजार ढूंढने हेतु सहायता	Assistance to Kerala Government for binding Rubber Market ...	21—22

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक हैं कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय		Subject	पृष्ट/Pages
ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.			
355	श्रीलंका को रेलवे वैगनों की सप्लाई	Supply of Railway Wagons to Ceylon ...	22—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
344	स्टेशन मास्टरों की काम की दशा में सुधार	Better Working Conditions for Station Masters ...	23
353	वैगन बनाने वालों को आयातित इस्पात की सप्लाई	Supply of Imported Steel to Wagon Builders ...	24
356	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के गैर-लाजिमी कर्मचारियों को क्वाटरों का आबंटन	Allotment of Quarters to non-Essential Staff of Delhi Division (Northern Railway) ...	24
357	मध्य प्रदेश में तापीय 'विद्युत संयंत्र लगाया जाना	Thermal Power Plant in Madhya Pradesh ...	24—25
358	कड़े बालों (ब्रिसल्स) के निर्यात में कमी	Decline in Export of Bristles ...	25—26
359	केरल में चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे बिकास पर व्यय	Amount of Expenditure during Fourth Plan on Development of Railways in Kerala ...	27
360	डेनमार्क से व्यापार समझौता	Trade Agreement with Denmark ...	27
2424	व्हारफेज चार्जेज़ (उत्तर रेलवे) में छूट देना	Waiver of Wharfage Charges (Northern Railway) ...	27—28
2425	आयकर न्यायाधिकरण के समक्ष आयकर से अनिर्णीत मामले	Pending Cases of Income Tax before Income Tax Tribunals ...	28—29
2426	पार्लियामेंट हाउस में रेलवे कैंटीन द्वारा लिया जाने वाला दूध	Procurement of Milk by Railway Canteen in Parliament House ...	29—30
2427	आजई नदी (बिहार) पर पुनासी बांध का निर्माण	Punasi Dam on Ajai River (Bihar) ...	30
2428	जोधपुर लोको वर्क्स का कार्य-करण	Working of Jodhpur Loco Works ...	30
2429	तराशे हुए पत्थरों के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Cut Stones ...	31
2430	राजस्थान को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Rajasthan ...	31—32
2431	देहरी-आन-सोन और बरवाडीह (पूर्व रेलवे) के बीच दिन में एक अन्य रेलगाड़ी का चलाया जाना	Introduction of another Day Train between Dehri-on-Sone and Barwadi (Eastern Railway) ...	32

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
2432	मुगलसराय स्टेशन के लिए देहरी ओन-सोन में टिकटों की बिक्री	Sale of Tickets at Dehri-on-Sone for Mughal Sarai Station	...	32
2433	रेलवे फाटकों पर उपरि पुल	Overbridges at Railway Level-Crossing	...	33—34
2434	मेरालग्राम और रामना रेलवे स्टेशनों (पूर्व रेलवे) पर अपर क्लास प्रतीक्षालयों की व्यवस्था	Provision of Upper Class waiting Rooms at Meralgram and Ramna Railway Stations (Eastern Railway)	...	34
2435	बिहार में लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की यात्रा / दैनिक भत्ते का भुगतान	Payment of TA/DA to Employees who performed Election Duties during Mid Term Lok Sabha Polls in Bihar	...	35
2436	पेरुगुंभी रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) का 'फलैग स्टेशन' के रूप में दर्जा बनाया जाना	Raising Perunguzhi Railway Station as a Flag Station (Southern Railway)	...	35
2437	व्यारा रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर उपरपुल का निर्माण	Construction of an Over-Bridge at Vyara Railway Station (Western Railway)	...	35
2438	रेलवे के मुख्य लेखा-परीक्षकों द्वारा निरीक्षण रेल डिब्बों का उपयोग	Use of Inspection Carriages by Chief Auditors on Railways	...	36
2439	'एशियन पेपर कम्यूनिटी' बनाने का प्रस्ताव	Proposal for Asian Pepper Community	...	36—37
2440	पश्चिम रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्कों की मंजूरशुदा संख्या	Sanctioned Strength of Commercial Clerk, Western Railway	...	37
2441	संगचल कर्मचारियों के लिये विश्राम सुविधायें	Resting facilities for Running Staff	...	37—38
2442	रनिंग रूमों में अत्यधिक भीड़	Overcrowding of Running Rooms		38
2443	संगचल भत्ते का भुगतान	Payment of Running Allowance	...	38—40
2444	आयात और निर्यात कार्यों को पृथक् करने संबंधी राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन का वक्तव्य	STC Chairman's statement regarding separation of Import and Export Functions of Corporation	...	40
2445	तकनीकी पदों पर इंजीनियरी के डिप्लोमाधारियों और डिग्रीधारियों की भर्ती	Recruitment of Engineering Diploma and Degree Holders for Technical Posts	...	40—41

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2446	श्री लंका द्वारा तामिल दैनिकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना	Tamil Dailies Entry banned by Ceylon ...	41
2447	बिना सोचे समझे नलकूपों का खोदा जाना	Indiscriminate Boring of Tube-wells ...	41—42
2448	विवाह की वैध न्यूनतम आयु को बढ़ाना	Raising of Legal Minimum Age of Marriages ...	42
2449	कपास के लिये न्यूनतम मूल्य समर्थन नीति	Minimum Price Support Policy for Cotton ...	42
2450	बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली के स्प्रिंग कार्नीवाल में घटित घटना	Incidents in Spring Carnival held in Baroda House, New Delhi ...	43
2451	नियंत्रित कपड़े का मूल्य बढ़ाने के लिए मिल मालकों का दबाव	Pressure from Mill Owners to raise Price of Controlled Cloth ...	43
2452	काजू उद्योग में संकट के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा केरल के सभी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल को दिये गये आश्वासन को पूरा करना	Fulfilment of Prime Minister's Promises to All Party Delegation from Kerala on crisis in Cashew Industry ...	43—44
2453	कोट्टावालसा किरुनदुल रेल लाइन का निर्माण	Construction of Kottavalsa Kirundul Line ...	44—45
2455	व्यापार विकास प्राधिकरण का यूरोपियन देशों को कुछ वस्तुओं का निर्यात करने सम्बन्धी करार	TDA Deal with European Countries for Exporting certain Commodities ...	45—46
2456	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापान को मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore to Japan by M.M.T.C. ...	46
2457	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा पेरु से विद्युत विश्लेषण तांबे का आयात	Import of Electrolytic Copper by M.M.T.C. from Peru ...	46
2458	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा रूमानिया को लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore by M.M.T.C. to Rumania ...	47
2459	लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	47
2460	एशियाई साझा बाजार की स्थापना	Setting up of an Asian Common Market	47

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
2461	कालीकट विश्वविद्यालय को दोलन दर्शी (ग्रासीलोस्कोप) का ग्रायात करने का लाइसेंस देना	icence for Importing Oscilloscope by Calicut University ...	48
2462	यूगोस्लाविया को मंत्रालय स्तर का प्रतिनिधिमंडल	Ministerial Delegation to Yugoslavia ...	48–49
2463	मध्य प्रदेश से कोयले का भेजा जाना	Movement of Coal from Madhya Pradesh ...	49
2464	वित्त सलाहकार ग्रौर मुख्य लेखा ग्रधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के कार्यालय द्वारा जाली बिलों का भुगतान	Payment by Office F. A. and C.A.O. Gorakhpur on Bogus Bills (North Eastern Railway) ...	50
2465	यूरोपीय साझा बाजार के देशों से भारत को उपलब्ध सुविधाएं	Facilities available to India from E C.M. Countries ...	50
2466	ग्रमरीका को खिलौना हाथियों ग्रौर खिलौना गधों का निर्यात	Export of Toy Elephants and Toy Donkeys to America ...	51
2467	वनरपती रोड ग्रौर कुरुमूर्ति स्टेशनों (दक्षिण मध्य रेलवे) के बीच एक मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Train between Wanrpati Road and Kurumurthi Stations (South Central Railway) ...	51
2468	चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification during Fourth Five Year Plan ...	51—52
2469	झांसी डिवीजन में तार काटने की घटनाएं	Incidents of Wire Cutting in Jhansi Division ...	52
2470	झांसी कानपुर लाइन पर चोरी तथा हत्या की घटनायें	Incidents of thefts and murder in Trains on Jhansi Kanpur Line ...	52–53
2471	झांसी इटारसी तथा भुसावल यात्री गाड़ियों में चोरी की घटनाएं	Incidents of thefts in Jhansi Itarsi and Bhusawal Passenger Trains ...	53
2472	ग्रन्य देशों को इंजीनियरी की तकनीकी जानकारी देना	Export of Engineering Technical know-how ...	53
2473	माल की हानि के कारण दण्डित रेल कर्मचारी	Railway Employees punished for loss of goods ...	53
2474	जुनागढ़ जिले में मालगाम ग्राम में एक नये रेलवे स्टेशन का निर्माण	Construction of new Railway Station at Bhalgam Village in Junagarh District ...	54

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
तां० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
2475 डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट मुरादाबाद के विरुद्ध काले झंडों से प्रदर्शन	Black flag demonstration against Divisional Superintendent, Moradabad	54
2476 राजधानी एक्सप्रैस के गार्ड और ड्राइवरों को ट्रंक मार्ग भत्ता	Trunk route allowance to Guards and Drivers of Rajdhani Express ...	54
2477 इन्दौर रेलवे स्टेशन से अर्जित राजस्व	Revenues earned from Indore Railway Station ...	54—55
2478 फलों का निर्यात	Export of Fruits ...	55—56
2479 तमिलनाडु में रेलवे के नये ऊपरी/नीचे के पुलों का निर्माण	Construction of new over/under Railway Bridges in Tamil Nadu ...	56
2480 विभिन्न रेलों में भ्रष्टाचार का उन्मूलन और उनकी सेवाओं में सुधार	Eradication of Corruption and Improvement in Services on various Railways ...	56—57
2481 बागमती नदी (बिहार) द्वारा हुई क्षति	Damage caused by Bagmati River (Bihar) ...	57
2483 राज्य व्यापार निगम का गेरज उपकरणों के निर्यात के लिए रूस के साथ करार	STC contract with Soviet Union for Exporting Garage Equipment ...	57
2484 रेलवे सुरक्षा निर्माण निधि में से पश्चिम बंगाल को दी गई सहायता	Assistance given to West Bengal from Railway Safety Works Fund ...	58
2485 मसालों का निर्यात	Export of Spices	58
2486 आसाम मेल में नई दिल्ली और बरौनी के बीच भोजन यान की व्यवस्था	Introduction of Dining Car in Assam Mail between New Delhi and Barauni ...	58—59
2487 काहिरा में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में बिक्री	Sale at International Fair at Cairo ...	59
2488 विदेशों में संयुक्त उद्यम	Joint Enterprises in Foreign Countries	59
2489 निर्यात में वृद्धि की दर का कम हो जाना	Fall in Export Growth Rate	60
2490 पश्चिम बंगाल में ग्राम्य विद्युतीकरण	Rural Electrification in West Bengal ...	61—62
2491 उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार	Trade with North Korea and South Korea ...	62—64

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
2493	पटसन और चाय के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned through Jute and Tea ...	64—65
2494	पूर्वोत्तर रेलदे के मोकामेह घाट पर बाटा शू कम्पनी द्वारा रेलवे की भूमि पर कब्जा करना	Occupation of Railway Land at Mokameh Ghat by Bata Shoe Company (North Eastern Railway) ...	65
2495	मोकामेह घाट, पूर्वोत्तर रेलवे में हरिजनों को रेलवे की भूमि आबंटित करना	Allotment of Railway Land to Harijan at Mokameh Ghat (North Eastern Railway) ...	65
2496	क्विलोन और नीडाकारा के बीच रेल संपर्क	Rail Link between Quilon and Neendakara ...	66
2497	रेलवे में कथित भ्रष्टाचार	Alleged Corruption in Railway ...	66
2498	स्टेशन मास्टरों के स्थानांतरण संबंधी नीति	Transfer Policy about Station Masters ...	66
2499	डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति, धनवाद, (पूर्व रेलबे) से स्कूटरर ऋण घोटाले के संबंध में अध्यावेदन	Representation from Divisional Railway Emploɔees Coordination Committee, Dhanbad regarding Sco oter Loan Scandal (Eastern Railway) ...	66—67
2500	डिवीजनल रेल कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद (पूर्व रेलवे) का भ्रष्टाचार समाप्त करने के बारे ज्ञापन	Memorandum by Divisional Railway Employees, Co-ordination Committee Dhanbad regarding Elimination of Corruption (Eastern Railway) ...	67
2501	लोको शैड, धनवाद में काम करने वाले संगचल कर्मचारी (रनिंग स्टाफ)	Running Staff working in Loco-shed Dhanbad ...	67—68
2502	आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं	Rural Electrification Schemes for Chittoor District of Andhra Pradesh ...	68
2503	इटारसी और भुसावाल स्टेशनों के बीच के स्टेशनों पर सवारी गाड़ियों का अधिक देर तक रुकना	Detention of Passenger trains between Itarsi and Bhusawal at Intermediate Stations for long hours ...	68—69
2504	मध्य प्रदेश से कोसे के कपड़े का निर्यात	Export of Kosa cloth from Madhya Pradesh ...	69
2505	मध्य रेलवे पर व्यापारियों द्वारा मांगे गये वैगन	Wagons demanded by Traders on Central Railway ...	69—70

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2506	मध्य रेलवे में केला व्यापारियों को वैगन देना	Wagons for Bannanas Traders on Central Railway ...	70
2507	बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) के नावथा ग्राम के पास ताप्ती नदी परियोजना	Project on Tapti River, near Novtha village of Burahanpur (M. P.) ...	70
2508	रेलवे बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों और अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Senior Officers and Additional Members in Railway Board ...	70—71
2509	आप्ता और मैलौर के बीच रेल लाइन का सर्वेक्षण	Survey for Rail Line between Apta and Mayloure ...	71—72
2510	बुलन्दशहर और खुर्जा के बीच सीधी गाड़ी (ट्रेन) का चलाया जाना	Introduction of another Day Train between Bulandshahar and Khurja ...	72
2511	नीमच और जावद स्टेशनों (रतलाम डिवीजन, पश्चिम रेलवे) के लिये लोड वैनों की सप्लाई	Supply of Load Vans for Neemuch and Jawad Stations (Ratlam Division, Western Railway) ...	72—73
2512	नेपाल, लंका, और जापान को मिर्च, प्याज और मसालों का निर्यात	Export of Chillies, Onions and Spices to Nepal, Ceylon and Japan ...	73
2513	रतलाम (पश्चिम रेलवे) के डीजल शेड का विस्तार	Expansion of Diesel Shed Ratlam (Western Railway) ...	73
2514	विद्युत परियोजनाओं के लिये मध्य प्रदेश को दी गई सहायता	Assistance given to Madhya Pradesh for Power Projects ...	74
2515	मध्य प्रदेश में मिलों का बन्द होना	Closure of Mills in Madhya Pradesh ...	74
2516	जुकेही और पाकाड़िया रोड स्टेशनों (मध्य रेलवे) के बीच एक मालगाड़ी और एक खड़े माल डिब्बों की टक्कर	Collision of a Goods Train and a Stationary Wagon between Jukehi and Pakaria Road Stations (Central Railway) ...	74—75
2517	टूंडला को पार्सल लाने ले जाने वाले ठेकेदार से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation from Parcel Handling Contractor at Tundla ...	75
2518	इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्राईवेट डाक्टरी प्रमाण पत्रों का दिया जाना	PMCs submitted by Railway Staff Allahabad Division (Northern Railway) ...	75—76

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2519	बखत्यारपुर राजगीर रेलवे लाइन का गया / बोध गया तक विस्तार	Extension of Bakhatiarpur and Rajgir Railway Line upto Gaya/Bodh Gaya ...	76
2520	बिहार राज्य के लिये बाढ़ नियंत्रण कार्य	Flood control measures for Bihar State ...	76—77
2521	दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर टिकट निरीक्षण कर्मचारियों के लिये आरामकक्ष	Rest Rooms for Tickets Checking Staff at Delhi and New Delhi Stations ...	77
2522	मधुबनी कला का विकास और उस का निर्यात	Development and export of Madhubani Art ...	77—78
2523	दक्षिण रेलवे में एक डिवीजन से दूसरे में वायरलेस आपरेटरों का स्थानांतरण	Transfer of Wireless Operators from One Division to another (Southern Railway) ...	78
2524	दक्षिण रेलवे के हैड सिगनेलरों का स्थानांतरण	Transfer of Head Singnaller on Southern Raliway ...	79
2525	सेंट थामस माउन्ट तथा मीनमबातकम (दक्षिण रेलवे) के बीच नगनाल्लूर में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाना	Construction of Railway Station at Nanganallur between St. Thomas Mount and Meenambakkam (Southern Railway) ...	79
2526	त्रिपुरा को कोयला व्यापारियों से कोयले की ढुलाई के सम्बन्ध में अभ्यावेदन	Representation from Coal Merchants of Tripura for Transportation of coal ...	79—80
2527	ओखला और दिल्ली सफदरजंग स्टेशनों पर कार्य करने वाले इलेक्ट्रिकल सिगनल मैंन्टेनर्स को समायोपरि भत्ते की अदायगी न करना	Non-payment of Overtime Allowance to Electrical Signal Maintainers at Okhla and Delhi Safdarjang ...	80
2528	जालंधर और लुधियाना में नियुक्त खलासियों एवं इलेक्ट्रिकल सिगनल मैंटेनर्स को रात्रि ड्यूटी भत्ता	Migat-Duty allowance to Khalasi and Electrical Signal Maintainers at Jullundur and Ludhiana ...	81
2530	कुछ वस्तुओं पर रेल भाड़े की पूर्व अदायगी को अनिवार्य बनाने की योजना	Scheme of Compulsory Prepayment of Railway Frieght on certain Commodities ...	81—82
2531	जूट तथा मेस्टा का उत्पादन	Jute and Mesta Production ...	82—83
2532	आधुनिक पटसन मिलें स्थापित करना	Setting up of Modern Jute Mills ...	83

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
2533	आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी	Power Shortage in Andhra Pradesh	...	83
2534	आंध्र प्रदेश में विद्युत संकट	Power crisis in Andhra Pradesh	...	83—84
2535	आसाम में असमिय माध्यम वाली रेलवे की शिक्षा संस्थाएं	Railway Educational Institutions in Assam with Assamese medium	...	84
2536	एक्सपोर्ट इंसपैक्शन ऐजेंसी स्टाफ एसोशिएसन कोचीन से अभ्यावेदन	Memorandum from Export Inspection Agency Staff Associations, Cochin	...	85
2537	केरल में ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण	Rural Engineering Survey in Kerala	...	85
2538	दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही	Departmental Proceedings against Employees of Southern Railway	...	85—86
2539	चीफ हैल्थ इंस्पैक्टर के पद का दिल्ली से अमृतसर को स्थानांतरण	Transfer of post of Chief Heblth Inspector from Delhi to Amritsar	...	86
2540	स्वास्थ्य मलेरिया निरीक्षकों का एक स्थान पर कार्य करने का कार्यकाल	Tenure of Health/Malaria Inspectors at one station	...	86—87
2541	पावी रेलवे स्टेशन, गुजरात (पश्चिम रेलवे) पर पेय जल की व्यवस्था	Drinking water facility at Pavi Station, Gujarat (Western Railway)	...	87
2542	पावी स्टेशन (पश्चिम रेलवे) में गोदाम का निर्माण	Construction of Warehouse at Pavi Station (Western Railway)	...	87
2543	आंध्र प्रदेश में अनकापल्ली के रव के व्यापारियों द्वारा वैगनों की मांग	Demand for wagons by Jaggery Traders of Anakapalle in Andhra Pradesh	...	87—88
2544	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा अणुशक्ति आयोग को सप्लाई किये गये इंजनों का मूल्य	Cost of DLW engines supplied to Atomic Energy Commission	...	88
2545	केन्द्रीय सरकार की सहायता से बेल्हर के निकट बदुआ नदी पर एक बांध का निर्माण	Construction of a Dam on river Badua near Belhar with Central Assistance	...	88—89
2546	निर्धन जिलों के विकास के लिये सर्वेक्षण	Development survey of Poor Districts	...	89

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	...	89—93
बंगला देश से बड़ी संख्या में बिहारी मुसलमानों को बिहार में आने का समाचार	Reported influx of Bihari Muslims of Bangla Desh into Bihar	...	89—93
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	...	89
श्री कृष्ण चंद्र पंत	Shri K. C. Pant	...	90—93
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	...	94
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	...	95
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक	Bills as passed by Rajya Sabha	...	95
लोक लेखा समिति	Public Accounts Commitee	...	95
32 वां और 33 वां प्रतिवेदन	Thirty-second and Thirty-third Reports	...	95
वैगनों की मामूली मरम्मत न किये जाने के कारण उनको न चलाये जाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 253 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य	Statement correcting answer to S. Q. No. 253 *re.* wagons held up for minor repairs	...	96
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	...	96
अनुदानों की मांगे, 1972-73	Demands for Grants, 1972-73	...	96—125
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	Ministry of Irraigation and Power	...	96—97
श्री विजय मोदक	Shri Bijoy Modak	...	97—103
श्री नरसिंह नारायण पांडे	Shri Narsingh Narain Pandey	...	104—105
श्री के. एम. मधुकर	Shri K. M. Madhukar	...	105
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munsi		105—106
श्री वी. मायावन	Shri V. Mayavan	...	106—107
श्री टी. बालकृष्णैया	Shri T. Balakrishniah	...	107—108
श्री रामरतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	...	108
श्री एन. शिवप्पा	Shri N. Shivappa	...	108—109

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P. M. Mehta ...	109
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	I09—110
श्री रणबहादुरसिंह	Shrí Ranabahadur Singh ...	110—111
श्री रामस्वरूप	Shri Ram Swarup ...	111
श्री पी. के. देव	Shri P. K. Deo ...	112—113
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey ...	113
डा. गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariy ...	114
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha ...	114—115
श्री बैजनाथ कुरील	Shri B. N. Kureel ...	115
श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे	Shri Annasaheb Gotkhinde ...	115—116
श्री गजाधर माझी	Shri Gajadhar Majhi ...	116—117
श्री निहार लास्कर	Shri Nihar Laskar ...	117
श्री वैकारिया	Shri Vekaria ...	118
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga ...	118
श्री बी. बी. नायक	Shri B. V. Naik ...	119
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar ...	119
श्री हुकमचन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai ...	119
श्री के. सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana ...	I20
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda ...	120
डा. के. एल. राव	Dr. K. L. Rao ...	120—125

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 11 अप्रैल, 1972/22 चैत्र, 1894 (शक)
Tuesday, April 11, 1972/Chaitra 22, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met Eleven of the Clock

[**श्री अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in *the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों में साधारण निर्वाचनों के बारे में शिकायतें

+
*341. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन आयुक्त और राज्यों के मुख्य निर्बाचन अधिकारियों को, दिल्ली महा-नगर परिषद् और विधान सभाओं के लिये हाल में हुए साधारण निर्वाचनों और उत्तर प्रदेश में हुये उप निर्वाचनों के बारे में कुल कितनी शिकायते प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) प्राप्त शिकायते किस प्रकार की हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) 1433 शिकायतें निर्वाचन आयोग द्वारा और 546 शिकायतें आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मणिपुर, मैसूर, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों के और दिल्ली, गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई। असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और

कश्मीर, मेघालय, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मांगी गई शिकायतों की विशिष्टियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं और उनकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) एक विवरण जिसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, सदन के पटल पर रख दिया गया है । जहां शिकायतों में विनिर्दिष्ट अभिकथन थे, वहां तुरन्त उचित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्राधिकारियों का ध्यान उनकी ओर दिला दिया गया ।

विवरण

हाल ही में हुए दिल्ली महानगर परिषद् और विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों और उत्तर प्रदेश में उप-निर्वाचनों के सम्बन्ध में शिकायतों के स्वरूप को दर्शाने वाला विवरण ।

शिकायतों का स्वरूप	आयोग द्वारा प्राप्त	मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्राप्त
निर्वाचक नामावलियों में नामों का लोप और मिथ्या नामों का सम्मिलित किया जाना	150	—
निर्वाचनों के ठीक पूर्व अधिकारियों का स्थानान्तरण	38	3
निर्वाचनों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा भाग लेना	270	176
सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग	59	160
निर्वाचन-कार्य में नियोजित सरकारी अधिकारियों का पक्षपातपूर्ण रवैया	36	34
आपत्तिजनक पोस्टरों और पैम्फलेटों आदि का मुद्रण और प्रकाशन	11	—
मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं का अभित्रास और प्रपीडन	70	47
मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण	30	1
सार्वजनिक सभाओं में उपद्रव और विधि और व्यवस्था बनाए रखना	419	66
अन्य प्रकीर्ण स्वरूप की शिकायतें	350	59
	1433	546

श्री ज्योतिमय बसु : यह वक्तव्य घटित बातों का बिल्कुल भी सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता। पश्चिम बंगाल के 280 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में से 200 में धोखाधड़ी और हिंसा का सहारा लिया गया। इस वक्तव्य में इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं हैं। हम आपके समक्ष ऐसे सैंकड़ों मतपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्हें हमने सड़कों तथा अन्य स्थानों जैसे मतदान केन्द्रों तथा चटाई आदि के नीचे से इकट्ठा किया है। मंत्री महोदय ने वक्तव्य में पूरा विवरण नहीं दिया है बल्कि उन्होंने कई प्रश्नों के उत्तर को भी टालने का यत्न किया है। प्रश्न के भाग (ख) में मैंने पूछा था कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है। चूँकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में हिंसा से मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने, मतदान ऐजेंटों को इस आशय के पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना कि सब काम शान्तिपूर्वक हुआ तथा बन्दूक की नाली पर मतदान अधिकारियों को कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने — (ऐसा जम्मू काश्मीर, त्रिपुरा, बंगाल और देश के अन्य भागों में किया गया) — जैसी बातों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को सुनिश्चित करने के बारे में किन उपायों पर विचार कर रहे हैं जिससे देश की जनता को लगे कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : कुछ मामले संयुक्त समिति में पेश किए गए थे जो निर्वाचन विधियों में संशोधन के बारे में विचार कर रही थी। समिति ने इन पर विचार किया है और उसका प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है। आवश्यक बिचार विमर्श उपरान्त एक समुचित विधेयक पेश किया जाएगा।

श्री ज्योतिमय बसु : मंत्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट है कि विद्यमान विधियों में काफी कमियां हैं और शासक दल उनका पूरा पूरा लाभ उठा रहा है। क्या सरकार पिछले चुनावों को ले कर विभिन्न दलों और व्यक्तियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक संसदीय आयोग की स्थापना करेगी यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : सरकार को इस प्रकार के आयोग की स्थापना का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता।

SHRI SHIV KUMAR SHASTRI : Mr. Speaker, Sir, before I ask question from the hon. Minister I wish to apprise you of my difficulty. I had gone to the Notice Office today for consulting the statement attached to this question but the Hindi Vession of the statement was not available. We are experiencing such difficulties in the matter of Hindi, Urdu in your protection. Previously the procedure was that answers to question in Hindi were given in Hindi by the Minister who knew Hindi while now such questions are answered in English only. When a complaint was made to you in this regard you said that instruments are fitted in the House and translated version of the original can be heard both in English and Hindi. Members interested in Hindi version can switch on accordingly but the same can be done in the case of those who want to hear answers in English. So I request you to do something in this regard.

MR. SPEAKER : Let it be postponed to some other occassion.

SHRI SHIV KUMAR SHASTRI : May I know from the hon. Minister whether Government had recieved such complaints, as are mentioned by the hon. Member Shri

Jyotirmoy Bosu regarding irregularities in election, in regard to his party in the previous election too. The new reform introduced by the Election Commission regarding the voting system has rather worsened the situation instead of improving it. Before casting vote one has to sign on counterfile. The secrecy in this way would vanish and no body would be able to come boldly for casting the vote. Is the hon. Minister aware of it ? If so what action is being taken in this regard.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : The hon. Member has complained that he has not received answer in Hindi. This question was raised in English and not in Hindi. That is why the answer has been given in English.

SHRI SHIV KUMAR SHASTRI : I was one among those members who have asked this question and I had put the question in Hindi.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : As to the first part of the question of the hon. Member, we had received such reports about Shri Bosu's party. Signature on counterfile does not affect the secrecy of vote because no one knows its number as it is kept sealed.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The hon. Minister will agree that independent and impartial elections are the basis of democracy. If there are doubts about election in the mind of the people democracy receive a set back. I want to know if anything can be done by way of a writ petition in cases where the polling booths were captured in Bihar. All are agreed that this time a large number of polling booths were raided. The voters were held back and some others were forced to cast their votes. I want to know the remedy for it ?

I have got few ballot papers from Jammu. A polling officer was caught red handed by people while he was affixing rubber stamps on these ballot papers at night. How are you going to deal with such matters ?

MR. SPEAKER : It can be a subject of election petition.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Every thing cannot come under the purview of elcction petition. This is the main difficulty.

MR. SPEAKER : Whatever can be the subject matter of election commission, should not be raised in this House.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : If there are few such complaints they can be challenged through election petitions but as such these irregularities have taken place at a large scale the Government should not have any objection to inquire into. Such complaints are confined to only few areas but as regard those areas from which such complaints have come in does the Government propose to set up an Independent Commission for investigation if no Parliamentary Commission is going to be set up.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : An election petition has bean filed in this regard if it is proved that voters were held back out of fear harrassment the election would be declared void.

As far the question of Jammu is concerned I want to know from where the hon. member has collected these ballot papers we would like to enquire if these are dummy papers or the real ones. No question of setting up a commission arises as the joint committee is siezed of the matter. All the members have expressed their views. The committee report would be published after due consideration.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Mr. Speaker, Sir what has the report to do with it. The report has nothing to do with the results. How can the report set right the irregularities committed during election. The report is concerned with the amendment of law concerning future elections. I am susprised that the hon. Minister wants to wind up the whole matter by taking shelter under the report.

SHRI R. S. PANDEY : I would like to know whether the attention of the hon. Minister has been drawn to the fact that during the election vulgar slogans are raised which create bad impression on the masses and it amounts to charchter assassination.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : We have received such complaints.

MR. SPEAKER : The question is about the number of complaints. It is not a general question on elections.

प्रो० मधु दंडवते : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के प्रति मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के आरोप लगाए गए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि किसी भी राजनैतिक दल के विरुद्ध चाहे बह साम्यवादी हो या कांग्रेस या समाजवादी यदि ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो क्या सरकार इन आरोपों की विस्तृत जांच करायेगी ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मध्यावधि चुनावों के दौरान मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की घटनायें हुई थीं उसके बाद हमने इस सम्बन्ध में समुचित कदम उठाए ताकि ऐसी घटनाए पुनः न हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसके बावजूद भी ऐसी घटनायें पुनः घटी।

श्री ज्योतिमय बसु : इतने गंभीर आरोपों की जांच हेतु एक संसदीय आयोग नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : हाल के चुनावों के बाद कितनी शिकायतें, विशेषकर पश्चिम बंगाल से विभिन्न न्यायालयों में दायर की गईं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में आंकड़े हमें अभी प्राप्त नहीं हुए हैं अतः मैं इस बारे में जानकारी नहीं दे सकता।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Mr. speaker, Sir I had also given a notice on it. You please search your papers. I should also be given a chance to ask a question.

अध्यक्ष महोदय : मैं और प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देता।

लागोस में आयोजित भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी

*342. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या लागोस, नाइजीरिया में हाल ही में एक भारतीत औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी ;

(ख) इस प्रदर्शनी की मुख्य धिशेषतायें क्या थीं; और

(ग) क्या सरकार इस वर्ष में ऐसी प्रदर्शनियां अन्य स्थानों पर आयोजित करने पर भी विचार कर रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। प्रदर्शनी लागोस में 2 मार्च से 22 मार्च, 1972 के दौरान आयोजित की गयी थी।

(ख) इस प्रदर्शनी में भारत की निर्यात क्षमता और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जब तक औद्योगिक क्षेत्र में की गई व्यापक प्रगति पर प्रकाश डाला गया।

(ग) जी हां। 1972-73 के दौरान तंजानिया, उगांडा, सिंगापुर, मलयेशिया, कुवैत और फ़िजी में पूर्णरूपेण भारतीय प्रदर्शनियां आयोजित किये जाने की प्रस्थापना है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : सामान्यत: विदेशों में भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनियां विदेशी मुद्रा कमाने तथा भारतीय वस्तुओं के लिए मंडी ढूंढने के ध्येय से आयोजित की जाती हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि लागोस में आयोजित इस प्रदर्शनी द्वारा हम अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हुए हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : इस प्रदर्शनी के फलस्वरूप तथा उसमें उपस्थित औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न भारतीय फर्मों के प्रतिनिधियों के कारण काफी मात्रा में माल के क्रयादेश मौके पर ही प्राप्त हुए हैं। इन मदों के अन्तर्गत बसें, ट्रक, फायर ट्रक, जीप, डायमेंड रिग्रस, डीज़ल इंजिन, डुपलीकेटर, पब्लिक एड्रस सिस्टम, ट्रांजिस्टर, आटो पार्टस, बिजली का सामान, स्वास्थय सम्बन्धी सामान, दवाईयां, फार्मेक्यूटिक्लज तथा जेवरात, आदि, सम्मिलित हैं। यह आर्डरों वस्तुत: कितने मूल्य के होंगे इसका ठीक २ अनुमान कुछ समय बाद लगाया जा सकेगा। मोटे तौर पर यह 4 करोड़ रुपये के होंगे।

श्री जगन्नाथ मिश्र : यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मंत्रालय 1972-73 के दौरान विदेशों में कई प्रदर्शनियां आयोजित करने जा रहा है। मैं उन देशों के नाम जानना चाहता हूं जो हमारे देश में 1972-73 के दौरान ऐसी ही प्रदर्शनियां आयोजित करेगें ?

श्री ए० सी० जार्ज : इस वर्ष हम तीसरा ऐशियाई मेला आयोजित करेंगे और 41 से अधिक देशों ने मेले में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि उन व्यापारियों तथा उत्पादकों को क्या सुविधाएं प्रदान की जाएगी जो विदेशों में आयोजित होने वाली ऐसी प्रदर्शनियों में भाग लेना चाहते है।

श्री ए० सी० जार्ज : असली निर्यातकर्ताओं और व्यापारियों को यात्रा, बिदेशी मुद्रा की सुविधायें दी जाती है तथा अन्य कई प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते हें।

प्रस्तावित साझी यूरोपीय मुद्रा का भारत पर प्रभाव

*343. **श्री एस. सी. सामन्त** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूरोपीय साझा बाजार के देशों द्वारा एक साझी यूरोपीय मुद्रा चालू करने के बारे में की जा रही कार्यवाही का भारत पर क्या असर पड़ेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : वर्तमान दशक के अन्त तक यूरोपीय साझा बाजार के देशों का एक पूर्ण मुद्रा तथा सीमा शुल्क संघ स्थापित करने की प्रस्थापना पर, नवम्बर 1970 में उनके विदेश तथा वित्त मंत्रियों द्वारा विचार-विमर्श किया गया था । लेकिन अब तक जो सहमति हुई है वह केवल नीतियों में 1973 के अन्त तक कुछ और तालमेल तथा समन्वय करने के सम्बन्ध में ही है, और सदस्य देश मुद्रा संघ की प्रस्थापना के सम्बन्ध में पूरी तरह से वचनबद्ध नहीं हैं और साझी यूरोपीय मुद्रा की स्थापना के लिये तो वे और भी कम वचनबद्ध हैं । तदनुसार, साझी यूरोपीय मुद्रा के आरम्भ होने से हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने का प्रश्न अभी नहीं उठता ।

श्री एस. सी. सामन्त : क्या यूरोपीय साझा बाजार के विधान रूप को देखते हुए हमें ब्रिटेन तथा यूरोप के अन्य देशों के साथ किये जाने वाले अपने व्यापार में किसी प्रकार की तबदीली करनी पड़ेगी ?

श्री ए. सी. जार्ज : मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि पहले यूरोपीय साझा बाजार के 6 देशों ने साझी यूरोपीय मुद्रा की व्यवस्था करने का विचार किया था परन्तु इस सम्बन्ध में हमारी जानकारी यह है कि निकट भविष्य में इसके क्रियान्वित होने की कोई संभावना नजर नहीं आती । सदस्य देशों के आपसी मतभेद कई सम्मेलनों में सामने आ चुके हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस दशक के अन्त तक भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनने की सम्भावना नहीं है ।

श्री एस. सी. सामन्त : क्या भारत अथवा किसी अन्य देश ने यूरोपीय साझा बाजार से कुछ सुविधाएं प्राप्त करने हेतु उनसे सम्पर्क स्थापित किया है ।

श्री ए. सी. जार्ज : भारत ने यूरोपीय साझा बाजार से विभिन्न, सुविधायें प्राप्त करने हेतु उनसे सम्पर्क स्थापित किया है । ताकि हमारे जैसे विकासशील देश को अपनी वस्तुओं का निर्यात करने में सहूलियत हो सके :

डा. रानेन सेन : अवमूल्यन से पूर्व, अमरीकी डालर यूरोपीय देशों की मुद्रा में समानता बनाये हुए था । डालर के अवमूल्यन का यूरोपीय बाजारों और भारतीय मुद्रा पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है क्योंकि भारतीय मुद्रा तो अमरीकी डालर के समान ही है ? अत: मैं इसके बारे में मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ।

श्री ए. सी. जार्ज : डालर के मूल्य में किये गये परिवर्तन का निश्चय ही हमारे व्यापार पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ।

श्री बी. के. दास चौधरी : यूरोपीय साझा बाजार के प्रस्ताव को आरम्भ करने वाले सभी 6 देशों की मूल नीति यही है कि यूरोपीय साझा बाजार के मार्ग में आने वाली सभी बाधायें समाप्त कर दी जायें। इस सन्दर्भ में यह भी पूर्णतया स्पष्ट है कि ऐसा साझा बाजार बनाने के लिए उन्होंने एक विशेष संविधान भी तैयार कर लिया है तथा इस तथ्य के कई प्रमाण सामने आये हैं कि वह साझी यूरोपीय मुद्रा बनाने का प्रयास कर रहे है। अतः इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनके इस वक्तव्य का मूल आधार क्या है कि निकट भविष्य में साझी यूरोपीय मुद्रा के बनने की कोई सम्भाना नहीं है। उन्हें यह जानकारी किस स्त्रोत से प्राप्त हुई है ?

श्री ए. सी. जार्ज : यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 6 सदस्य देशों के अध्यक्षों का 1967 में एक शिखर सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में लगजनवर्ग के वित्त मंत्री, श्री पियरे वरनर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। आयोग ने 25-9-70 को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया था और 13-10-70 को उस पर चर्चा की गई थी। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ओर फ्रांस तथा दुसरी ओर जर्मनी और हालैण्ड का आपस में तीव्र मतभेद हो गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : डालर के अवमूल्यन ने परीक्षा रुप से भारतीय रुपये का लगभग $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत अवमूल्यांन कर दिया है। क्या यह सत्य नही है कि यदि साझी यूरोपीय मुद्रा चालू की जाती है तो उससे रुपये का लगभग साढ़े चार प्रतिशत अावमूल्यन हो जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के अनुभामात्मक प्रश्न मत पूछिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह तो पहले ही हो चुका है। डालर अवमूल्यन के कारण भारतीय रुपये का अवमूल्यन तो पहले ही किया जा चुका है। अमरीकी डालर से जुड़े रहने की इनकी नीति ही गलत रही है। मुझे खेद है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा।

उत्तर कोरिया के साथ व्यापारिक समझौता

*345. **श्री पी० गंगादेव** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोरिया के व्यापार दल ने व्यापार वार्ता के उद्देश्य से हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) क्या उस दल के साथ वर्ष 1972 के लिए किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मेंमंत्रालय उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत तथा कोरिया लोकतन्त्रीय जनवादी गणराज्य के प्रतिनिधिमंडलों के बीच व्यापार वार्ताएं 7 और 21 फरवरी, 1972 के बीच नई दिल्ली में हुई। इन विचार विमर्शों के दौरान दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति हुई कि 1972 में व्यापार स्तर में और वृद्धि की जानी चाहिये। कोरिया, लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य से आयात की जाने वाली मुद्रा में, मैगनेसिया विलकर, मूल रिफ्रेक्टरी, एन्थ्रासाइट, ग्रेफाइट, फ्लुओरस्पार, होप्स, पिपरमिंट तेल, हाई स्पीड टूल स्टील, कार्बन टूल स्टील, स्टेनलैस स्टील आदि सहित विशेष इस्पात शामिल हैं। भारत से कोरिया लोकतन्त्रीय जनवादी गणराज्य को निर्यात की जानी वाली वस्तुओं में कच्चा लोहा, मैंगनीज अयस्क, सवारी डिब्बे, आटो बसें, टायर तथा ट्यूबें, विभिन्न रासायानिक पदार्थ, पटसन से बना सामान, कागज से बने उत्पाद, सूती वस्त्र, रेयन वस्त्र तथा बालवेयरिंग, तार के रस्से सहित विभिन्न इंजीनियरी माल आदि शामिल हैं।

श्री पी० गंगादेव : क्या इन दोनों देशों के बीच दो तरफा व्यापार में सराहनीय वृद्धि हुई है और इस व्यापार करार के अन्तर्गत कौन कौन सी मदें आती है ?

श्री ए० सी जार्ज : इस समझौते के अन्तर्गत उत्तरी कोरिया से आयात की जाने वाली मुख्य मदें हैं : मशीन टूल, स्पैशल स्टील, मूल रिफ्रेक्टरी, मैगनेसिया, क्लिकर, ग्रेफाइट पिपरमिंट तेल आदि। इसी प्रकार भारत से कोरिया को टायर तथा ट्यूब, कच्चा लोहा, सूती वस्त्र, सवारी डिब्बे, आटो वसें, विभिन्न रसायनिक पदार्थ और मैगनीज आदि का निर्यात किया जायेगा।

श्री पी० गंगादेव : क्या प्राइवेट निर्यात कर्त्ताओं को उत्तरी कोरिया के साथ व्यापार करने की अनुमति है और यदि नहीं, तो क्या वर्तमान व्यापार करार के अन्तर्गत उन्हें ऐसा करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ए० सी० जार्ज : इस समय सम्पूर्ण निर्यात राज्य व्यापार नियम द्वारा नहीं किया जाता परन्तु राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्रत्येक वस्तु को निर्यात करने की सरकार की नीति है।

उड़ीसा में कटक और पारादीप के बीच रेलवें लाइन

*346. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में **कटक और पारादीप** के बीच रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में कहां तक प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह लाइन कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) फरवरी, 1972 के अन्त तक उस लाइन के निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 48 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) पिछले वर्ष तूफान के कारण जिससे उड़ीसा तहस-नहस हो गया था और सिचाई-नहर के पानी को रोक सकने में राज्य सरकार की असमर्थता के कारण जिससे कुछ क्षेत्रों में निर्माण कार्य की प्रगति में बाधा पड़ी है, उप लाइन के निर्माण कार्य को धक्का लगा।

श्री अर्जुन सेठी : इस ब्रांच लाइन के निर्माण कार्य में जो बिलम्ब हुआ है, उसे दृष्टिगत रखते हुये मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई विशेष कदम उडाये गये हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : निर्धारित तिथि में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब यह लक्ष्य 1973 निर्धारित किया गया है। हमें आशा है कि जून 1973 तक हम इस परियोजना को पूरा करने में सफल हो जायेंगे ?

श्री अर्जुन सेठी : इसे यातायात के लिए कबतक खोल दिया जायेगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इसको पूरा होने के शीघ्र बाद ही इसे यातायात के लिए खोल दिया जायेगा।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Mr. Speaker, Sir, the construction of such railway lines somehow continues for a long time which results in huge expenditure. May I know if Government is formulating a scheme under which construction work is completed in time and that if may not involve much expenditure ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : Every effort is made to finish the work in time but we become helpless against a natural calamity such as Cyclone in Orissa, otherwise we are always seen to complete the work in time.

भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण

*347. **श्री निहार लास्कर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 के दौरान रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण की योजनाओं की मोटी रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

1973-73 के दौरान रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिये परियोजनाओं की मोटी रूप रेखा इस प्रकार :—

विद्युतीकरण परियोजना का नाम	मार्ग कि० मी०	रेल पथ कि० मी०	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
1. विरार-साबरमती	437	1130	32.06 रु०
	इससे बम्बई और अहमदाबाद बिजली कर्षण से सम्बद्ध हो जायेगी ।		
2. पांशकुड़ा-हल्दिया	69	114	2.40 रु०
	यह हल्दिया बन्दरगाह के यातायात को सम्हालने के लिऐ है ।		
3. किरंदुल-बाल्लेरू	471	620	19.05 रु०
	यह लोड अयस्क के निर्यात के लिये वेलाडिला क्षेत्र से विशाखापतनम् बन्दरगाह तक लोह अयस्क के संचलन के लिए है।		
4. टुंडला-दिल्ली	269	730	19.72 रु०
	इससे ग्रांड कार्ड, इलाहाबाद और अलीगढ़ के रास्ते हावड़ा से दिल्ली तक के ट्रंक मार्ग के विद्युतीकरण का काम पूरा हो जायेगा ।		
5. मद्रास-विजयवाड़ा	433	1125	31.03 रु०
	मद्रास-हावड़ा और मद्रास दिल्ली ट्रंक मार्ग का भाग है ।		
	1679	3719	

आशा की जाती है कि अहमदाबाद-बड़ोदा खण्ड, जो विरार-साबरमती बिजली योजना का एक भाग है और कुल 437 में से 102 मार्ग कि० मी० लम्बा है, का 1972-73 में विद्युतीकरण हो जायेगा ।

श्री निहार लास्कर : मेरे विचार से विवरण में बतायी गयी परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है । यदि ऐसा है तो क्या वर्ष 1972-73 के दौरान किसी परियोजना के पूरा होने की संभावना है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इन सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है । यद्यपि 1972-73 के दौरान कुछ कार्य किया जायेगा फिर भी इनमें से कोई परियोजना पूरी नहीं होगी ।

श्री निहार लास्कर : दिल्ली-टूंडला लाइन के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वर्ष 1975-76 तक इस लाइन का कार्य पूरा हो जायेगा ।

श्री निहार लास्कर : क्या कलकत्ता-बम्बई तथा बबम्बई-दिल्ली जैसे मुख्य मार्गों को विद्युत चालित रेलगाड़ियों से जोड़ने की कोई योजना है ?

श्री मुहम्मद कुरेशी : इस समय ऐसी कोई योजना नहीं ?

श्री नवल किशोर सिंह : पटना होते हुए हावड़ा-दिल्ली मार्ग की निकट भविष्य में बिद्युतीकरण अथवा डीजलीकरण करने में मंत्रालय के सम्मुख क्या कठिनाई है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : आर्थिक सुविधा की दृष्टि से हमने हावड़ा-दिल्ली लाईन पर यह कार्य आरम्भ किया परन्तु यह लाईन बारास्ता पटना नहीं जाती है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मद्रास से आरकोनम रेल मार्ग पर विद्युत चालित रेल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव था। यह मांग बहुत दिनों से अनिर्णीत पड़ी है। क्या बर्ष 1972-73 के कार्यक्रम में इस मार्ग को भी सम्मिलित किया जायेगा और यदि नहीं, तो इस मार्ग पर विद्युतीकरण का कार्य कब आरम्भ होगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस समय मद्रास-विजयवाड़ा सैक्शन को सम्मिलित किया गया है। इस कार्य में लगभग 31 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। माननीय सदस्य ने जिस मार्ग के विषय में कहा है इस समय उसका कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : यदि यह कार्य 1972-73 में आरम्भ नहीं किया जायेगा तो इसे कब आरम्भ करने का विचार है। मंत्री महोदय ने सदन में आश्वासन दिया है कि यह कार्य किया जायेगा। यह मांग बहुत पहले की गई थी।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : विद्युतीकरण का कार्य निरन्तर चलने वाला है। जब विनीय संसाधन तथा उस क्षेत्र की आर्थिक सुलभता विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये उपयुक्त होगी तो इस पर निश्चय ही विचार किया जायेगा।

श्री के० सूर्यनारायण : मद्रास-विजयवाड़ा सैक्शन का कार्य निष्पत्ति सम्बन्धी कार्यालय मद्रास में है तथा कार्य की शीघ्र निष्पक्षता के उद्देश्य से संसद सदस्यों ने सरकार से कहा है कि यह कार्यालय विजयवाड़ा में होना चाहिये। क्या सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है अथवा नहीं; क्या मद्रास-विजयवाड़ा सैक्शन का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिये इस कार्यालय को विजयवाड़ा, जो मद्रास-हावड़ा लाईन के मध्य में स्थित है, में स्थापित करने के सम्बन्ध में संसद सदस्यों के प्रस्ताव से सरकार सहमत हो गई है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : कार्य की शीघ्र पूर्ति के विचार को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय अब विजयवाड़ा में स्थापित किया जाया ला रहा है।

श्री ए० पी० शर्मा : क्या हावड़ा-दिल्ली मुख्य मार्ग के पूरा हो जाने पर मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियों के आने-जाने के समय में कोई कमी आयेगी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जी हां, आने-जाने का समय कम हो जायेगा ।

फरक्का बांध के कारण गंगा के वहाव में रुकावट पड़ना

*348. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के कारण गंगा नदी के बहाव में रुकावट पड़ती है जिसके परिणाम-स्वरूप बिहार के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समस्या का विस्तृत अध्ययन करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) और (ख). फरक्का बराज केवल एक व्यपवर्तन संरचना है । बाढ़ों के दौरान इसके सभी कपाट खोल दिये जाते हैं, इसलिए इससे बहाव में रुकावट नहीं पड़ती ।

श्री एन० ई० होरो : फरक्का बांध गंगा नदी पर बहुत नीचे बनाया गया है और इसमें निर्माण सम्बन्धी दोष भी प्रतीत होते हैं । जिससे बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है । अतः क्या मंत्री महोदय केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग से इसकी जांच करायेंगे जिससे बाढ़ों को रोका जा सके ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : जैसा कि मेरे सहयोगी श्री बी० एन० कुरील ने बताया हैं कि फरक्का बांध से किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती है और बिहार तथा बंगाल में इसके कारण बाढ़ नहीं आती हैं । इसकी कार्य संचालन गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत कर दिया जाएगा जिसका गठन शीघ्र ही किया जाना है ।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या बिहार राज्य सरकार के कृषि मंत्रालय ने केन्द्रीय कृषि मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर दिलाया हैं कि बिहार में यह धारणा बन रही है कि फरक्का बांध के बनने के कारण ही बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है ।

डा के० एल० राव : जी हां, बिहार के कृषि मंत्री ने मौखिक रूप में मुझसे यह बात कही हैं परन्तु किसी तथ्य पर आधारित नहीं है । वास्तव में फरक्का बांध से किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है । गत वर्ष भी जब फरक्का पर गंगा में भारी बाढ़ आई थी, लगभग 25 लाख क्यूसेक्स जल नीचे बह रहा था, तब ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर बहने वाली धाराओं की सतत में केवल तीन इंच का अन्तर था । अतः यह कहना कि फरक्का बांध के कारण बिहार में बाढ़ आती हैं, तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय ने अपने को इस बात से संतुष्ट कर लिया है कि फरक्का वांध पर गंगा नदी के जल का किसी प्रकार भी वयपर्वतन नहीं किया जायेगा जिससे 40,000 क्यूसेक्स पानी हुगली नदी में डालने की मूल योजना पर दुष्प्रभाव न पड़े तथा कलकत्ता पतन को हानि से बचाया जा सके ?

डा० के० एल० राव : फरक्का बांध के सम्बन्ध में पानी के बहाव की योजना को प्रभावित करने वाला पानी का कोई व्यपवर्तन नहीं किया जाएगा। कुछ महीनों में वहाव तेज होता है तथा कुछ में धीमा। इसे स्वीकृत परियोजना का रूप दिया जा रहा हैं और परियोजना का कार्यसंचालन स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार चलायेगा।

SHRI SHANKAR DYAL SINGH : May I know from the Home Minister whether the Farakka Barrage is one of the reasons of the unexpected flood in Bihar last year ?

डा० के० एल० राव : मैं बता चुका हूं कि नदी में बाढ़ आने से इस बांध का कोई सम्बन्ध नहीं है। बाढ़ के पानी में वृद्धि से भी इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा० रनेन सेन : क्या मंत्री महोदय को पता है कि जल भौतिकीविद्ध अर्थात नदी के जल से सिंचाई में बाढ़ तथा अन्य बातों में दक्षता प्राप्त व्यक्तियों का यह मत है क्यों कि घाघर तथा अन्य बांधों का निर्माण गंगा के ऊपरी भाग की ओर हुआ है इस लिए फरक्का बांध के निकट पानी की इतनी कमी हो जाती है कि हुगली नदी को पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता और पूर्वी बंगाल की नदियां पानी की कमी के कारण सूख जाती हैं।

डा० के० एल० राव : यह ठीक नहीं हैं। किसी भी बांध के निर्माण से पानी की इतनी कमी नहीं होती है जिसका प्रभाग फरक्का बांध परियोजना पर पड़ सके। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह प्रश्न में बंगला देश को न लायें। यह एक पृथक देश है और हमें पृथक ढंग से उसके साथ व्यवहार करना है।

श्री ज्योतिमय बसु : मन्त्री महोदय ने अभी बताया हैं कि वर्ष के सभी महीनों में 40,000 क्यूसेक्स पानी की सप्लाई नहीं की जा सकती। क्या मन्त्री महोदय वतायेंगे कि कम से कम कितने पानी की सप्लाई की जा सकती है और किन किन महीनों में पानी का बहाव धीमा हो जाता है ?

डा० के० एल० राव : जैसा कि मैंने बताया है, फरक्का बांध का कार्य संचालन स्वीकृत परियोजना के रूप में होगा। जब परियोजना स्वीकृत की जाती है तो प्रत्येक महीने के लिए जल बहाव की एक मात्रा निर्धारित की जाती है। यह कार्य संचालन कार्यक्रम होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वर्ष में बहुत से महीनों में 40,000 क्यूसेक्स पानी नीचे बहेगा केवल कुछ महीनों में यह बहाव कम हो जाता है। इसके लिए भी कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। यह 40,000 क्यूसेक्स से भिन्न होता है परन्तु कार्य संचालन निश्चित कार्यक्रमानुसार ही होता है।

जल सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति बनाना

*349. **श्री अण्णा साहिब गोटखिडे** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय एक राष्ट्रीय जल नीति प्रतिपादित करने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) कृषि और आर्थिक विकास में जल के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए बेसिन राज्यों द्वारा मौजूदा सीमित उपयोग की अवधारणा के स्थान पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संस्थानों के आयोजन और विकास की आवश्यकता को अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है । नए दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं का, जिनमें कानूनी पहलू भी सम्मिलित हैं, अध्ययन किया जा रहा है ।

श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे : क्या सरकार जल को राष्ट्रीय संसाधन मानेगी किसी एक राज्य विशेष का नहीं और इस पर राष्ट्रीय नियंत्रण रखने के ढंग से कार्यवाही करेगी ? दूसरे जब तक अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 कानून के रूप में उपलब्ध है सरकार, स्थानीय छोटे छोटे विवादों को सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायाधिकरण में ले जाने से किस प्रकार रोक सकेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : बात वास्तव में यही है । इस समय एक राष्ट्रीय जल नीति शुरु करने का विचार है क्योंकि पानी की इस देश में ही नहीं अपितु विश्व पर्यन्त अत्याधिक कमी होती जा रही है । अतः देश के हित में पानी के प्रयोग को विनियमित करना बहुत आवश्यक हो गया है । अब हम, सम्बद्ध व्यक्तियों से परामर्श करके तथा अध्ययन कार्य करके, राष्ट्र के लिए एक जल सम्बन्धी नीति बनाने का विचार कर रहे हैं ।

श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे : कानून के रूप में उपलब्ध अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम से सम्बन्वित प्रश्न के भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । (**व्यवधान**)

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय जल प्रबन्ध तथा जल विकास के क्षेत्र से सम्बन्धित सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे ?

डा० के० एल० राव : जब हम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा करेंगे कि जल राष्ट्र की सम्पत्ति है तो उसके परिणाम स्वरुप अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में संशोधन हो जायेगा ।

जहां तक मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सारी स्थिति स्पष्ट करने में सदन को बहुत समय लगेगा । मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । मुख्य मार्ग दर्शी सिद्धांत यह होगा कि देश के विभिन्न भागों में पानी सप्लाई का प्रयत्न किया जायेगा चाहे उस भाग में नदी बहती हो या न बहती हो ।

दूसरे, प्राथमिकता के आधार पर पानी के विविध प्रयोग तथा जल-दूषण रोकने के उपाय प्रतिपादित किये जायेंगे ।

श्री पी० वेंकटासुब्बाया : राष्ट्रीय जल नीति को कार्यरूप देने के उद्देश्य से क्या सरकार का विचार मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का है जिससे क्षेत्रीय अथवा ग्राम्य स्तर तक सीमित न रहकर जब राष्ट्रीय स्तर पर पानी का प्रयोग किया जाये और इस मार्ग में कठिनायां आयें तो उनको सुलझाया जा सके ।

डा० के० एल० राव : क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है अतः उनसे तो परामर्श किया ही जाना है ।

श्री एम० सत्यानारायण राव : क्या गंगा को कावेरी से मिलाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी और यह कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के लिए अलग से नोटिस दिया जा सकता है । माननीय सदस्य को प्रश्न के विषय तक ही सीमित रहने का प्रयत्न करना चाहिए ।

अगला प्रशन ।

गुजरात को कोयला भेजना

*450. **श्री प्रवन्न भाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्यपाल ने उन्हें एक तार भेजकर, राज्य को कोयला भेजने में तेजी लाने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

जून, 1971 से अब तक गुजरात के राजपाल की ओर से रेल मंत्री के नाम 2 पत्र और 3 तार प्राप्त हुए हैं जिनमें गुजरात में उद्योगों को कोयले के संचलन के सम्बन्ध में कठिनाई होने का उल्लेख है । इन पत्रों के प्राप्त होने पर गुजरात के लिए अधिक कोयले का लदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई थी ।

2. 1971-72 में गुजरात में उद्योगों को कोयले के संचलन मे सुधार हुआ और नम्बर 1971 से फरवरी, 1972 तक की अवधि में तो स्थिति और भी सुधर गयी क्योंकि इस अवधि में तो पिछले दो वर्षों की तदनुरुपी अवधि की तुलना में भी कोयले का संचलन अधिक रहा । कपड़ा मिलों और ओटन उद्योगों के लिये भी पिछले दो वर्षों की तदनुरुपी अवधि की तुलना में अधिक कोयला भेजा गया ।

3. यद्यपि इस वर्ष लदान का स्तर अधिक रहा तथापि मांग के पालन किये जाने का प्रतिशत कम रहा क्योंकि प्रयोजित मांगों में अकस्मात् अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। इस मामले में सम्बन्धित प्रायोजन अधिकारियों से बातचीत की गई है और उनसे कहा गया है कि वे अपने प्रायोजन को उद्योगों की न्यूनतम वास्तविक मांगों के अनुसार ही सीमित रखें।

4. लदान में और वृद्धि करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री पी. एम. मेहता : वक्तव्य के अनुसार गुजरात के राज्यपाल ने गुजरात में उद्योगों के समक्ष कोयले की कमी के कारण उत्पन्न कठिनाईयों के बारे में एक तार नहीं अपितु तीन तारें और दो पत्र लिखे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जनवरी 1972 से मार्च 1972 के तीन महीनों में कुल कितने कोयला वैगनों की आवश्यकता थी और उनकी सप्लाई में कितने प्रतिशत कमी रही ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वास्तव में वर्ष 1971-72 में लदान 1970-71 की अपेक्षा कहीं ज्यादा हुआ। किन्तु बहुत बढ़ा-चढ़ाकर रखी गई मांगों ने हमें कठिनाइयों में डाल दिया। वर्ष 1969-70 में गुजरात के उद्योगों के लिये कुल 22,016 बैगन कोयले की मांग थी। यह अब बढ़कर 40,628 बैगन हो गई है जबकि उद्योगों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कोयले की खपत बहुत अधिक दिखाई गई है। इस मामले पर गुजरात सरकार के साथ बिचार-विमर्श किया गया है। और समूचे मामले की जांच की जा रही है जिससे रेलवे से वहुत बढ़ा-चढ़ाकर वैगनों की मांग न की जा सके। इस बात के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहें हैं कि गुजरात राज्य की मांगों की पूर्ति की जा सके।

श्री पी. एम. मेहता : मेरा प्रश्न था कि जनवरी से मार्च 1972 तक कुल कितनी मांग थी और उसकी पूर्ति में कितने प्रतिशत कमी रही ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वर्ष 1970-71 में वैगनों का प्रतिमास औसत लदान 7339 था जो कि वर्ष 1971-72 में बढ़कर 8139 हो गया था। माननीय सदस्य को इसे तीन से गुणा करने पर तीन महीनों के आंकड़े प्राप्त हो जायेंगे ?

श्री पी. एम. मेहता : मैं गुणा नहीं करना चाहता। मैं केवल तीन महीनों के लिए मांग के आंकड़े तथा मांग की पूर्ति में कमी का प्रतिशत जानना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वर्षवार आंकड़े दे दिये हैं।

श्री पी. एम. मेहता : आवश्यकताओं की तुलना में कमी की प्रतिशतता क्या है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हू। प्रश्न यह है कि समर्थन गुजरात सरकार द्वारा कितनी मांग रखी जाती है। बैगनों की कमी के कारण वैगनों की मांग

बहुत बढ़ा दी गई है। हां, गुजरात सरकार ने जितनी मांगें रखी, उन्हें हम पूरा नहीं कर पाए। किन्तु हमने उन्हें 1970-71 की तुलना में वर्ष 1971-72 में अधिक वैगनों का आवंटन किया और अधिक कोयला दिया।

श्री पी. एम. मेहता : मेरे पहले प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया गया है। तो भी मैं दूसरा प्रश्न करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे व्यवहार को पसन्द नहीं करता। पहले आप सुनते रहते हैं और बाद में पहले प्रश्न में सुधार करके दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं।

श्री पी. एम. मेहता : मैं पहले प्रश्न को नहीं छेड़ूंगा।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे अधिकारियों को पता है कि वस्त्र उद्योग, विद्युत गृह और मध्यम दर्जे के तथा लघु उद्योगों में कोयले की भारी कमी है और इसके कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें केवल वैगन सप्लाई करने हैं।

श्री पी. एम. मेहता : इस परिस्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : एक बैठक में गुजरात सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि वैगनों की मांगे बहुत बढ़ा-चढ़ा कर की जाती है। अब गुजरात के वस्त्र-उद्योग की यथोचित मांगों की पूर्ति की कोशिश की जा रही है।

श्री पी. एम. मेहता : बिजली घरों के बारे में क्या स्थिति है।

श्री मुहम्मद कुरेशी : बिजली घरों के बारे में ?

श्री के. एस. चावड़ा : क्या यह सच है कि कुछ मामलों में आवंटन आदेश दे दिये गये किन्तु वैगन उपलब्ध नहीं थे। और जब वैगन उपलब्ध थे, तब आवंटन आदेश नहीं दिये गये। यदि हां, तो सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह सच नहीं है।

श्री महाराजसिंह : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कोयला खानों में कोयले के भारी स्टाक है और वे वैगनों के अभाव में उसकी कारखानों में ही खपत करते हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : उनके यहां पहले 90 लाख टन कोयला था जो अब घटकर 70 लाख टन रह गया है। साधारण तौर पर इतना स्टाक कोयला खानों के पास रहता ही है।

हिमाचल प्रदेश में स्योल परियोजना पर खर्च की गई धन-राशी

*351. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1972 तक हिमाचल प्रदेश की स्योल परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसमें से प्रशासन कार्य पर कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(ख) उक्त परियोजना की कुल लागत कितनी है ; और

(ग) परियोजना कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं ।

विवरण

(क) मार्च, 1972 तक बैरा-सियुल जल-विद्युत परियोजना पर लगभग 6.81 करोड़ रुपये खर्च हो गए होंगे । इसमें से प्रशासन पर किया गया व्यय लगभग 0.13 करोड़ रुपये है ।

(ख) परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 40.59 करोड़ रुपये है ।

(ग) भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है । बांध-स्थल निर्धारित करने के लिए आवश्यक अन्वेषणात्मक कार्य किया जा चुका है । परियोजना स्थल को जाने वाली सड़क पूर्ण हो चुकी है। निर्माण-पूर्व सर्वेक्षण चल रहे है । विद्युत-घर आवास कालोनी (लगभग 50 रिहायशी क्वार्टर) पूर्ण हो चुकी है । निर्माण-विद्युत के लिए प्रबन्ध पूर्ण हो चुके हैं । सुरंग, पेन-स्टाकों आदि के लिए ठेके दिए जा चुके हैं । विद्युत घर के निर्माण और पेन स्टाकों के लिए सिविल निर्माण-कार्यों के लिए निविदाएं प्राप्त हो गई हैं । सर्ज शाफ्ट के अंतिम छोर के निकट सुरंग के मुख-भाग की खुदाई शुरु की जा चुकी है । विद्युत-जनन यूनिटों के लिए मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स इंडिया लिमिटेड, हरिद्वार को आर्डर दे दिए गए हैं ।

प्रथम यूनिट के जनवरी, 1975 में चालू हो जाने की आशा है ।

श्री विक्रम महाजन : मेरा प्रश्न यह था कि फरवरी 1972 तक हिमाचल प्रदेश की स्योल परियोजना पर कितनी धन राशि खर्च हुई और उसमें से प्रशासन-कार्य पर कितनी धनराशि खर्च हुई ? उत्तर दिया गया है कि लगभग 6.81 करोड़ रुपये खर्च हो गये होंगे ।

मेरा निवेदन है कि उत्तर में जान बूझ कर ठीक जानकारी नहीं दी गयी है क्योंकि वे इस वर्ष के लिये निर्धारित धन राशि को खर्च नहीं कर पाए है । प्रशासन द्वारा जानबूझ कर ऐसा किया गया है जिससे कि वे अधिक समय तक वहां कार्य करते रहें और कई अन्य परियोजनाओं के समान इसमें भी विलम्ब किया जा रहा है ।

इसलिये, इस समय को मेरे अनुपूरक प्रश्न पूछने के समय में न गिना जाये, क्योंकि मैं केवल उस जानकारी के लिये यह प्रश्न कर रहा हूं जो उन्होंने दी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इस परियोजना पर अब तक वास्तव में कितना खर्च किया गया है ? मैं यह नहीं सुनना चाहता कि कितना धन व्यय कर दिया जाना चाहिए था।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मेरे विचार से माननीय सदस्य साधारण से प्रश्न को बहुत अधिक जटिल बना रहे है ; मामला यह है कि मार्च के अंत तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। इनमें से कुछ उपलब्ध नहीं थे। वे महालेखापाल से आते थे। अतः 6.8 करोड़ रुपये के अनुमानित आकड़ें दिये गये।

यह स्पष्ट उत्तर है। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि यह परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो जाये। इसके लिए हमने जनवरी, 1975 की तिथि निर्धारित है।

श्री विक्रम महाजन : उन्होंने प्रशासन पर व्यय की गई धनराशि के सही आंकड़े दिये हैं। परन्तु विकास परियोजना पर कितना धन व्यय हुआ है, यह नहीं बताया गया। मैंने यह पूछा था कि परियोजना पर कितना कार्य हुआ है। उन्होंने बताया कि परियोजना-स्थल पर सड़के तैयार हो गई हैं। मेरी जानकारी यह है कि वहां पर कोई भी पुल अथवा सड़क ऐसी नहीं बनी, जिन पर से भारी मशीने गुजर सकें।

डा के. एल. राव : माननीय सदस्य के पास बहुत सी जानकारी है, किन्तु वह गलत है। सड़क हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से बनायी गई है। फिर भी, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यह परियोजना जनवरी, 1975 तक पूरी हो जायेगी।

श्री विक्रम महाजन : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। यदि मैं आपको अधिक समय देता हूं तो अन्य सदस्यों को भी उतना ही समय देना पड़ेगा। वैसे तो आप अनेक प्रश्न पूछ सकते हैं परन्तु इसमें समय की कठिनाई हैं।

Trunk Route Allowance to Permanent Way Staff on Indian Railways

*352. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether work-load on trunk routes is much more than on the main lines and branch lines in Permanent Way Department on Indian Railways ;

(b) whether the Permanent Way staff on trunk routes is not being paid remuneration according to the work-load ; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी क़ुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : May I know whether keeping in view that they have to put longer hours of work and a large number of trains passes through these routes, Government is considering to give any aditional facility to the employees there ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : The workers are posted on trunk, main and branch lines under a phased programme and it is so arranged that no body may feel over burdened.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सभी रेलपथ कर्मचारियों के सम्बध में ठीक है अथवा केवल निरीक्षकों के सम्बन्ध में ?

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : There is a great difference in the responsibility and work load of the employees working on banch line and main or trunk routes. So, keeping this in view does government not consider it necessary to give them some more facilities ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह एक सुझाव है ?

रबड़ का बाजार ढूंढ़ने हेतु केरल सरकार की सहायता

*354. श्री **एम. एस. जौसफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने अपनी ऐजेंसियों द्वारा एकत्र किये गये **रबड़** की बिक्री के लिए बाजार ढूढने में राज्य व्यापार निगम की सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आवश्यक सहायता देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केरल राज्य सरकार ने राज्य व्यापार निगम से अनुरोध किया कि विनिर्माताओं द्वारा जो क्रयादेश राज्य व्यापार निगम को दिये गये है। उनमें से कुछ केरल राज्य सहकारी विपणन परिसंघ को दिये जाएं अथवा परिसंघ के पास से रबड़ स्टाक को उठाया जाये। तदनुसार, राज्य व्यापार निगम ने मद्रास स्थित अपने शाखा कार्यालय को यह अनुदेश जारी कर दिया है कि वे राज्य सरकार अभिकरण द्वारा अब तक प्राप्त की गई कच्ची रबड़ की मात्रा तथा ग्रेड का पता लगाएं और टायर तथा गैर टायर विनिर्माताओं को इन स्टाकों के देने में आवश्यक सहायता दें।

श्री एम० एम० जोसफ : कितनी राशि स्वीकृत की गयी है और उसमें से केरल सरकार को कितनी दी जा चुकी है ?

श्री ए० सी० जार्ज : गत अक्तूबर में जब रबड़ बाजार में बहुत सा माल इकट्ठा हो गया था, तो केरल सरकार ने रबड़ को स्वयं खरीदने के लिए केन्द्रीय सरकार से आसान शर्तों पर ऋण मांगा था। केन्द्रीय सरकार ने 2.5 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया; जिस से पचास-पचास लाख रुपये की दो किस्तें अब तक उसे दी जा चुकी हैं।

श्री एम० एम० जोजफ : क्या मूल्य में कुछ ठोस वृद्धि हुई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : केरल सरकार के द्वारा खरीद शुरू किये जाने का बड़ा ही हितकर प्रभाव पड़ा है और हमारी जानकारी यह है कि कीमतें लगभग स्थायी स्तर पर आ रही हैं।

श्री वयालार रवि : क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से शेष राशि देने का भी अनुरोध किया है ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम उन्हें 1 करोड़ रुपया दे चुके हैं और केरल सरकार ने अब तक 627 मीट्रिक टन रबड़ खरीदा है जिस पर 37 लाख रुपया खर्च हुआ है। अतः उनके पास अभी भी 63 लाख रुपया शेष है और इसके समाप्त होने पर ही वे अगली किस्त के लिए केन्द्र से अनुरोध कर सकते हैं।

श्रीलंका को रेलवे बैंगनों की सप्लाई

*355. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका को रेलवे बैंगनों की सप्लाई करने के संबंध में श्रीलंका के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो श्रीलंका को कितने तथा किस प्रकार वैगन सप्लाई किये जायेंगे;

(ग) ये बगन कब तक सप्लाई कर दिये जायेंगे; और

(घ) क्या भुगतान भारतीय रुपयों में होगा अथवा विदेशी मुद्रा में ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). श्रीलंका सरकार की रेलवेज़ के महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मार्च, 1972 में भारत आया था। इसने 6 से 7 किस्मों के सवारी डिब्बे खरीदने में रुचि दिखाई थी। तथापि, अभी तक कोई पक्का क्रयादेश नहीं दिया गया है।

श्री नवल किशोर शर्मा : इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने माल डिब्बों के निर्यात और उनसे अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। क्या इस योजना का अन्त तक यह लक्ष्य पूरा हो जायेगा।

श्री ए० सी० जार्ज : माल डिब्बों से हमारी विदेशी मुद्रा की आय बढ़ रही है और जनवरी 1971-72 तक यह आय 6 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। इस वर्ष हमें एक निर्यात हेतु एक बड़ा क्रयादेश मिला है तथा परियोजना और उपकरण निगम को यूगोस्लाविया से 36 करोड़ रुपये के मूल्य के 36000 माल डिब्बों के लिए क्रयादेश मिला है। हमें आशा है कि 1972-73 में माल डिब्बों के निर्यात से हमें 68 करोड़ रुपये और 1973-74 में लगभग 84 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होने लगेगी।

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या रूस के साथ होने वाला मालडिब्बों का बहुचर्चित करार सम्पन्न होने जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न श्रीलंका से सम्बन्धित था और माननीय सदस्य रूस के बारे में पूछ रहे हैं अब प्रश्न काल समाप्त हो गया हैं।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

स्टेशन मास्टरों की काम की दशा में सुधार

*344. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ द्वारा पारित संकल्प के बारे में 9 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 483 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें दिये गए आश्वासनों को इस बीच पूरा कर दिया गया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या स्टेशन मास्टरों का मामला वेतन आयोग के समक्ष रखा गया है और यदि हां, तो मोटे तौर पर उसकी रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें 9 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न सं० 483 के उत्तर में दिये गये आश्वसनों की वर्तमान स्थिति दिखायी गयी है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी.** 1709/72]

(ख) वेतन आयोग स्टेशन मास्टरों सहित सरकारी कर्मचारियों की सभी कोटियों के मामले की जांच कर रहा है।

———

वेगन बनाने वालों को आयातित इस्पात की सप्लाई

*353. **श्री बक्शी नायक** : क्या **विदेश** व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वेगन निर्माताओं को निर्यात के लिये वेगन बनाने हेतु आयातित इस्पात सप्लाई किया जा रहा है और, यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितना इस्पात आयात किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): इस्पात की सामान्य कमी को ध्यान में रखते हुये, इंजीनियरी माल के निर्यात करने वाले विनिर्माताओं, जिनमें रेल के माल डिब्बे बनाने वाले भी शामिल हैं, को वितरित करने के लिए विपुल परिमाण में अनेक वर्गों के इस्पात के आयात की अनुमति दी गई है। अब तक, माल डिब्बों के निर्यातकों में वितरण के लिए 67,370 मे० टन इस्पात का आयात करने की अनुमति दी गई है।

लाजिमी कर्मचारियों को क्वाटरों का आबटंन

*356. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के उन गैर लाजिमी कर्मचारियों को अभी तक क्वार्टर नहीं दिए गये हैं जिन्हें चिकित्सा आधार पर बिना वारी के क्वार्टर देने की मंजूरी दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां

(ख) क्वार्टरों की अत्याधिक कमी और कर्मचारियों को किये गये कुल आबंटन को ध्यान में रखते हुए, बिना वारी के क्वार्टरों के आबंटन को न्यायसंगत आधार पर सीमित करने की आवश्यकता।

मध्य प्रदेश में तापीय विद्युत् संयंत्र लगाया जाना

*357. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या सिंचाई-विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के सिंधी जिले में सिंगरोली में एक बड़ा तापीय विद्युत् जनन एकक स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति तथा सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एस० राव) : (क) मध्य प्रदेश का राज्य में तीन ताप विद्युत् केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जो कोरबा, सतपुड़ा और सिंगरौली में स्थित होंगे और

जिनकी कुल क्षमता 3.63 मिलियन किलोवाट होगी। सिंगरौली में 1320 मैगावाट के जिस केन्द्र का प्रस्ताव है उसमें 330-330 मेगावाट की चार यूनिटें शामिल हैं।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को सलाह दी गई है कि वह एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे जो कि समस्त देश के लिए सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विद्युत् विकास के लिए समग्र स्कीम के सदृश हो। मध्य प्रदेश के लिए पांचवीं योजना में ताप-विद्युत् द्वारा 1460 मैगावाट की अनुमानित वृद्धि की संभावना है।

———

कड़े बालों (ब्रिसल्स) के निर्यात में कमी

*358. **श्री अनन्त प्रसाद घूसिया** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कड़े बालों (ब्रिसल्स) के निर्यात से कितनी विदेश मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या कड़े बालों के निर्यात में कमी हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके निर्यात में कमी को रोकने की दृष्टि से क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1968-69 से 1970-71 के वित्तीय वर्षों तथा 1971-72 के छः महीनों के दौरान अर्जित विदेशीमुद्रा की राशि इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा	मात्रा में० टनों में मूल्य 000 रु० में मूल्य
1968-69	124	11,861
1969-70	109	9,771
1970-71	73	5,583
1971-72 (अप्रैल-सितम्बर 71)	60	5,899

(ख) कड़े **बालों केनिर्यात में कमी के कारण** : कड़े बालों के निर्यात पर नेपाल सरकार द्वारा दिये जाने वाले आर्थिक लाभ के प्रोत्साहनोंके कारण भारतीय कड़े बाल नेपाल भेज दिए जाते थे

और वहां से उनका निर्यात किया जाता था। कड़े बालों के नेपाली नियर्यातक भारत आकर गांवों में कड़ों बालों की ऐंचने वाले व्यक्तियों के सम्पर्क स्थापित करते थे और भारतीय व्यापारियों की तुलना में उन्हें अधिक कीमतें देते थे । परन्तु कड़े बालों को निर्यात नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत लाया गया है।

2. बड़ी मात्रा में कड़े बालों के निर्यात करने के मार्ग में आने वाली एक प्रमुख बाधा यह है कि इसका व्यापार इस समय कुटीर उद्योग क्षेत्र में केन्द्रित हैं जिसमें वित्त तथा ऋण की सीमित सुविधाएं प्राप्त हैं। इसके निर्यातकों को लन्दन में होने वाली नीलामी पर निर्भर रहना पड़ता है जहां खरीदार प्रत्येक तिमाही में नीलामी के समय कीमत निर्धारित करते हैं। नीलामी में खरीदारों द्वारा लगायी गयी कीमते अधिक न होने पर भी निर्यातकों के पास खरीदार द्वारा लगाई गई कीमत पर बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं होता।

3. वर्तमान स्थिति में भारतीय निर्यातकों में सौदेवादी करने की कोई शक्ति नहीं है । यदि निर्यातक नीलामी कीमत पर अपने उत्पाद न बेचना चाहें, तो उन्हें अपना माल लंदन मालगोदाम में रखना पड़ता है जहां भाण्डागार की बीमा तथा रख-रखाव का प्रभार बढ़ता जाता है। परिणामस्वरूप निर्यातकों को खरीदारों द्वारा निर्धारित कीमतों पर अपना माल बेचने के लिए विवश होना पड़ता है।

4. चीन, जो कि कड़े बालों का सब से बड़ा उत्पादक देश है, अब विश्व में कड़े बालों के सर्वाधिक उपभोक्ता देश, सं० रा० अमेरिका को कड़े बालों का निर्यात करने में समर्थ है । इस के अलावा, चीनी कड़े बाल भारतीय कड़े बालों से बढ़िया क्वालिटी के भी होते हैं।

(ग) सरकार ने कड़े बालों के निर्यात में गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये है :

(i) इस वस्तु के नेपाल में चोरी से ले जाये जाने को रोकने के लिए कड़े बालों के निर्यात को मार्च, 1971 से निर्यात नियंत्रण आदेश के अर्न्गत लाया गया है।

(ii) आयातित उद्गम के दुर्लभ माल की कमी को पूरा करने हेतु 2 की दर से आधान प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

(iii) कड़े बालों के उद्योग को, जो कि कुटीर उद्योग क्षेत्र में केन्द्रित है और जिसको वित्त तथा ऋण की सीमित सुविधाएं उपलब्ध हैं, संगठित करने के उद्देश्य से भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड से कड़े बालों के निर्यात में सहायता देने के लिए कहा गया है।

केरल में चौथी-पंचवर्षीय योजना में रेलवे के विकास पर व्यय

*359. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के विकास पर अनुमानतः कितना धन व्यय किया जायगा; और

(ख) इसमें से कितना धन केरल में रेलवे के विकास पर व्यय किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री० के० हनुमंतैया) : (क) रेलों की चौथी पंचवर्षीय योजना में 1400 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है जिसमें गतायु परिसंपत्तियों के बदलाव के लिए 550 करोड़ रुपया शामिल है ।

(ख) रेलों का विकास राज्य वार या क्षेत्र वार नहीं किया जाता । रेलों द्वारा प्रारम्भ किया जाने वाला काम और उस पर होने वाला खर्च उस क्षेत्र के यातायात और परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है ।

डेनमार्क से व्यापार समझौता

*360. **श्री पम्पन गौडा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में डेनमार्क की सरकार के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं तथा उसके अन्तर्गत भारत डेनमार्क से किन-किन वस्तुओं का आयात करेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० लार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

व्हारपेज चार्जेज (उत्तर रेलवे) में छूट देना

2424. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जून, 1970 के बीजक संख्या 35 के अन्तर्गत अलीगढ़ से इलाहाबाद भेजे गये माल के सम्बन्ध में व्हारपेज चार्जेज की छूट देने के लिये किया गया अनुरोध पहले अस्वीकार कर दिया गया था और बाद में उसमें 50 प्रतिशत की छूट दे दी गई थी;

(ख) क्या एक ही प्राधिकार ने दोनों निर्णय लिये थे; और

(ग) क्या किसी ऐसे अधिकारी ने छूट का आदेश दिया था जो इस प्रकार के आदेश नहीं दे सकता था और यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). रिपोर्ट मिली है कि इलाहाबाद स्थित उत्तर रेलवे के मंडल कार्यालय से इस विषय से सम्बन्धित फाइल गुम है। इसलिए यह पता लगाना सम्भव नहीं हो सका है कि स्थान शुल्क प्रभार छोड़ देने के लिए माल पाने वाले का अनुरोध शुरू में अस्वीकार कर दिया गया था और यदि ऐसा किया गया था तो किस प्राधिकारी द्वारा।

अन्य रिकार्डों से पता चलता है कि विलम्ब शुल्क की कुल 523 र० 80 पै० की रकम में से 273 रु० 80 पै० की रकम छोड़ दी गयी थी।

(ग) जी नहीं। जिस अधिकारी ने विलम्ब शुल्क प्रभारों में छूट दी, वह ऐसा करने के लिए समर्थ था। अतः इस मामले में कोई कार्रवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

आय-कर अधिकरणों के समक्ष आय-कर के अनिर्णित मामले

2425. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी आय-कर अधिकरणों के समक्ष आय-कर के मामले बड़ी संख्या में जमा हो गये हैं;.

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी हैं और 2 और 3 वर्षों से अनिर्णित पड़े ऐसे मामलों के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इन मामलों के जमा होने के क्या कारण हैं और क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को पुनः निर्धारित करने की वांछनीयता पर विचार किया है कि ऐसे मामले अधिक समय तक अनिर्णित न रहें और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अधिकरण के समक्ष संस्थित की जाने वाली अपीलों की संख्या हाल के वर्षों में काफी बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण निर्धारण सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए राजस्व विभाग द्वारा चलाया गया अभियान और नए स्थानों पर नई न्यायपीठों की स्थापना है। अधिकरण, संस्थित की जाने वाली अपीलों की बढ़ती हुई संख्या से निपटने और लम्बित मामलों को कम करने के लिए

भरसक प्रयत्न कर रहा है। तथापि, चूंकि अधिकरण न्यायिककल्प निकाय है और विधि के प्रश्न पर उसके विनिश्चय को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में निर्देश द्वारा चुनौती दी जा सकती है, अतः वह अपने कृत्यों के महत्वपूर्ण गुणात्मक पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकता है।

अधिकरण के समक्ष अधिक संख्या में संस्थित की जाने वाली अपीलों पर कार्यवाही करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, अधिक न्यायपीठों की स्थापना करके हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। जनवरी, 1971 में 7 और न्यायपीठों की स्थापना की गई थी जिससे न्यायपीठों की कुल संख्या बढ़कर 30 हो गई थी। लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए जल्दी ही अधिकरण की 8 और न्यायपीठों की स्थापना की जा रही है। अपीलों को निपटाने के लिए नई न्यायपीठों की स्थापना करने के अतिरिक्त कतिपय अन्य प्रशासकीय उपाय भी किये गये हैं। मामलों को निपटाने की गति में सुधार के लिए अधिकरण के सदस्यों को प्रशासकीय स्तर पर निम्नलिखित सलाह दी गई है :

(i) आय-कर अधिकारी द्वारा संगठित 40,000/- रु० से अनधिक कुल आय वाले मामलों में अपीलों को निपटाने के लिए सम्यक् रूप से अपनी शक्तियों का अकेले प्रयोग करना;

(ii) प्रत्येक मास में प्रत्येक व्यायपीठ द्वारा 150 या इसके लगभग मामलों को निपटाना;

(iii) मामलों का स्थगन मंजूर करने में अधिक कड़ाई बरतना;

(iv) छोटे मामलों में खुले न्यायालय में आदेश सुनाना;

(v) अन्य मामलों में न्यायालय के समय से परे या शनिवार को आदेश सुनाना; और

(vi) प्रत्येक दिन मामलों की सुनवाई के लिए पांच घन्टे बैठना।

ऊपर वर्णित प्रशासकीय उपायों के अतिरिक्त आय-कर अधिनियम, 1961 को उचित रूप से संशोधित करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

पार्लियामेंट हाऊस में रेलवे कैंटीन द्वारा लिया जाने वाला दूध

2426. **श्री के. सूर्यनारायण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पार्लियामेंट हाउस की रेलवे केटरिंग ऐस्टेब्लिमेंट द्वारा दूध कहां से लिया जाता है;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिये कि दूध शुद्ध है कोई जांच की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार से और, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) संसद भवन की रेलवे केंटीन में इस्तेमाल के लिए कुछ दूध दिल्ली दुग्ध योजना से और कुछ केवेंटर्स से सील की हुई बोतलों में लिया जाता है।

(ख) और (ग). चूंकि ये दोनों पार्टियां, विधिवत जांच करने के बाद पास्तुरीकृत दूध सप्लाई कर रही हैं और दूध की किस्म के सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, अतः रेलवे द्वारा किसी प्रकार की जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

आजई नदी (बिहार) पर पुनासी बांध का निर्माण

2427. **श्री शिवचंडिका** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में संथाल परगना जिले के देवगढ़ सब-डिवीजन में अजई नदी पर पुनासी बांध के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(क) क्या इस बांध के पूरा हो जाने पर उससे रोहाइन, मोहनपुर तथा देवगढ़ प्रखंड क ग्रामों को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध होंगी; और

(ग) निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). मार्च, 1967 में बिहार सरकार ने देवधर, जसिडीह, मोहनपुर पुलिस स्टेशन और देवधर उपमंडल के सरवन तथा बंका उपमंडल में चानण के क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए पुनासी जलाशय परियोजना हेतु प्रस्ताव भेजे थे। स्कीम पर टिप्पणियां अक्तूबर, 1967 में भेज दी गई थीं। राज्य सरकार ने उत्तर नहीं भेजे हैं और इस परियोजना को चतुर्थ योजना में सम्मिलित करने के लिए भी प्रस्ताव नहीं किया है।

जोधपुर लोको वर्क्स का कार्यकरण

2428. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर लोको वर्क्स पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी बेकार क्षमता का प्रयोग किया जा सकता है; और

(ग) यह क्षमता कब से बेकार पड़ी है और क्षमता का पूरी तरह प्रयोग करने के लिये क्या कार्य-वाही की जा रही है?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) जोधपुर कारखाने में उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

तराशे हुए पत्थरों के निर्यात में वृद्धि

2429. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में तराशे हुए पत्थरों के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने निर्यात से कमी होने के कारणों का पता लगाया है; और

(ग) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण ने तराशे हुये पत्थरों के लिये नई मण्डियों का पता लगाने के लिये और इन पत्थरों के निर्यात के संवर्धन के लिये कोई योजना बनाई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) गत तीन वर्षों में कीमती तथा अर्ध-कीमती हीरों के निर्यात में कमी-वेशी होती रही हैं, जो निम्नोक्त प्रकार हे :

वर्ष	मूल्य (लाख रु.)
1968-69	1166.69
1969-70	1274.45
1970-71	913.43

(ख) 1969-70 की तुलना में 1970-71 में निर्यात में जो गिरावट हुई उसके कारण निम्नोक्त हैं;

(1) विदेशों में बाजार सम्बन्धी प्रतिकूल परिस्थितियां;

(2) सं. रा. अमरीका, जो कि प्रमुख बाजार है, में अत्यधिक मंदी ।

(ग) जी नहीं ।

राजस्थान को बिजली की सप्लाई

2430. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा, सतपुड़ा और कोटा परियोजनाओं से इस समय राजस्थान को कुल कितनी बिजली सप्लाई की जा रही है ;

(ख) क्या यह सप्लाई इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए इसे बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) इस समय भाखड़ा सतपुड़ा और चम्बल परियोजाओं के माध्यम से राजस्थान की सप्लाई की जा रही विद्युत की कुल मात्रा 300 मेगावाट है।

(ख) राज्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इन पीरयोजनाओं से विद्युत सप्लाई से की जाती है। साथ ही लघु तापविद्युत और डीजल यूनिटों से भी विद्युत पैदा की जाती है।

(ग) निकट भविष्य में होने वाली अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना (कोटा) और राणाप्रताप सागर परमाणु विद्युत केन्द्रों से, जिनके इस वर्ष के दौरान ही चालू किये जाने की सम्भावना है, की जाएगी।

देहरी-आन-सोन और बरवाडीह (पूर्व रेलवे) के बीच दिन में एक अन्य रेलगाड़ी का चलाया जाना

2431. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरी-आन-सोन और बरवाडीह के बीच दिन के समय में कितनी यात्री गाड़ियां चलती हैं; और

(ख) क्या इस मार्ग पर दिन में एक अन्य रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (श्री के. हनुमन्तेया) : (क) दो।

(ख) जी नहीं।

मुगलसराय स्टेशन के लिए देहरी-ओन-सोन में टिकटों की बिक्री

2432. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरी-ओन-सोन से 16 और 17 जुलाई, 1971 को मुगलसराय जंकशन के लिए कुल कितने टिकट बेचे गये; और

(ख) उक्त तारीखों को मुगलसराय स्टेशन पर कुल कितने टिकट एकत्र किए गए ?

रेल मन्त्री (श्री के. हनुमन्तेया) : (क) 16 और 17 जुलाई, 1971 और देहरी-ओन-सोन से मुगलसराय जंकशन के लिए बेचे गये टिकटों की संख्या क्रमशः 57 और 73 थी।

(ख) उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित टिकटों में से 16 और 17 जुलाई, 1971 को मुगल-सराय में प्राप्त हुए टिकटों की संख्या क्रमशः 42 और 58 थी।

रेलवे फाटकों पर उपरि पुल

2433. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) देश में, राज्यवार, कुल कितने रेलवे फाटक हैं;

(ख) ऐसे रेलवे फाटकों की संख्या कितनी है जिन पर गत तीन वर्षों से उपरिपुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) शेष रेलवे फाटकों पर उपरिपुल का निर्माण कब तक हो जायेगा और उस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के वर्षों की अवधि में समपारों के स्थान पर 45 ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण का काम पूरा किया गया।

(ग) रेलों की यह नीति है कि वर्तमान व्यस्त रेल समपारों के बदले, न कि सभी समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया जाये। इस तरह की योजनाओं को राज्य सरकारों और सड़क प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें यह वचन देना होता है कि वे वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अपने हिस्से का खर्च वहन करेंगे। इस समय, यह बताना सम्भव नहीं है कि बाकी के व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों की व्यवस्था कब तक हो सकेगी। इस सम्बन्ध में कुल खर्च कितना आयेगा यह बताना भी सम्भव नहीं है।

विवरण

भारतीय रेलों पर मवेशी समपारों सहित समपारों की राज्य-वार कुल संख्या

राज्य	समपारों की संख्या
महाराष्ट्र	2547
मध्य प्रदेश	2843
तामिलनाडु	3332
बिहार	3378
उड़ीसा	1209
केरल	921
पश्चिम बंगाल	2845
असम	1351

आन्ध्र प्रदेश		2784
मैसूर		1719
उत्तर प्रदेश		6253
जम्मू और काश्मीर		6
हरियाणा		945
राजस्थान		3527
हिमाचल प्रदेश		355
पंजाब		1992
गुजरात		5056
	जोड़	41,063

केन्द्र शासित प्रदेश

पाण्डिचरी		16
दिल्ली		86
चंडीगढ़		3
गोआ		13
	जोड़	118

कुल जोड़ 41063+118=41,181

मेरालग्राम और रामना रेलवे स्टेशनों (पूर्व रेलवे) पर अपर क्लास प्रतीक्षालयों की व्यवस्था

2434. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालामऊ (बिहार) में मेरालग्राम और रामना रेलवे स्टेशनों पर अपर क्लास के यात्रियों के लिए प्रतीक्षालयों की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) क्या तत्सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) मेरालग्राम और रामन्ना स्टेशनों पर ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिए अलग प्रतीक्षा कमरे की सुविधा की व्यवस्था नहीं है।

(ख) जी नहीं।

बिहार में लोक सभा के मध्यावधि निर्वाचनों के लिए ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को यात्रा दैनिक भत्ते का भुगतान

2435. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 में बिहार में लोक सभा के मध्यावधि निर्वाचनों में निर्वाचन कार्यों पर तैनात कर्मचारियों की जिला-वार संख्या कितनी थी;

(ख) जिला-वार ऐसे कर्मचारियों को कितना यात्रा/दैनिक भत्ता दिया गया और जिला-वार कितना भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है; और

(ग) सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है कि भुगतान शीघ्र किया जाये ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी बिहार सरकार से इकट्ठी की जा रही है और सम्यक् अनुक्रम में सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पेंरुगुंभी रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) का "फ्लेग स्टेशन' के रूप में दर्जा बनाया जाना

2436. **श्री बयालार रवि** : क्या **रेल मंत्री** 16 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्नसंख्या 205 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में पेंरुगुंभी रेलवे स्टेशन को 'फ्लेग-स्टेशन' बनाने का इस बीच निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जी नहीं। पेरुंगुंभी गाड़ी हाल्ट को फ्लेग स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव की जांच की गई है लेकिन वित्तीय दृष्टि से उसे उचित नहीं पाया गया।

Construction of an Over-Bridge at Vyara Railway Station (Western Railway)

2437. SHRI AMAR SINGH CHAUDHURY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to construct an overbridge at Vyara Railway Station of Western Railway; and

(b) if so, the time by which this overbridge is likely to be constructed ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) No.

(b) Does not arise.

रेलवे के मुख्य लेखा परीक्षकों द्वारा निरीक्षक रेल डिब्बों का उपयोग

2438. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **रेल** मंत्री रेलवे लेखा परीक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आये भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण रेल डिब्बों और सैलूनों का उपयोग करने के बारे में 23 नवम्बर, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 202 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के मुख्य लेखा परीक्षकों को स्टेशनों का, जहां विश्रामालय संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं, दौरा करते समय अथवा स्थानांतरण के समय अथवा सरकारी बैठकों में उपस्थित होने के लिए दिल्ली आते समय निरीक्षण रेल डिब्बों का उपयोग करने की अनुमति है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के उस समय के मुख्य लेखा परीक्षक ने फरवरी, 1971 को दिल्ली में स्थानांतरण होने वर विशेष रेल डिब्बे में यात्रा की थी; और

(ग) उन्हीं मुख्य लेखा परीक्षक ने और उसके पूर्ववर्ती तथा उत्तराधिकारी ने अपने सेवा काल में गोरखपुर से लखनऊ को यात्रा करते समय कितनी बार निरीक्षण रेल डिब्बों का उपयोग किया था ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) मुख्यतः कार्यात्मिक प्रयोजनों जैसे निरीक्षण, जांच और पड़ताल आदि के लिए मुख्य लेखा परीक्षकों का अन्य रेल अधिकारियों की तरह निरीक्षण यानों का उपयोग करने की अनुभति है। किसी बैठक या सम्मेलन में उपस्थित होने जैसे प्रयोजनों के लिए उन स्टेशनों तक जाने के लिए, जहां विश्राम गृह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, निरीक्षण यानों का उपयोग सामान्यतः हतोत्साहित किया जाता है। दिल्ली होने वाली बैठकों में उपस्थित होने के लिए निरीक्षण यानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं हैं जब तक मार्ग में निरीक्षण करना शामिल न हो। नियमों के अनुसार स्थानान्तरण पर जाते समय निरीक्षण यानों के उपयोग की व्यवस्था नहीं है।

(ख) मुख्य लेखा परीक्षक को, उनके स्थानान्तरण के समय किसी विशेष बोगी का आबंटन नहीं किया गया था।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

'एशियन पेपर कम्यूनिटी' गनाने का प्रस्ताव

2439. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एशियन पेपर कम्यूनिटी' बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज : (क) जी हां ।

जिस समुदाय की स्थापना की जा रही है वह 'काली मिर्च समुदाय' हैं न कि 'एशियन काली मिर्च समुदाय' । इसका अभिप्राय यह है कि ऐसे देश भी, जो कि काली मिर्च के उत्पादक देश तो हैं परन्तु एशिया मे स्थिति नहीं हैं, इस समुदाय में शामिल हो सकते हैं ।

(ख) 'काली मिर्च समुदाय' की स्थापना करने के करार की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये** संख्या एल.टी. 1710/72]

(ग) भारत ने 'काली मिर्च समुदाय' का सदस्य बनने के प्रयोजनार्थ इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और उसे अनुसमर्थित कर दिया है । अनुसमर्थन सम्बन्धी दस्तावेज दिनांक 29 मार्च, 1972 को संयुक्त राष्ट्र महा-सचिव के पास जमा कराया गया था ।

पश्चिम रेलवे में वाणिज्यि क्लर्कों की मंजूरशुदा संख्या

2440. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में प्रत्येक ग्रेड के वाणिज्यिक क्लर्कों की, अलग-अलग, मंजूरशुदा संख्या कितनी है;

(ख) 1 जनवरी, 1972 को पश्चिम रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में प्रत्येक ग्रेड के वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या अलग-अलग कितनी थी;

(ग) 1 जनवरी, 1972 को पश्चिम रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में माल, पार्सल और टिकट-घरों में अलग-अलग रिक्त स्थानों की कुल संख्या कितनी थी; और

(घ) कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

संगचल कर्मचारियों के लिये विश्राम सुविधायें

2441. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्यालय (हैडक्वार्टर) से बाहर ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों को रेलवे द्वारा विश्राम सुविधायें दी जाती है;

(ख) क्या मुख्यालय से बाहर के स्टेशनों पर संगचल कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह तथा संगचल कर्मचारियों के लिए रनिंग रूम बने हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का आवास तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं; और

(घ) विश्राम गृह तथा रनिंग रूम का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों से उनके यात्रा भत्ते या वेतन से कितनी राशि वसूल की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). वर्तमान नियमों के अनुसार परिचलन कर्मचारी परिचलन कमरों में विश्राम करने/भोजन पकाने की सुविधाएं पाने के हकदार हैं। मुख्य परिचलन कर्मचारियों की आवश्यकताएं पूरी हो जाने के बाद यदि परिचलन कमरों में फालतू जगह उपलब्ध रखती है, तो चल टिकट परीक्षकों आदि जैसे गैर परिचलन कर्मचारियों की कुछ कोटियों को भी उसे इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है। इन अनुदेशों के अनुसार जहां वर्तमान परिचलन कमरों में सुविधाऐं इतनी नहीं है कि उनका विशिष्ट कोटियों के गैर-परिचलन कर्मचारी इस्तेमाल कर सकें, वहां एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्ही इमारतों में या सुविधा अनुसार किहीं अन्यतरण पारेचलन कमरों के रूप में केवल बिश्राम गृहों का निर्माण करके इन सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ग) परिचलन कमरों में विश्राम के अलावा भोजन पकाने की सुविधा रहती है जब कि विश्राम गृहों में आमतौर पर केवल विश्राम की सुविधा रहती है।

(घ) विश्राम गृहों और परिचलन कमरों का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों से कोई रकम नहीं वसूल की जाती।

रनिंग रूमों में अत्याधिक भीड़

2442. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भारतीय रेलों में रेल कर्मचारियों के रनिंग रूमों में भी अत्याधिक भीड़ रहती है और उनमें उचित सुविधाओं का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं, किन्तु कुछ मामलों को छोड़कर कर।

(ख) जहां आवश्यक है, उन स्थानों में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के लिए योजना बनायी जा रही है।

संगचलन भत्ते का भुगतान

2443. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगचल कर्मचारियों को यात्रा भत्ते के रूप में संगचल भत्ता दिया जा रहा है जिसको वेतन तथा प्रोत्साहन का अंग समझा जाता हैं;

(ख) यदि हां, तो संगचल कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग के संगचल भत्ते में प्रत्येक की प्रतिशतता कितनी है और ड्यूटी पर जाने की प्रतीक्षा करते समय कर्मचारियों को वेतन के भुगतान की प्रक्रिया क्या हैं; और

(ग) क्या 1956 के बाद संगचल कर्मचारियों के संगचल भत्ते में कोई वृद्धियां की गई है, और यदि हां, तो संगचल कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग के भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रनिंग कर्मचारियों को दिये जाने वाले रनिंग भत्ते में जेब खर्च (यात्रा भत्ता) का तत्व और प्रोत्साहन तत्व (वेतन का तत्व) शामिल है।

(ख) दोनों तत्वों के लिए कोई अलग प्रतिशत निर्धारित नहीं है। श्रम संगठनों के परामर्श से रनिंग भत्ते की दरें इस तरह से निर्धारित की जाती हैं कि उनमें वेतन और यात्रा भत्ता दोनों तत्व परिलक्षित हों।

प्रतीक्षा ड्यूटी के लिए, जिसकी अवधि किलोमीटरों में परिवर्तित कर दी जाती हैं, [प्रत्येक कोटि पर लागू रनिंग भत्ते की दर पर भुगतान किया जाता है।

(ग) जी हां। प्रतिशत वृद्धि संलग्न विवरण में दिखायी गयी है।

कर्मचारियों में कोटि	दर प्रति 100 किलोमीटर		प्रतिशत वृद्धि
	1-4-56	1-1-71	
	रु० पै०	रु० पै०	
1. ड्राइवर 'ए'	2·80	7·90	282
2. ड्राइबर 'बी'	2·65	7·85	296
3. ड्राइवर 'सी'	2·50	7·80	312
4. फायरमैन 'ए' | सहायक ड्राइवर प्रथम फायरमैन | ड्राइवर सहायक	1·40	5·20	371
5. फायरमैन 'बी' प्रथम फायरमैन	1·25	4·30	344
6. फायरमैन 'सी' द्वितीय फायरमैन	1·05	4·20	400
7. आगवाला	—	—	—
8. गार्ड 'ए'	1·70	5·70	335
9. गार्ड 'बी'	1·60	5·65	353
10. गार्ड 'सी'	1·55	5·60	361
11. शंटिंग कर्मीदल शंटर ग्रेड 'ए'	2·50	5·25	210
12. शंटर 'बी'	2·50	5·25	210
13. शंटर 'सी'	—	—	—

14.	प्रथम फारयमैन 'ए'	1·20	3·20	267
15.	प्रथम फायरमैन 'बी'	1·00	2·05	265
16.	द्वितीय फायरमैन	0·80	2·50	312
17.	ब्रेक्समैन 'ए'	0·95	3·50	368
18.	ब्रेक्समैन 'बी'	—	—	—

आयात और निर्यात कार्यों को पृथक करने सम्बन्धी राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन का वक्तव्य

2444. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन श्री पी० एल० टंडन के भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ के सदस्यों के सम्मुख दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि राज्य व्यापार निगम भारत के विदेश व्यापार में अधिक योग दे सकता है यदि उसके आयात और निर्यात सम्बन्धी कार्य पृथक कर दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जब कि इस सन्दर्भ में श्री टंडन का वक्तव्य सामान्यतः सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली वर्तमान नीति को ही दर्शाता है, आयातों तथा निर्यातों को सम्बद्ध करने की अनुमति उन परिस्थितियों में दी जाती है जब कि इस प्रकार के सम्बद्ध किये जाने का परिणाम अर्थव्यवस्था के लिये समग्र रूप से हितकर हो ।

तकनीकी पदों पर इंजीनियरी के डिप्लोमा धारियों और डिग्री-धारियों की भर्ती

2445. **श्री एस. डी. सोमसुन्दरम्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे शिक्षित इंजीनियर बहुत अधिक संख्या में बेरोजगार हैं जो किसी विशेष इंजीनियरिंग क्षेत्र, विशेषकर अनुसंधान कार्य के लिए, प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो चीफ रिसर्च असिस्टेंट (इलेक्ट्रोनिक्स), सीनियर रिसर्च असिस्टेंट (इलेक्ट्रोनिक्स), और जूनियर रिसर्च असिस्टेंट (इलेक्ट्रोनिक्स) जैसे पदों के लिये विज्ञान की स्नातकोत्तर डिग्री की इंजीनियरिंग की डिग्री के समान और विज्ञान स्नातर को इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारियों के बराबर मानने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार की गई भर्ती से विभाग की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) शुद्ध तकनीकी पदों पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री-धारियों को रखने के लिए कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

रेल मंत्रालय (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) से (घ). सम्बन्धित मंत्रालय से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्री लंका द्वारा तामिल दैनिकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना

2446. **श्री के० मालन्ना :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में श्री लंका सरकार ने भारत में प्रकाशित तामिल दैनिकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) बताया गया है कि यह प्रतिबन्ध उनकी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिन स्थिति के कारण और भारतीय तामिल दैनिकों की प्रतिस्पर्द्धा से श्रीलंका के दैनिकों की रक्षा करने के लिये लगाया गया है।

(ग) इस मामले के सम्बन्ध में श्रीलंका के प्राधिकारियों से बातचीत की गयी थी, परन्तु प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए उन्होंने इन प्रतिबन्धों में छूट देना सम्भव नहीं पाया है।

विना सोचे समझे नलकूपों का खोदा जाना

2447. **श्री राजदेवसिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई आयोग ने सरकार को यह चेतावनी दी है कि बिना सोचे समझे नलकूल नहीं खोदे जाने चाहिये और यह कि भूमिगत जल जिस दर से एकत्र होता है, उससे अधिक दर से वह भूमि से न निकाला जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या आयोग ने प्रभावशाली बरानी खेती के विकास के साथ-साथ पानी के वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता का सुझाव दिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री श्री बैजनाथ कुरील : (क) से (ग). सिंचाई आयोग ने बताया है कि भूगत जल के अविवेकपूर्ण प्रयोग से गम्भीर कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं और उनका विचार है कि नलकूप निर्माण का कार्य उन क्षेत्रों में कानून द्वारा नियमित किया जाना चाहिए जहां पर पानी के अति उपयोग का खतरा है ताकि किसी क्षेत्र विशेष में भूगत संसाधनों को सुव्यवस्थित उपयोग करने के लिए नलकूपों के आकार और इनके बीच की दूरी को नियंत्रित किया जा सके।

आयोग ने सिंचाई के लिए पानी के दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए कई सुझाव दिए हैं। आयोग को भेजे गए विचारार्थ विषयों में बागनी खेती शामिल नहीं थी।

सिंचाई आयोग के सुझावों की सरकार द्वारा जांच हो रही है।

विवाह की वैद्य न्यूनतम आयु को बढ़ाना

2448. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विवाह की वैध न्यूनतम आयु को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) विवाह के लिए आयु में वृद्धि करने से प्रजननशक्ति के घटने की सम्भावना है क्योंकि इससे प्रजनन की अवधि का विस्तार कम हो जाएगा और परिणामस्वरूप परिवार नियोजन का कार्यक्रम, जो कि जनसंख्या में वृद्धि की दर को रोके रखने की दृष्टि से राष्ट्रीय पैमाने पर चालू किया गया है, आगे बढ़ेगा।

कपास के लिए न्यूनतम मूल्य समर्थन नीति

2449. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में फसल उगाने सम्बन्धी प्रणाली में सुधार करने के लिये गारंटी युक्त न्यूनतम मूल्य समर्थन नीति सम्बन्धी सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) तथा (ख). उपजकर्ताओं को उनका उपज के लिये न्यूनतम समर्थन कीमत की गारंटी देना सरकार की घोषित नीति है। चूंकि पिछले कुछ वर्षों में रुई की प्रचलित बाजार कीमतें कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की गई इन न्यूनतम समर्थन कीमतों से काफी ऊंची रही हैं अतः इन कीमतों पर क्रय करना आवश्यक नहीं था। चालू मौसम में, कीमतों में स्थिरता लाने के लिये रुई निगम से अपनी खरीद बढ़ाने के लिये कहा गया है।

बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली के स्प्रिग कार्नीवाल में घटित घटना

2450. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 फरवरी, 1972 को बड़ौदा हाउस नई दिल्ली में एक 'स्प्रिग कार्नीवाल' मनाया गया था; और

(ख) क्या इस अवसर पर हुई कुछ घटनाओं को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में ऐसे कार्नीवाल बन्द करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। घटना बड़ौदा हाउस के बाहर कर्जन रोड पर हुई थी।

नियंत्रित कपड़े का मूल्य बढ़ाने के लिये मिल मालिकों का दवाव

2451. **श्री राज रार्जासह देव** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मिल मालिकों द्वारा नियंत्रित किस्मों के कपड़े का मूल्य बढ़ाने के लिये दबाव डाला जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) तथा (ख). फरवरी 1970 में भारतीय सूती मिल संघ ने 2-5-1968 को निर्धारित किये गये मूल्यों पर गुणक को बढ़ाकर 29 से 30 प्रतिशत करने के लिये कहा था।

(ग) नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में संशोधन करने का प्रश्न औद्योगिक लागत तथा कीमत ब्यूरो को सौंप दिया गया है। उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

काजू उद्योग में संकट के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा केरल के सभी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल को दिये गये आश्वासन को पूरा करना

2452. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उन आश्वासनों को कहां तक पूरा किया है जो प्रधान मंत्री ने गत वर्ष केरल के काजू उद्योग में उत्पन्न संकट पर चर्चा करने के लिए आए सभी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल को दिया था ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : केरल से सर्व-दलीय प्रतिनिधि-मंडल के प्रधान मंत्री से मिलने के पश्चात् जो केन्द्रीय अध्ययन दल मई, 1971 में केरल को भेजा गया था, उसकी सिफारिशों पर भारत सरकार ने काजू उद्योग के संबंध में कुछ उपाय किये हैं। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1. सरकार ने केरल राज्य सरकार को 20 लाख रुपये का ऋण दिया है जिससे केरल राज्य काजू विकास निगम काजू साधित करने वाले बंद पड़े दस कारखानों को अपने अधिकार में ले सके और उन्हें पुनः चालू कर सके।

2. भारतीय काजू निगम को सलाह दी गई है कि वह केरल राज्य काजू विकास निगम को 20 लाख रुपये का 90 दिन का ऋण दे।

3. भारतीय काजू निगम को निदेश दिया गया है कि किसी कारखाने का कच्चे काजू का आयात आबंटन तय करते समय उसमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या को ध्यान में रखे।

4. आबंटी आयातित कच्चे काजू के अपने कोटे का अंतरण केवल भारतीय काजू निगम की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही कर सकते हैं।

कोट्टावाल्सा किरुनडुल रेल लाइन का निर्माण

2453. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टावाल्सा और किरुनडुल के बीच 44 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन को समय से पूर्व ही बदलना पड़ा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 1965-66 में इसका निर्माण होते समय इन कारणों का पहले ही क्यों नहीं पता लगाया जा सका था;

(ख) क्या इस लाइन के 25 प्रतिशत लकड़ी के स्लीपर बेकार हो गये हैं और उनके स्थान पर अन्य स्लीपर लगाने की आवश्यकता हैं; और

(ग) क्या इस हानि के लिए किसी पर जिम्मेदारी नियत की गई है और यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बिरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। लेकिन कोट्टावाल्सा—किरुनडुल रेलवे लाइन के जटिल अन्नथागिरि खंड के तीव्र मोड़ों पर लगभग 44 किलोमीटर लम्बी रेल लाइनों का बदलाव किया जा रहा है। इस बदलाव की आवश्यकता इसलिए है कि निम्नलिखित कारणों से पटरियां असाधारण रूप से घिस गयी थी :—

(i) 44 किलोमीटर की पूरी लम्बाई में अत्यधिक तीव्र घुमाव,

(ii) निरंतर 60 कि० मी० की अत्यधिक ढलान

(iii) बहु संख्यक सुरंगें।

(iv) अधिक धुरा—भार और कम व्यास के पहियों वाले वी. ओ. बी. एक्स./वी. ओ. एक्स. माल डिब्बों में लादा गया अत्यधिक लोह-वयस्क यातायात जिसे तीन डीज़ल इंजनों से खींचा जाता है।

इस तरह के पहलुओं का जो सबसे खराब सम्मिश्रण इस लाइन पर दिखाई दिया, वह निर्माण के समय भारतीय रेलों पर अन्यत्र कहीं भी विद्यमान नहीं था इसलिये इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

व्यापार विकास प्राधिकरण का यूरोपीय देशों को कुछ वस्तुओं का निर्यात करने सम्बन्धी करार

2455. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण ने कुछ यूरोपीय देशों से कुछ वस्तुओं का निर्माण करने और उन देशों को उनका निर्यात करने के लिए समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं तथा देशों के नाम क्या है;

(ग) उससे अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी; और

(घ) क्या इन वस्तुओं का निर्माण करने के लिए सयन्त्र पूर्णरूपेण स्वदेश के बने हुए होंगे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). व्यापार विकास प्राधिकरण व्यापारिक संगठन नहीं है बल्कि यह सेवा प्रदान करने वाला एक अभिकरण है जो व्यापारिक संपर्क स्थापित करने में भारतीय निर्यातक एककों तथा विदेशी क्रेताओं की सहायता करता हैं, निर्यात उत्पादन में सुविधा प्रदान करता है तथा विपणन की संभावनाएं बढ़ाता है। अपने कार्य-कलापों में इसने निर्यात के लिए कुछ वस्तुएं भारत में ही तैयार करने के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के सम्बन्धी चार मामलों में भारतीय निर्यातकों और विदेशी विनिर्माताओं/आयातकों की भी सहायता की।

जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा तथा जिन देशों को उनका निर्यात किया जायेगा उसका व्यौरा इस प्रकार है : ब्रिटेन के लिए **एल-टी** स्विच गियर, ब्रिटेन के लिए मशीनी औजार, ब्रिटेन के लिए इन्टर्नल कम्बश्चन इंजन के हिस्से तथा नीदरलैंड्स के लिए हाइड्रालिक जैक्स तथा शाक एयजार्बर।

इन प्रस्थापनाओं से 5 वर्ष की अवधि में 2.5 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित विदेशी मुद्रा की आय होने की संभावना है।

इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए संयंत्र तथा औजार विदेशी सहयोगियों द्वारा सप्लाई किए जाएंगे।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापान् को मैंगनीज अयस्क का निर्यात

2456. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने जापान को मैंगजीन अयस्क की सप्लाई करने के लिए जापान स्टील मिल्स के साथ करार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितना मूल्य देना निश्चित हुआ है; और

(ग) अयस्क की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की जाएगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) तथा (ग)**. जी हां, 1972-73 के दौरान 3,00,000 मै. टन लौह-युक्त मैंगनीज (जिसमें, इस्पात मिलों की इच्छा पर निर्यात की जाने वाली 0.7 लाख मे. टन की मात्रा भी शामिल है) की सप्लाई के लिए, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने जापान की इस्पात मिलों के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) कीमतें बताना लोक हित में समीचीन नहीं है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा पेरू से विद्युत-विश्लेषिक तांबे का आयात

2457. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पेरू खनिज निगम जिस पर पेरू सरकार का स्वामित्व है से करार किया है कि जिसके अन्तर्गत विद्युत-विश्लेषिक तांबे का भारत में आयात होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): **(क) तथा (ख)**. जी नहीं। तथापि, खनिज तथा धातु व्यापार निगम पेरू से दीर्घावधि आधार पर विद्युत विश्लेषिक तांबे के तार की छड़ों का आयात करने के लिए एक संविदा के बारे में बातचीत कर रहा हैं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा रूमानिया को लौह् अवस्क का निर्यात

2458. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने रूयानिया को लौह् अयस्क का निर्यात करने के लिए उस देश के साथ करार किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने लौह् अयस्क का निर्यात किया जायेगा; और

(ग) इस करार की शर्तें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : संविदा में अप्रैल, 1972 से मार्च, 1973 के दौरान 18 लाख टन लौह् अयस्क का निर्यात करने की व्यवस्था है।

लौह् अयस्क का निर्यात

2459. **श्री सी० टी० दंडपाणि** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बनाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971 में भारत से कितने लौह् अयस्क का विर्यात किया गया ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : बर्ष 1971 के दौरान भारत से 109.68 करोड़ रु० मूल्य के 204 लाख मे. टन लौह् अयस्क का निर्यात किया गया।

एशियाई साझा बाजार की स्थापना

2460. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी देश ने एशियाई देशों के बीच व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय साझा बाजार के समान एशियाई साझा बाजार की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत तथा अन्य एशियाई देशों के बीच इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ है यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कालीकट विश्वविद्यालय को दोलन दर्शी (आसीलोस्कोप) का आयात करने का लाइसेंस देना

2461. **श्री राजदेव सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट विश्वविद्यालय को गत दो वर्षों से लगभग 35,000 रुपये मूल्य का दोलनदर्शी (आसीलोस्कोप) क्रय करने के लिए आयात लाइसेंस नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) 35,000 रुपये मूल्य के आसीलोस्कोप आयात करने के लिए कालीकट विश्वविद्यालय से निर्धारित रूप में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

युगोस्लाविया को मन्त्रालय-स्तर का प्रतिनिधि मंडल

2462. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने फरवरी-मार्च, 1972 के दौरान एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल युगोस्लाविया भेजा था और यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन थे;

(ख) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ;

(ग) प्रतिनिधिमंडल के ऐसे कौन से सदस्य हैं जो अपने अपने मंत्रालयों में कार्य करते हुए 4-5 से भी अधिक बार विदेश जा चुके हैं; और

(घ) प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को चुनने की पद्धति को व्यापक न बनाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का चयन बातचीत के लिए कार्य-सूची तथा संबंधित अधिकारियों के उत्तरदायित्वों को देखकर करना होता है।

विवरण

प्रतिनिधिमंडल का गठन	विदेशी मुद्रा में अनुमानित व्यय	वे सदस्य जो 4-5 से अधिक बार विदेश गये
1. श्री ए. सी. जार्ज, उप-मंत्री (विदेश व्यापार) —नेता		वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

2. श्री एम. जी. कौल, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग —सदस्य	6500/- रु. लगभग	1. श्री एम. जी. कौल, अपर सचिव ।
3. श्री बी. एन. स्वरूप, संयुक्त सचिव, विदेश व्यापार मंत्रालय —सदस्य		2. श्री के. सी. सोधिया विशेष कार्य अधिकारी
4. श्री के. सी. सोधिया, विशेष कार्य अधिकारी, वित्त मंत्रालय —सदस्य		**विदेश व्यापार मंत्रालय** 1. श्री बी. एन. स्वरूप, संयुक्त सचिव ।
5. श्री एन. के. सिंह, अवर सचिव, विदेश व्यापार मंत्रालय —सदस्य		2. श्री एन. के. सिंह, अवर सचिव ।

Movement of Coal from Madhya Pradesh

2463. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the coal produced in Madhya Pradesh cannot move beyond Katni, Bina-Kota line according to the rationalised movement of coal policy decided in 1952;

(b) whether Government are aware that the movement of coal from Central India Coalfields to Punjab and Uttar Pradesh etc., will be cheaper than from Bihar and Bengal; and

(c) if so, whether Government propose to consider revising its movement policy for Madhya Pradesh coal ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) No, according to the Rationalisation of Movement Scheme now in force, coal from Central India Coalfields in Madhya Pradesh can move upto Jhansi and Manikpur. Coal from Singrauli fields in Madhya Pradesh can, however, move to the entire Northern region including Punjab and Uttar Pradesh.

(b) The freight rates of coal from Central India Coalfields to destination in Punjab and to a few destinations in Uttar Pradesh are marginally cheaper than those from the Bengal-Bihar fields.

(c) The present embargo on the movement of coal from Central India Coalfields to Northern India is due to limited movement capacity on Bina-Jhansi-Agra section and will last till the doubling of the same is completed. After the doubling is over, limited movement of coal from Central India Coal-fields to these areas except destinations in Uttar Pradesh on Northern Railway will be permitted. But the bulk of the increased demand for these areas, is to be met from Singrauli fields of Madhya Pradesh for which extensive capacity has been developed by the Railways. It is not possible to transport coal from Central India Coalfields to destinations in Uttar Pradesh on Northern Railway due to long circuitous movement involved. Coal from Central India Coalfields is to meet the present and future demand in Western and Central India.

वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के कार्यालय द्वारा जाली बिलों का भुगतान

2464. श्री एस. सी. सामन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा वस्तुओं के क्रय के जाली बिलों के कुछ भुगतान किये जाने का पता लगा है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन भुगतानों में कितनी धनराशि अन्तर्गत है और क्या सम्बन्धित व्यक्तियों से इसकी वसूली कर ली गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस प्रकार के एक मामले की जांच पड़ताल की थी।

(ख) इस मामले में 1,69,224.30 रुपये का घोटाला है। सम्बन्ध व्यक्तियों से अभी तक कोई रकम वसूल नहीं की गई है क्योंकि उनके विरुद्ध फौजदारी की कार्यवाई की गई है। लखनऊ के विशेष जज ने उन्हें दोषी ठहराया और हाल ही में उन्हें 3½ वर्ष से 5 वर्ष तक की कड़ी कैद की सजा दी है।

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए पर्याप्त उपचारात्मक उपाय किये गये हैं जैसे निरन्तरता पंजी का रखा जाना, जमा खाते की रकमों का सत्यापन और लेखा विभाग द्वारा क्रय आदेशों का परिशोधन किया जाना चाहिए।

यूरोपीय साझा बाजार के देशों से भारत को उपलब्ध सुविधाएं

2465. श्री एस. सी. सामन्त : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूरोपियन साझा बाजार के देशों से भारत को कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिन पर वहां की नई घटनाओं का प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : ऐसा अनुमान है कि यह प्रश्न ब्रिटेन, डेनमार्क, नार्वे, तथा आयरलैंड गणराज्य को यूरोपीय साझा बाजार में नये सदस्यों के रूप में प्रविष्ट करके बाजार का विस्तार करने की प्रस्थापना से सम्बद्ध है। भारत को ब्रिटेन के बाजार में अधिमान्य टैरिफ तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त थीं, जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, यदि सम्बद्ध देशों द्वारा उपयुक्त संरक्षण प्रदान नहीं किये जायें। इस विस्तार के कारण अन्य गौण प्रभाव भी पड़ सकते हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार का दृष्टिकोण समय-समय पर लोक सभा में स्पष्ट किया जा चुका है।

अमरीका को खिलौना-हाथी और खिलौना-गधों का निर्यात

2466. **श्री राजदेव सिंह : क्या विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प वस्तुओं का व्यापार करने वाली एक अमरीकी एजेन्सी ने अमरीका को निर्यात किये जाने के लिए बड़ी संख्या में खिलौना-हाथियों और खिलौना गधों के लिए केरल हस्तशिल्प सहकारी एपेक्स सोसाइटी को क्रयादेश दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस क्रयादेश की मुख्य बातें क्या हैं और क्या यह इस वर्ष में अपने किस्म का पहला क्रयादेश है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी नहीं। फिर भी, केरल हस्तशिल्प सहकारी एपेक्स सोसाइटी ने एक गैर-सरकारी एजेंसी के द्वारा अमरीका को खिलौना-हाथियों तथा खिलौना-गधों के नमूने भेजे हैं। इन नमूनों के आधार पर इसे क्रयादेश मिलने की आशा है।

वनपरती रोड और कुरुमूर्ति स्टेशनों (दक्षिण मध्य रेलवे) के बीच एक मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

2467. **श्री पी. गंगादेव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 मार्च, 1972 को दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद द्रोणचलय मीटर गेज सेक्शन पर वनपरती रोड और कुरुमूर्ति स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के 9 डिब्बे पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी क्षति हुई है; और

(ग) क्या कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) इस दुर्घटना में ब्रेकबान सहित 12 माल डिब्बे पटरी से उतर गये।

(ख) रेल सम्पत्ति को लगभग 13,255 रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

(ग) रेलवे अधिकारियों की एक समिति द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गयी थी। उसकी रिपोर्ट का इन्तजार हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण

2468. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितने गांवों में बिजली लगाने का विचार है; और

(ख) फरवरी, 1972 के अन्त तक वस्तुतः कितने गांवों में बिजली लगाई गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). चौथी योजना के दौरान पंपों के उर्जन पर बल दिया जाना जारी है । ग्रामों का विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का एक आनुषांगिक भाग है । ग्राम विद्युतीकरण निगम के लिए, लगभग 444 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय से, जिसमें राज्य योजनाओं के लिए 294 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सेक्टर में 150 करोड़ रुपये शामिल हैं, चौथी योजना के दौरान 12.5 लाख सिंचाई पंप और 50000 ग्राम विद्युतीकृत होने की संभावना है । यदि अन्य वित्तपौषक संस्थाओं से और साधन उपलब्ध हो जाएं तो उम्मीद है कि और अधिक ग्रामों और पंपों का विद्युतीकरण किया जा सकता है और चौथी योजना के दौरान, कुल लगभग 75000 ग्रामों और 150 लाख पंपों के ऊर्जित होने की संभावना है । अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार फरवरी, 1972 के अन्त तक कुल 1,19,563 ग्राम विद्युतीकृत हुए हैं जिसमें 45,244 ग्राम चौथी योजना के आरम्भ होने के बाद विद्युतीकृत हुये हैं ।

Incidents of Wire Cutting in Jhansi Division

2469. SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of incidents of wire cutting, in Jhansi Division during the last six months;

(b) whether Government are aware that there is the hand of an organised gang behind this activity;

(c) if so, the steps taken by Government in this regard; and

(d) the number of persons arrested and convicted in this connection ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANU MANTHAIYA) : (a) 352.

(b) No.

(c) Does not arise. However cooperation meetings are held by RPF with the local police and patrolling by police is done in affected areas.

(d) No arrest has been made so far in this connection.

Incidents of thefts and murder in Trains on Jhansi-Kanpur Line

2470. SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased state :

(a) the number of incidents of thefts and murder in the trains on Jhansi-Kanpur line during the last six months;

(b) the value of property stolen and the number of persons killed during the period; and

(c) the number of persons arrested and convicted in this connection ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) 29 cases of thefts only.

(b) Rs. 17337.85. However, no person was killed during this period.

(c) 4 persons were arrested by Police. Of these two were convicted and the remaining two cases are pending trial.

Incidents of thefts in Jhansi-Itarsi and Bhusawal Passenger Trains

2471. SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that incidents of theft take place daily in Jhansi-Itarsi and Bhusawal passenger trains;

(b) whether such incidents take place particularly at night between Bina and Vidisha;

(c) if so, the number of thefts committed during the last six months and the amount of goods stolen; and

(d) the number of persons arrested and convicted in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) No.

(b) A few cases have been reported between Bina and Vidisha.

(c) No. of thefts during the last 6 months : 93
Amount of goods stolen : Rs. 58,650/- (approx.)

(d) No. of persons arrested : 12
No. of persons convicted : 5

अन्य देशों को इंजीनियरी की तकनीकी जानकारी देना

2472. **श्री एन. ई. होरो** : क्या **विदेश व्यारार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य देशों की इंजीनियरी की तकनीकी जानकारी देने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

माल की हानि के कारण दण्डित रेल-कर्मचारी

2473. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में माल की हानि के कारण जोन-वार कितने रेल कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया और दण्ड दिया गया ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जूनागढ़ जिले में मालगाम ग्राम में एक नए रेलवे स्टेशन का निर्माण

2474. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री वेकरिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जूनागढ़ जिले में मालगाम ग्राम में एक नये रेलवे स्टेशन का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). बांटवा और सराडिया स्टेशनों के बीच 'कोटनाथ रोड' के नाम से ठेकेदार द्वारा परिचालित एक गाड़ी-हाल्ट खोलने का प्रस्ताव है। स्टेशन के शीघ्र ही खुल जाने की संभावना है।

डिवीजनल सुपरिन्टेडेंट मुरादाबाद के विरुद्ध काले झंडों से प्रदर्शन

*2475. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन ने डिवीजन सुपरिन्टेडेंट, मुरादाबाद के विरुद्ध काले झंडों से प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा।

(ख) मुरादाबाद के मंडल अधीक्षक द्वारा अपनायी गयी कथित श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में।

Trunk route allowance to Guard and Drivers of Rajdhani Express

2476. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(i) whether any trunk route allowance is being paid to Guards and Drivers of Rajdhani Express ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (i) No trunk route allowance is paid to the Guards and Drivers of Rajdhani Express.

Revenues earned from Indore Railway Station

2477. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the revenue earned by Government from Indore Railway Station during the financial year 1971-72; and

(b) the expenditure incurred by Government on the maintenance and repairs of the Station during the period ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) The earnings from originating traffic in passengers, other coaching and goods at Indore Station during the year 1971-72, were of the order of Rs. 170.63 lakhs.

(b) Rs. 37,000/-

फलों का निर्यात

2478. **श्री शिवकुमार शास्त्री** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से फल विदेशों को निर्यात किए गये और उन देशों के नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जानकारी निम्न प्रकार है :

संतरे : बहरीन द्वीप समूह, ईरान, कुवैत, नेपाल, कतार तथा स्विटजरलैंड ।

नींबू तथा लाइम : अफगानिस्तान, हांगकांग, कुवैत, नेपाल, कतार, स्विटज़रलैंड तथा अमरीका ।

अंगूर : बहरीन द्वीप समूह ।

अन्य फल बहरीन द्वीप समूह, नेपाल तथा कतार ।

ताजे केले आबू धाबी, बहरीन द्वीप समूह, दुबई, ईरान, कुवैत, नेपाल, कतार तथा स्विटज़रलैंड ।

ताजे सेब : नेपाल ।

ताजे अंगूर बहरीन द्वीप समूह, कनाडा, दुबई, कुवैत, नेपाल तथा कतार ।

खूबानी कुवैत ।

सैपोटा बहरीन द्वीप समूह, कुवैत, कतार, स्विटज़रलैंड तथा इंगलैंड ।

अन्य गुठली वाले फल : बहरीन द्वीप समूह, नेपाल तथा इंग्लैंड ।

आम : अफगानिस्तान, बहरीन द्वीप समूह, बेल्जियम, डेनमार्क, दुबई, इथोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, हांगकांग, ईरान, इटली, कुवैत, लैबनान, मलेशिया, मस्कट, नेपाल, नीदरलैंड्स, पोलैंड, कतार, दक्षिण, यमन, सिंगापुर का जनवादी गणराज्य, सोमालिया, स्वीडन, स्विटजरलैंड, इंगलैंड, ।

अनन्नास : वहरीन द्वीप समूह, कुवैत, कतार, इंग्लैंड ।

अन्य उप्प कटिवंधीय फल : आस्ट्रेलिया, बहरीन द्वीप समूह, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, कुवैत, स्विटज़रलैंड, इंग्लैंड, अमरीका ।

अनार : हांगकांग, नेपाल, कतार तथा सिंगापुर ।

अन्य ताजे फल : अफगानिस्तान, बहरीन द्वीप समूह, फिजी द्वीप समूह, फ्रांस, कुवैत, नेपाल, कतार, स्विटज़रलैंड तथा इंगलैंड ।

तामिल नाडू में रेलवे के नये ऊपरी/नीचे के पुलों का निर्माण

2479. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तामिलनाडू में रेलवे के नये ऊपरी/नीचे के पुल बनाने सम्बन्धी व्यय का कुछ भाग अदा करने के लिये रेलवे सुरक्षा निर्माण निधि में से कुछ सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो सहायता की राशि कितनी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) तामिलनाडू के लिए रेल संरक्षा निर्माण कार्य निधि में 59,82 लाख रुपये की रकम उपलब्ध है ।

(ग) अनुमोदित निर्माण कार्यों की लागत के अपने हिस्से को वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त रकम निकाली जा सकती है ।

विभिन्न रेलों में भ्रष्टाचार का उन्मूलन और उनकी सेवाओं में सुधार

2480. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की विभिन्न रेलों में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने और उनकी सेवाओं में सुधार लाने सम्बन्धी अभियान के अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) इसमें और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अच्छे परिणाम निकले हैं । जहां तक सवारी गाड़ियों का संबंध है, जून 1971 में चलाये गये समयपालन अभियान के फलस्वरूप समयपालन में चतुर्दिक सुधार हुआ है ।

(ख) भ्रष्टाचार दूर करने और गाड़ियों के संचालन में और अधिक सुधार करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

बागमती नदी (बिहार) द्वारा हुई क्षति

2481. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धौंस-बागमती में आई बाढ़ों से बिहार में दरभंगा जिले के माधबपुर, बेऊपट्टी, बिस्फी, जेली, सिंधबाड़ा और दरभंगा खण्डों को भारी क्षति पहुंचती रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नदी पर बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उच्च बाढ़ों के समय दरभंगा-बागमती की सहायक नदी धौंस से उसके दायें तट के निम्नवर्ती क्षेत्र जल प्लावित हो जाते हैं। इस समय नदी पर बाढ़ सुरक्षा अथवा सिंचाई स्कीम के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य व्यापार निगम का गेरज उपकरणों के निर्यात के लिये रूस के साथ करार

2483. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने गेरज उपकरणों के निर्यात के लिये रूस के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात किये जाने वाले उपकरणों का ब्यौरा क्या है और उसका कुल मूल्य क्या है; और

(ग) उपकरणों की पहली खेप कब तक भेजी जायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 87.89 लाख रु० जहाज पर मूल्य के पेट्रोल डिस्पेंसिंग पम्प, स्प्रे गन तथा होइसट्स हाइड्रालिक।

(ग) पहली खेप 1972 की तीसरी तिमाही में भेजी जायेगी।

रेलवे सुरक्षा निर्माण निधि में से पश्चिम बंगाल को दी गई सहायता

2484. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये उपरी/नीचे के रेलवे पुल बनाने सम्बन्धी व्यय का कुछ भाग अदा करने के लिये राज्य को रेलवे सुरक्षा निर्माण निधि में कुछ सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) पश्चिम बंगाल में अत्याधिक भीड़ वाले रेलवे फाटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए इस राज्य को कितनी सहायता दी जायेगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल के लिए रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में 59.51 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है ।

(ग) उपर्युक्त धनराशि, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निर्माण-कार्यों की लागत का अपना हिस्सा चुकाने के लिए निकाली जा सकती है ।

मसालों का निर्यात

2485. **श्री रायबहादुर सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मसाले विदेशों में अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो मसालों का कितना निर्यात होता है और गत 6 महीनों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जून-नवम्बर 1971 के दौरान विदेशों को 29.557 मी० टन मसालों का निर्यात किया गया और 15·28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ।

आसाम मेल में नई दिल्ली और बरौनी के बीच भोजन-यान की व्यवस्था

2486. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम मेल में नई दिल्ली और बरौनी के बीच भोजन-यान की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो भोजन-यान कब से लगाया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री के. हनुमन्तेगा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

काहिरा में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में बिक्री

2487. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काहिरा में हाल ही में लगे अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भारतीय पंडाल में कुल कितनी बिक्री हुई थी;

(ख) क्या वहां पर भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिये कुल क्रयादेश भी बुक किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके अधीन कितना माल निर्यात करने का प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) काहिरा में अन्तर्राष्ट्रीय मेले के चलने के दौरान माल बेचने की अनुमति नहीं थी। अतः मेले की समाप्ति के बाद स्मृति-वस्तुओं की 9,000 रु० से अधिक की सांकेतिक बिक्री की गई थी।

(ख) और (ग). वेल्डिंग इलेक्ट्रोड़ों के लिये 3.65 लाख रु० का सौदा तय किया जा चुके है और भारतीय पार्टियों के नाम में साख-पत्र खोले जा चुके हैं । व्यापार संवर्धन एक दीर्घावधि प्रक्रिया है और कुछ समय बीतने पर ही उसके परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है। तथापि, कुछ मदों के निर्यात के लिए बातचीत चल चल रही है। उनमें से प्रमुख मदें ये हैं :—खरादे, गाड़ियों के सहायक पुर्जे तथा प्रक्रिया नियन्त्रयंत्र आदि।

Joint Enterprises in Foreign Countries

2488. SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the number of proposals received for joint enterprises in foreign countries since June 1971 and the number of proposals approved; and

(b) the number of proposals rejected and the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) and (b). Twenty-two proposals have been received since June, 1971 for setting up joint ventures abroad. Of these five have been approved and the remaining are in various stages of consideration. None of these proposals have been rejected.

निर्यात में वृद्धि की दर का कम हो जाना

2489. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक वर्ष-वार भारत ने कितने मूल्य का निर्यात किया;

(ख) वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक प्रत्येक वर्ष निर्यात में वृद्धि की दर क्या थी;

(ग) क्या उनका ध्यान दिनांक 29 फरवरी, 1972 के **'स्टेट्समैन'** (कलकत्ता संस्करण) में "निर्यात वृद्धि की दर में कमी" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) :

(क) तथा (ख) : भारतीय निर्यातों के मूल्य

(करोड़ रुपये)

वर्ष	**मूल्य**	**पूर्व वर्ष की उसी अवधि के मुकाबले में वृद्धि**
1969-70*	1413.28	+4.1 प्रतिशत
1970-71	1535.16	+8.6 '
अप्रैल 70-जनवरी 71	1293.27	+8.9 "
अप्रैल 71-जनवरी 72	1337.92	+3.5 "

(ग) जी हां।

(घ) यह सच है कि वाणिज्यिक जानकारी अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 1970-71 की तुलना म 1971-72 में निर्यात की वृद्धि की दर गिरी है। तथापि, नवम्बर 1970 में निर्यात आंकड़ों के संकलन के तरीके में परिवर्तन होने के कारण 1970-71 के आंकड़े न तो पिछले वर्ष के आंकड़ों से मेल खा सकते हैं और न अगले वर्ष के आंकड़ों से। विदेश व्यापार मंत्री 1970-71 के निर्यात आंकड़ों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने वाला एक विवरण पहले ही 14-3-72 को सभा पटल पर रख चुके हैं।

* नवम्बर 70-मार्च 71 के निर्यात आंकड़े, अवधि के दौरान जो विवरणियां कम प्राप्त हुई तथा जिन की प्रविष्टि नहीं की गई उनके बारे में समायोजन करने के बाद पोत-लदान विल की मूल प्रति पर आधारित है। जबकि अप्रैल-अक्तूबर 70 तक के निर्यात आंकड़े अन्तिम रूप से पास किए हुए पोतलदान बिलो पर आधारित थे। अतः 1970-71 के निर्यात आंकड़ों की विगत अथवा बाद के वर्षों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती।

पश्चिम बंगाल में ग्राम्य विद्युतीकरण

2490. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 1969-70 से 1971-72 तक तथा वर्ष-वार कुल कितने सिंचाई पम्पों को बिजली दी गई; और ग्राम विद्युतीकरण के जिलावार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पश्चिम बंगाल में जिलावार ग्राम विद्युतीकरण की योजनाएं क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1969-70 से 1971-72 तक पश्चिम बंगाल में विद्युतीकृत सिंचाई पंपों और ग्रामों की संख्या जिले-वार नीचे दी जाती है :—

क्रम सं०	जिले का नाम	1969-70		1970-71		1971-फरवरी 72	
		ग्राम	पंप	ग्राम	पंप	ग्राम	पंप
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बांकुरा	16	9	11	—	38	—
2.	बीरभूम	7	2	8	—	18	5
3.	बर्दवान	38	8	68	7	49	30
4.	कूचबिहार	—	—	—	—	1	—
5.	दार्जलिंग	—	—	—	—	3	—
6.	हुगली	45	—	55	—	34	21
7.	हावड़ा	25	—	15	—	22	9
8.	जलपाईगुड़ी	1	—	—	—	4	—
9.	मालदा	7	5	8	12	—	—
10.	मिदनापुर	22	21	52	7	37	15
11.	मुर्शिदाबाद	16	6	18	17	15	—
12.	नदिया	49	78	18	34	14	10
13.	24-परगना	20	56	34	2	73	6
14.	पुरूलिया	—	—	—	—	4	—
15.	पश्चिम दिनाजपुर	—	—	—	—	—	—
	कुल	246	185	287	79	312	96

(ख) चौथी योजना के दौरान जिन ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है उनका जिले-वार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

1.	बांकुरा	466
2.	बीरभूम	573
3.	बर्दवान	964
4.	कूचबिहार	410
5.	दार्जिलिंग	59
6.	हुगली	1134
7.	हावड़ा	374
8.	जलपाईगुड़ी	31
9.	मालदा	658
10.	मिदनापुर	1663
11.	मुर्शिदावाद	616
12.	नदिया	430
13.	24-परगना	1369
14.	पुरूलिया	698
15.	पश्जिम दिनाजपुर	555
	कुल	10000

केन्द्रीय सेक्टर में ग्राम विद्युतीकरण निगम पश्चिम बंगाल को ग्राम विद्युतीकरण के लिए काफी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। चौथी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित 10,000 ग्रामों के सम्बन्ध में निगम ने अभी तक 16 स्कीमें स्वीकार की हैं, जिनमें 3387 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए 1186.68 रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है।

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार

2491. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1969 से 1971 तक, प्रत्येक वर्ष, भारत ने कितने मूल्य की वस्तुयें उत्तर और दक्षिण कोरिया को निर्यात की और वहां से कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया;

(ख) भारत ने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से 1969 से 1971 तक वर्ष-वार और वस्तुवार कितने मूल्य का और कितना निर्यात/आयात किया; और

(ग) उत्तर कोरिया के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने के लिये सरकार ने गत तीन वर्षों में क्या कार्यवाही की ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). कोरिया गणराज्य के सम्बन्ध में व्यापार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

कोरिया गणराज्य को भारत के निर्यात

(मूल्य लाख रुपयों में)

क्रमांक	वस्तुएं	इकाई	1968-69		1969-70		1970-71	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सीरा	हजार टन	—	—	—	—	—	—
2.	नमक	,,	—	—	20	6	21	6
3.	अभ्रक	हजार कि०ग्रा०	2	1	20	4	13	2
4.	प्राकृतिक गोंद, रालें, बालसम तथा लाख	,,	63	2	62	2	9	0.4
5.	लोहा, तथा स्पात स्क्रेप	हजार टन	1	2	6	15	—	—
6.	मानव केश, अपरिष्कृत तथा छटन	हजार कि.ग्रा.	331	421	189	183	109	85
7.	बकरी के बाल	मूल्य	—	—	—	1	—	—
8.	काजू छिलके का तेल	हजार कि.ग्रा.	76	1	60	1	118	2
9.	विद्युत मशीनों के अलावा अन्य मशीनें	मूल्य	—	2	—	1	—	34
10.	नेप्था सोलवेंट कच्चा	लाख कि.ग्रा.	209	25	—	—	—	—
11.	पटसन निर्मित वस्तुएं	हजार टन	—	3	0·6	19	0.3	11
12.	लोहा तथा इस्पात	,,	21	66	34	292	—	—
13.	विद्युत मशीनें	मूल्य	—	नगण्य	—	1	—	0.4
14.	परिवहन उपस्कर	,,	—	513	—	नगण्य	—	0.4
15.	विग तथा अन्य चीजें बनाने के लिए मानव केश, ऊन आदि	,,	—	7	—	57	—	37
	कुल निर्यात (अन्य मदों सहित)	मूल्य	—	1046	—	584	—	201

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			कोरिया गणराज्य से भारत के आयात					
1.	प्राकृतिक ग्रेंफाईट	हजार कि.ग्रा.	196	1	232	1	540	4
2.	रेशम	,,	9	13	29	35	25	39
3.	टगस्टन अयस्क तथा सांद्र	,,	62	14	58	16	—	—
4.	एन्टीमोनी ग्रयस्क	,,	10	3	—	—	—	—
5.	रबड़ की बनी गर्भ निरोधक वस्तुएं (मेल कन्डोम)	मूल्य	—	8	—	6	—	—
6.	जिंक	हजार कि.ग्रा.	369	9	81	2	101	3
	कुल ग्रायात (ग्रन्य मदों सहित)	मूल्य	—	49	—	61	—	81

(ii) कोरिया लोकतंत्रीय गणराज्य के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 31 दिसम्बर, 1970 तक के लिए वैध एक व्यापार तथा भुगतान करार पर 9 दिसम्बर, 1968 को हस्ताक्षर किये गये थे, जिसकी अवधि को जून, 1970 में भारतीय व्यापार प्रतिनिधि-मंडल की यांग-यांग की यात्रा के दौरान 31 दिसम्बर, 1972 तक ग्रौर बढ़ाया गया था। करार के साथ संलग्न ग्रनुसूचियों में दोनों देशों के बीच ग्रादान-प्रदान हेतु उपलब्ध वस्तुएं दी गई हैं।

कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य से एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ 7 से 21 फरवरी, 1972 के बीच नई दिल्ली में व्यापार वार्ताएं की गई। इन विचार-विमर्शों के दौरान दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हो गये हैं कि 1972 में व्यापार के स्तर को और उठाया जाए।

पटसन और चाय के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा

2493. **श्री जी. वाई कृष्णन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चाय ग्रौर पटसन के निर्यात से सरकार ने कुल कितनी राशि की बिदेशी मुद्रा ग्रर्जित की; ग्रौर

(ख) क्या चाय और पटसन के निर्यात व्यापार में सुधार लाने के लिए सरकार के पास कोई नई योजना है ग्रौर यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) चाय तथा पटसन के निर्यातों का मूल्य इस प्रकार था :

	(करोड़ रुपयों में)	
	चाय	पटसन माल
1969-70	124.50	206.10
1970-71	146.65	189.92
1971-72 (फरवरी 1972 तक)	153.54	273.36

(ख) चाय तथा पटसन माल का निर्यात बढ़ाने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं ।

पूर्वोत्तर रेलवे के मौकामेह घाट पर बाटा शू कम्पनी द्वारा रेलवे की भूमि पर कब्जा करना

2494. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मौकामेह घाट पूर्वोत्तर रेलवे में बाटा शू कम्पनी ने रेलवे की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री० के० हनुमंतैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मोकामेह घाट, पूर्वोत्तर रेलवे में हरिजनों को रेलवे की भूमि आवंटित करना

2495. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1961 में पूर्वोत्तर रेलबे मोकमेह घाट में सम्बन्धित अधिकारियों ने हरिजनों को रेलवे की भूमि आबंटित की थी; और

(ख) यदि हां, तो भूमि किन शर्तों पर दी गई थी ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तैया) ; (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

क्विलोन और नीडाकारा के बीच रेल सम्पर्क

2496. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्विलोन जंक्शन और नीडाकारा पतन को रेल द्वारा मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तैया) : जी नहीं।

रेलवे में कथित भ्रष्टाचार

2497. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पटना के दिनांक 8 मार्च, 1972 के 'सर्चलाइट' में 'ग्रोइंग करप्शन इन रेलवे' शीर्षक में छपे एक पत्र की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के॰ हनुमन्तैया) : (क) उल्लिखित पत्र का सारांश रेल मंत्रालय को मिल गया है।

(ख) भ्रष्टाचार दूर करने के लिए यथावश्यक कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी की जाती रहेगी।

स्टेशन मास्टरों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति

2498. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ ने स्थानान्तरण के सम्बन्ध मे एक निश्चित नीति बनाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति, धनवाद (पूर्व रेलवे) से स्कूटर-ऋण घोटाले के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

2499. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल रेलवे समन्वय समिति धनबाद (पूर्व रेलवे) ने स्कूटर ऋण देने में होने वाले घोटाले के सम्बन्ध में 19 फरवरी, 1972 को एक अभ्यावेदन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) धनबाद मंडल के रेल कर्मचारियों के लिए स्कूटर ऋण की मंजूरी के सम्बन्ध में अनाचार और भ्रष्टाचार के अभियोग लगाये गये हैं। इसकी जांच की जा रही है।

डिवीजनल रेल कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद (पूर्व रेलवे) का भ्रष्टार समाप्त करने के बारे में ज्ञापन

2500. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 25 फरवरी, 1972 के 'सर्चलाट' में छपे समाचार के अनुसार डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति, पूर्व रेलवे, धनबाद में रेलवे में भष्टाचार समाप्त करने के लिए उन्हें 15 सूत्रीय सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या उक्त समिति ने जनशक्ति के दुरुपयोग, बिना टिकट यात्रा आदि के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के विशिष्ट मामलों का उल्लेख भी किया है; और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मन्त्री (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) सुझावों की जांच की जा रही है।

(ग) श्रम शक्ति के दुरुपयोग के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट आरोप की जांच-पड़ताल की जा रही है।

लोकोशैड, धनबाद में काम करने वाले संगचल कर्मचारी (रनिंग स्टाफ)

2501. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकोशैड, धनबाद के संगचल कर्मचारियों (रनिंग स्टाफ) का उपयोग नियमित रूप से बुकिंग क्लर्कों के तौर पर या वहां बिशेष ड्यूटी पर लगा कर किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और गत छः मास में उन्हें कितना संगचल भत्ता दिया गया ?

रेल मन्त्री (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) रनिंग कर्मचारियों को नियमित रूप से बुकिंग क्लर्क के रूप में या विशेष ड्यूटी पर नहीं लगाया जाता, लेकिन आपात स्थितियों में उन्हें ऐसी स्थिर ड्यूटी पर यदा-कदा लगा दिया जाता है ।

(ख) पिछले छः महीने के दौरान इस प्रकार ड्यूटी पर लगाये गये कर्मचारियों की संख्या और उन्हें दिये गये भत्ते के बारे में सूचना अभिलेखों से इकट्ठी करनी पड़ेगी । इसलिए, उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

2502. **श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के विचाराधीन पड़ी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं को शीघ्रता से चालू करने हेतु सहायता की मंजूरी शीघ्र देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में ग्रामों और पंपों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम को दो स्कीमें प्राप्त हुई थीं । 31 ग्रामो और 2082 पंपों के विद्युतीकरण की एक स्कीम, जिसमें लगभग 80 लाख रुपये की ऋण-सहायता की परिकल्पना की गई है, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा पहले ही स्वीकृत हो चुकी है । चित्तूर जिले में लगभग 72 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 42 ग्रामों और 2300 पंपों के विद्युतीकरण से सम्बन्धित दूसरी स्कीम ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को, विद्युत की यथार्थिक लगात के आधार पर पुनरीक्षित करने के लिए तथा परियोजना के कार्यान्वियन के लिये पूंजीगत परिव्यय के उचित चरण बनाने के लिए वापिस कर दी गई है । राज्य विद्युत बोर्ड से स्कीम के प्राप्त होने पर, निगम इस पर आगे की कार्यवाही करेगा ।

Detention of Passenger trains between Itarsi and Bhusawal at intermediate Stations for long hours

2503. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether passenger trains between Itarsi and Bhusawal are detained at intermediate Stations for almost two hourse;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to remedy the situation keeping in view the inconvenience being caused to passengers thereby ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) & (b). Yes, No. 357 Bhusaval-Itarsi Passenger stops at Khandwa in the night hours from 11.00 P.M. to 3.10 A.M. in order to pick up the timings suited for passengers of Khandwa-Itarsi section.

(c) Does not arise.

Export of 'Kosa' cloth from Madhya Pradesh

2504. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the export of 'Kosa' cloth from Madhya Pradesh to various countries has registered any increase; and

(b) if so, the exent thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) & (b). Separate statistics of exports of kosa cloth produced in Madhya Pradesh are not maintained. The overall export of kosa cloth from India rose from Rs. 1.20 crores in 1970-71 to Rs. 1.30 crores in 1971-72.

Wagons Demanded by Traders on Central Railway

2505. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of wagons requisitioned from the Central Railway by traders and other business communities during the last three years and the number of wagons actually supplied to them; and

(b) whether the supply was made in time and if not, the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) The number of wagons requisitioned by traders on Central Railway and supplied during the last three years were as under :—

	No. of wagons *requisitioned*	No. of wagons *supplied*
1969-70	840916	823860
1970-71	839938	804288
1971-72	934291	834600

(b) Wagon supply position during 1969-70 and 1970-71 was quite satisfactory. Although more wagons were supplied in 1971-72 in comparison to earlier years, the outstanding demands were more; one of the reasons being that the number of indents registered by traders were highly inflated as the Railways allowed free registration of indents without any ceiling limits. With the reduction of the tempo of various special moves, all-out efforts are being made to meet all the pending demands.

Wagons for Banana Traders on Central Railway

2506. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether requisitions for supply of wagons from Banana Traders on Central Railway are attended to promptly; and

(b) if not, the steps proposed to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes.

(b) Does not arise.

Project on Tapti River, near Navtha Village of Burahanpur (M.P.)

2507. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Government have accorded sanction to the Tapti River Project near Navtha village of Burahanpur Tehsil Madhya Pradesh;

(b) if so, the total expenditure to be incurred thereon and the acreage of land likely to be irrigated thereby; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI B. N. KUREEL) : (a) to (c). The Government of Madhya Pradesh have reported that the proposed dam near Nawtha is part of Upper Tapi Stage II Project which is under survey. The project features will be finalised after the surveys are over. The question of acceptance of the project will arise only after the project report and estimates are sent to the Centre.

रेलवे बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों और अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति

2508. **श्री के. सूर्यनारायण** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के कार्यालय में उप-निदेशक, संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त सदस्यों के पद पर नियुक्ति किस प्रकार की जाती है तथा उनका कार्यकाल कितना होता है ;

(ख) क्या ये नियुक्तियां सम्बन्धित सेवा से ही की जाती हैं अथवा कुछ पदों को विशेषकर प्रशासन विभाग में, विभिन्न रेलवे सेवाओं के बीच अदला-बदला जाता है;

(ग) इन पदों पर काम कर रहे वर्तमान कर्मचारियों का कार्यकाल कब समाप्त होगा; और

(घ) क्या इनमें से किसी के कार्यकाल को बढ़ाने का विचार है यदि हां, तो उसका व्योरा और कारण क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री के. हनुमन्तेया) : (क) और (ख). अपर सदस्यों, संयुक्त निदेशकों और उप निदेशकों के पद मुख्यतः सम्बन्धित रेल सेवाओं से लिये गये उपयुक्त अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। संयुक्त निदेशकों और उप निदेशकों के कुछ पद रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों में से भी भरे गये हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा / भारतीय पुलिस सेवा / राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को भी सतर्कता और सुरक्षा निदेशालयों के कुछ पदों पर नियुक्त किया जाता है।

विभिन्न रेल सेवाओं से लिये गए अधिकारियों की पदावधि इस प्रकार है :—

अतिरिक्त सदस्य	—5 वर्ष
संयुक्त निदेशक) उप निदेशक)	कोई पदावधि निर्धारित नहीं है, परन्तु 4 वर्षों के बाद, रेल अधिकारियों को रेलवे पर पुनः स्थानान्तरित करने पर विचार किया जाता है।

कुछ विशेष मामलों में इन अवधियों को प्रशासनिक हित में घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय प्रशासकीय सेवा / भारतीय पुलिस सेवा / राज्य सिविल सेवा से लिये गये अधिकारियों की पदावधि पांच वर्ष होती है।

(ग) और (घ). एक सूची संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गयी / देखिये संख्या एल० टी० 1711/72]

अधिकारियों की पदावधि बढ़ाने अथबा उनके स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में प्रत्येक मामले में अलग से उपयुक्त समय पर विचार किया जाता है।

आप्ता और मैलौर के बीच रेल लाइन का सर्वेक्षण

2509. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आप्ता और मैलोर के बीच पश्चिमी तट पर ऐक रेलवे लाइन बिछाने का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो रेल मार्ग पर कितना खर्च आयेगा और उसका रूट क्या होगा; और

(ग) लाइन बिछाने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सर्वेक्षण पूरा हो जाने और रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद ही इनका पता चल सकेगा।

Introduction of another train via Bulandshahar and Khurja

2510. SHRI NARENDRA SINGH BISHT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item appearing in the daily "*Hindustan*" of 2nd March, 1972 that sanction has been granted to introduce a through train via Bulandshahar and Khurja from April;

(b) if so, the date from which the said train will be introduced;

(c) whether Hapur Shuttle is also proposed to be converted into Bulandshahar Shuttle; and

(d) if so, when ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) No. However, such a news item appeared in the *Nav Barat Times* dated 6-3-1972.

(b) There is no proposal at present to introduce a through train between Delhi and Howrah via Bulandshahar.

(c) No.

(d) Does not arise.

Supply of Load Vans for Neemuch and Jawad Stations (Ratlam Division, Western Railway)

2511. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the load vans are not supplied at Neemuch and Jawad Stations of Ratlam Division of Western Railway in accordance with the demand for loose load vans;

(b) whether the attention of the concerned officers has been drawn to this fact by the traders of the said places; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) to (c). Presumably the Honourable Member is referring to supply of wagons at Neemuch and Jawad Road stations. Loading at Neemuch and Jawad Road stations during the last three months were as under :—

	Month	*Loading*
Neemuch	Jan/72	214 wagons
	Feb/72	167 ,,
	Mar/72	181 ,,
Jawad Road	Jan/72	15 ,,
	Feb/72	6 ,,
	Mar/72	18 ,,

The number of indents registered by traders at these stations was highly inflated as the Railways allow free registration of indents without any ceiling. Between 30th and 31st March 1972, 200 indents were cancelled at Neemuch and 10 indents at Jawad Road station. The pending indents at these stations were registered only in February.

All out efforts are being made to meet the pending demands.

Export of Chillies, Onions and Spices to Nepal, Ceylon and Japan

2512. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state the value of chillies, onions and other dry spices exported to Nepal, Ceylon and Japan during the last three years ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : A statement showing value of exports of chillies, onions and other spices to Japan, Ceylon and Nepal during 1968-69, 1969-70 and 1970-71 is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See* No. L.T. 1712/72]

Expansion of Diesel Shed, Ratlam (Western Railway)

2513. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the extent to which the work relating to the expansion of 'Diesel Shed' at Ratlam in the Ratlam Division of Western Railway has been completed so far;

(b) the time by which arrangements for the maintenance of the prescribed number of diesel engines will be completed; and

(c) the estimated expenditure in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) The estimate for this work has recently been sanctioned and the work will be taken up shortly.

(b) The work is expected to be completed by 1975 subject to availability of steel.

(c) Rs. 39.42 lakhs approximately.

Assistance given to Madhya Pradesh for Power Projects

2514. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the amount proposed to be given by the Central Government to Madhya Pradesh for power projects in the State during the Fourth Five Year Plan; and

(b) the amount actually given so far ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION & POWER (SHRI B. N. KUREEL) : (a) Since the commencement of the Fourth Plan, Central assistance to 'State Plan' Scheme is being given in the form of block loans and grants towards their overall plan expenditure and not for any specific projects. The total assistance allotted to Madhya Pradesh during Fourth Plan is Rs. 262 crores.

(b) The central assistance actually made to end of 1971-72 is Rs. 145.33 crores.

Closure of Mills in Madhya Pradesh

2515. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the number of textile mills closed down in Madhya Pradesh during 1970-71 and by the end of 1971;

(b) the reasons for their closure; and

(c) the number of mills re-opened and what action is being taken in regard to the remaining ones ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) to (c). Two cotton textile mills which closed down due to financial difficulties during the year 1970-71 in Madhya Peadesh have restarted working. No cotton textile mill was lying closed in the State at the end of 1971.

जुकेही और पाकाडिया रोड स्टेशनों, (मध्य रेलवे) के बीच एक मालगाड़ी और एक खड़े माल डिब्बे की टक्कर

2516. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 मार्च, 1972 को एक मालगाड़ी और एक खड़े डिब्बे की टक्कर होने से जबलपुर-सतना सेक्सन के जुकेही और पकाड़िया रोड स्टेशनों के बीच ग्यारह डिब्बे और एक स्टीम इंजन पटरी से उतर गया;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित हानि कितनी हुई; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तेया) : (क) जी हां। एक मालगाड़ी अलग खड़े हुये एक माल-डिब्बे से टकरा गयी थी।

(ख) रेल सम्पत्ति को लगभग 1,43,522 रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

(ग) जांच समिति की रिपोर्ट का इन्तजार है। प्रत्यक्षतः यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई लगती है।

टूंडला के पार्सल लाने ले जाने वाले ठेकेदार से प्राप्त अभ्यावेदन

2517. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूंडला पार्सल के लाने ले जाने वाले ठेकेदार ने एक अभ्यावेदन दिया है और क्या डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, इलाहाबाद ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है;

(ख) क्या टूंडला के स्टेशन कर्मचारियों की सहायता से ठेकेदार ने स्टेशन रिकार्ड में कुछ हेरफेर की है, और जांच अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्राइवेट डाक्टरी प्रमाण-पत्रों का दिया जाना

2518. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1971 से मार्च, 1972 की अवधि के दौरान इलाहाबाद डिवीजन के वाणिज्यिक अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के कतिपय प्राइवेट डाक्टरी प्रमाण-पत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अस्वीकृत किये गये मामलों की संख्या क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Extension of Bakhatiarpur and Rajgir Railway Line upto Gaya Bodh Gaya

2519. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the railway line between Bakhatiarpur and Rajgir of the Eastern Railway is running at a loss;

(b) whether in order to make up this loss, a proposal for extending this line upto Gaya and Bodh Gaya is under consideration of the Railway Department; and

(c) if so, the time by which the proposal will be finalised ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes, if dividend liability is also taken into account.

(b) No.

(c) Does not arise.

Flood Control Measures for Bihar State

2520. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Govrrnment have formulated any concrete scheme to protect Bihar State from devastation caused by floods every year; and

(b) if so, the salient features thereof and the time by which it will be completed ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI B. N. KUREEL) : (a)&(b). The Government of Bihar have stated that they have taken up the preparation of a comprehensive plan for flood control in the State taking into account the experience of floods and damage caused in the last few years. The State Government have also implemented flood protection measures consisting of embankments, drainage channels and town protection works in the Five Year Plans. The progress reported so far include construction of 1772 Km of embankments, 355 Km of drainage channels and six town protection schemes. These have benefitted about 12.4 lakh ha. Further works are being carried out of which the important is the Bagmati Embankment Scheme estimated to

cost Rs. 6.54 crores.

Taking into occount the damage caused by floods in the Ganga and its tributaries in recent years and particularly in 1971, it has been decided to implement the following schemes in Bihar on a priority basis :

		Estd. cost *Rs. crores*
1.	Construction of an embankment on the right bank of Ganga from Buxar to Koilwar.	4.0
2.	Raising and strengthening of existing embankment along Ganga.	4.0
3.	Construction of embankments and protection works on Gandak.	3.0
4.	Embankments on the right side of Pun Pun river.	3.0
5.	Embankments on both banks of the Sone dowstream of Sone Barrage.	4.0
6.	Mahananda Embankment Scheme and Kankai river scheme.	9.0

All the important schemes indicated above are expected to be completed in the Fifth Plan period.

Rest Rooms for Tickets Checking Staff at Delhi and New Delhi Stations

2521. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is a shortage of Rest Rooms for Ticket Checking staff at Delhi and New Delhi Railway Stations; and

(b) whether Government are aware that the Rest Rooms for the Ticket Checking staff do not have adequate amenities ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) & (b). Yes. Provision of additional resting facilities for ticket checking staff at Delhi and New Delhi stations is being programmed

---

Development and Export of Madhubani Art

2522. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have taken any concrete steps for development and export of Madhubani Art;

(b) if so, an outline thereof; and

(c) whether there is a great demand for Madhubani Art in foreign countries ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India have taken a number of steps for development and export of Madhubani Art. The important among them are as follows :—

(i) Exhibitions have been organised in some of the departmental stores in Europe for sales of Madhubani paintings;

(ii) Special display has been arranged for Madhubani paintings in SONA shop of the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India at Paris;

(iii) Wide publicity of Madhubani Art was given by participation in Expo '67 at Montreal and Expo' 70 at Osaka;

(iv) To give wide publicity to Madhubani Art, a brochure on "Folk Art of Madhubani" has been prepared;

(v) A Madhubani painting has been reproduced on a calendar brought out by the All India Handicrafts Board for 1972 and it has been distributed in several foreign countries; and

(vi) The Royal Ontario Museum, Toronto (Canada) is organising a special exhibition of Mithila Paintings. This will give further impetus to the export of this art.

(c) Yes, Sir. Ther e is a demand for Madhubani Art in foreign countries specially in Canada, U. K., France, Holland, Sweden, Switzerland and USA.

दक्षिण रेलवे में एक डिवीजन से दूसरे में वायरलैस आपरेटरों का स्थानान्तरण

2523. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 से दक्षिण रेलवे में वायरलैस आप्रेटरों के कुल कितने पद रिक्त हुए;

(ख) इन पदों पर कितने सिगनेलरों की पदोन्नति की गई; और

(ग) क्या भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध के कारण कुछ पद अभी तक रिक्त हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) आठ ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) इस कोटि में प्रत्याशित अतिरिक्त कर्मचारियों के कारण ये रिक्त स्थान नहीं भरे गये हैं ।

दक्षिण रेलवे के 'हैड सिगनेलरों' का स्थानान्तरण

2524. **श्री टी. एस. लक्ष्मण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में 205-280 रुपये के वेतन मान में काम करने वाले 'हैड सिगनेलरों' को एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता, हालांकि उन की प्रवरता अखिल रेलवे के आधार पर निश्चित होती है;

(ख) क्या उन के नीचे ग्रेड के वायरलैस आपरेटरों को एक डिबीजन से दूसरे डिवीजन में स्थानान्तरित किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो दोनों वर्गों में इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) से (ग). 205-280 रुपये के बेतनमान में प्रधान तार बाबुओं की वरिष्ठता मंडलीय आधार पर नियंत्रित की जाती है; इसलिए सामान्यतया उनके एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानान्तरण की सम्भावना नहीं होती । दूसरी ओर चूंकि वायरलेस आपरेटरों का संवर्ग छोटा होता है इसलिए, उन्हें पदोन्नति के समान अवसर देने के लिए उनकी वरिष्ठता प्रधान कार्यालय में केन्द्रित रखी जाती है। अतएव, उन्हें एक मंडल से दूसरे मंडल मे स्थानान्तरित किया जा सकता है।

सेंट थामस माउण्ट तथा मीनमबातकम (दक्षिण रेलवे) के बीच नगनाल्लूर में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाना

2525. **श्री टी. एस. लक्ष्मणन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर सेंट थामस माउण्ट तथा मीनमबातकम के बीच नगनाल्लूर में रेलवे स्टेशन बनाने का कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) और (ख). कुछ प्रारम्भिक कार्य पूरा कर लिये जाने के बाद निर्माण का काम जून 1972 में प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया है और आशा है कि सम्पूर्ण कार्य एक वर्ष में पूरा हो जायेगा।

त्रिपुरा के कोयला व्यापारियों से कोयले की ढुलाई के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

2526. **श्री बीरेन दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा के कोयला व्यापारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही;

(ख) क्या त्रिपुरा को कोयले की ढुलाई के लिए कोई वेगन सप्लाई नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो त्रिपुरा के लोगों की कठिनाईयां दूर करने के लिये सरकार का विचार कौन से कदम उठाने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां। त्रिपुरा को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के सम्बन्ध में हिदायतें जारी कर दी गयी हैं।

(ख) जी नहीं। 1971-72 में त्रिपुरा के लिए बंगाल-बिहार क्षेत्रों में साफ्ट कोक के तेंतीस माल-डिब्बे आवंटित किये गये। त्रिपुरा दूसरे किस्म के कोयले की आवश्यकताएं असम कोयला क्षेत्रों से पूरी की जाती हैं। असम क्षेत्र की माल डिब्बों की आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पूरी की गयीं हैं। सितम्बर और अक्तूबर, 1971 में वर्षा, बाढ़ और लाइनों की टूटफूट आदि के कारण और उसके बाद भारी आपतकालीन ढुलाई के फलस्वरूप 1971-72 में बंगाल-बिहार क्षेत्र से त्रिपुरा को साफ्ट कोक की ढुलाई कम हुई।

(ग) विशेष ढुलाई की गति धीमी पड़ जाने से अब साफ्ट कोक के लिए माल डिब्बों का आवंटन राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है।

ओखला और दिल्ली-सफदरजंग स्टेशनों पर कार्य करने वाले इलेक्ट्रिकल सिगनल मेन्टेनर्स को समयोपरि भत्ते की अदायगी न करना

2527. **श्री बी. पी. मोर्य : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सफदरजंग एवं ओखला स्टेशनों पर नियुक्त इलेक्ट्रिकल सिगनल मेन्टेनर्स लगातार 12 घण्टे की ड्यूटी देते हैं;

(ख) क्या उन्हें समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). ओखला और दिल्ली सफदरजंग में तैनात बिजली सिगनल अनुरक्षकों ने, जिन्हें काम का घंटा विनियम के अन्तर्गत 'निरन्तर' के रुप में वर्गीकृत किया जाता है, अधिक कार्यभार को सम्हालने के लिए यदा कदा 12 घन्टे की ड्यूटी की है। 1970-71 में ऐसे कर्मचारियों को देय समयोपरि का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि बिल समय पर नहीं भेजें गये थे। सम्बन्धित कर्मचारियों को देय रकम की शीघ्र अदायगी के लिए रेल प्रशासन को हिदायत दी गयी है।

जालंधर और लुधियाना में नियुक्ति खलासियों एवं इलैक्ट्रिक सिगनल मैन्टेनर्स को रात्रि ड्यूटी भत्ता

2528. **श्री बी. पी. मौर्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलंधर शहर और लुधियाना में पारियों (शिफ्टों) पर कार्य करने वाले खलासियों एवं इलैक्ट्रिकल सिगनल मैन्टनर्स को रात की ड्यूटी देनी पड़ती है;

(ख) क्या उन्हें रात्रि ड्यूटी भत्ता नहीं दिया जाता; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जालंधर सिटी और लुधियाना में जो बिजली सिगनल अनुरक्षक और जालंधर सिटी में जो खलासी पारी की ड्यूटी पर काम करते हैं, उन्हें रात्रि ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। पता चला है कि लुधियाना में पारी की ड्यूटी पर काम कर रहे खलाखियों को भूल से रात्रि ड्यूटी भत्ता नहीं दिया गया था। इसलिए रात्रि ड्यूटी भत्ते की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं।

कुछ वस्तुओं पर रेल भाड़े की अनिवार्यता पहले अदायगी की योजना

2530. **श्री के० कोण्डारामी रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम कीमत की वस्तुओं पर रेल भाड़ा की अनिवार्यता पहले अदायगी की योजना का लागू किया जाना स्थगित कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या करण हैं; और

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इस योजना से सभी छोटे व्यापारी और उद्योगपति अपना माल रेल द्वारा नहीं भेजेंगे और यदि हां, तो इस पर क्या सरकार की प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) जी हां, व्यापारियों को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कुछ अधिक समय मिले इस दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि कुछ कम मूल्य वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में माल भाड़े का पहले ही भुगतान लागू करने की तारीख पूर्व अधिसूचित 1-4-72 के बदले 1-7-1972 होगी।

(ख) जी हां, इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि इस विनिश्चय से छोटे व्यापारियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसी भी बहुत पुरानी परिपाटी में परिवर्तन करने से व्यापारियों को प्रारम्भ में कुछ असुविधाएं हो सकती है लेकिन समय बीतने के साथ व्यापारी नयी परिस्थिति के

अनुकूल कारोबार का समर्जन कर लेंगे। माल भाड़ा तो देना ही पड़ता है, अब प्रश्न केवल यह है कि भुगतान का समय कुछ दिन पहले ही कर दिया गया है।

जूट तथा मस्टा का उत्पादन

2531. **श्री के. कोडण्डा रामी रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में जूट तथा मेस्टा का उत्पादन होता है और बर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में उनका उत्पादन कितन-कितना था; और

(ख) राज्यवार तथा क्षेत्रबार पटसन मिलों, (गैर-सरकारी, सरकारी तथा सहकारी) की संख्या कितनी-कितनी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) और (ख). (1) 1970-71 में जूट तथा मेस्टा का राज्यवार उत्पाद निम्नोक्त प्रकार है :—

आंकड़े : लाख गांठों में

राज्य	जूट	मेस्टा
आंध्र प्रदेश	—	2.96
आसाम	9.37	0.24
बिहार	7.73	1.71
उड़ीसा	2.97	1.32
उत्तर प्रदेश	1.00	—
पश्चिम बंगाल	26.84	3.84
त्रिपुरा	0.65	0·55
अन्य	0.49	1.68
योग	40.05	12.30

1971-72 के लिए राज्यवार आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। जूट तथा मेस्टा का कुल उत्पादन लगभग 68 लाख गांठें होने का अनुमान है।

(2) **कम्पोजिट जूट मिलों की राज्यवार संख्या**

पश्चिमी बंगाल ... 54 (सभी गैर सरकारी क्षेत्र में)

आंध्र प्रदेश	...	4	सभी गैर सरकारी क्षेत्र में
बिहार	...	3	"
उत्तर प्रदेश	...	3	"
आसाम	...	1 (सहकारी क्षेत्र में)	
मध्य प्रदेश	...	1 (गैर-सरकारी क्षेत्र में)	

आधुनिक पटसन मिलें स्थापित करना

2532. **श्री के. कोडन्डा रामी रेड्डी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पटसन उत्पादन राज्यों में नई तथा आधुनिक पटसन मिलें स्थापित करने की संभावनाओं का सर्वेक्षण करने हेतु नियुक्ति समिति के निष्कर्षों के संबंध में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजना से कौन कौन से राज्य चुने गए हैं और ये मिलें किस क्षेत्र में स्थापित की जायेंगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी

2533. **श्री के. कोडण्डा रामी रेड्डी** :
श्री के. रामकृष्ण रेड्डी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में इस समय बिजली की कमी के क्या कारण हैं और केन्द्रीय सरकार का इस सम्वन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : आंध्र प्रदेश में बिजली की वर्तमान कमी अपर्याप्त विद्युत जनन क्षमता और वाहक्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा के कारण मचकुंड में जल-विद्युत जलाशय से अपेक्षतया कम बिजली पैदा होने के कारण है।

मैसूर, केरल और तमिलनाडु से, यथासंभव राहत-विद्युत का प्रबन्ध किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में विद्युत संकट

2534. **श्री के. कोडण्डा रामी रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को यह पता है कि यदि आंध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन की वर्तमान गति को न बढ़ाया गया तो वहां 1973-74 और 1974-75 के दौरान विद्युत संकट उत्पन्न हो सकता है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि 'लोअर सिलेरू पन-बिजली परियोजना' के लिए 9.50 करोड़ रुपए दिए जायें और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां। सरकार को आंध्र प्रदेश में 1973-74 और 1974-75 में होने वाली बिद्युत की सम्भावित कमी के बारे में मालूम है।

(ख) राज्य प्राधिकारियों ने 1973-74 तक 100 मैगावाट की एक अतिरिक्त विद्युत जनन यूनिट को चालू करने के लिए 29.25 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकार को बता दिया गया है कि यदि वे संसाधकों को जुटाकर आवश्यकता के काफी भाग को पूरा कर सकें तो केन्द्र बाकी कमी को पूरा करने में सहायता कर सकेगा।

आसाम में असमिया माध्यम वाली रेलवे की शिक्षा संस्थाएं

2535. **श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन द्वारा आसाम में कितनी शिक्षा संस्थाएं चलाई जा रही हैं; और

(ख) उन संस्थाओं की संख्या तथा नाम क्या है जहां शिक्षा का माध्यम असमिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) तीस।

(ख) निम्नलिखित नौ शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम असमिया भाषा है :—

1. रेलवे प्राथमिक विद्यालय, पांडु।
2. रेलवे प्राथमिक विद्यालय, लमडिंग।
3. रेलवे प्राथमिक विद्यालय, मरियानी।
4. रेलवे प्राथमिक विद्यालय, तिनसुकिया।
5. रेलवे प्राथमिक विद्यालय, डिब्रूगढ़।
6. रेलवे प्राथमिक विद्यालय, डांगतल।
7. रेलवे प्राथमिक विद्यालय, बोंगाई गांव।
8. रेलवे प्राथमिक विद्यालय, अमीन गांव और
9. रेलवे प्राथमिक विद्यालय, बदरपुर।

एक्सपोर्ट इन्सपैक्शन ऐजेंजी स्टाफ ऐसोशिएशन, कोचीन से अभ्यावेदन

2536. **श्रीमती भार्गवी तनकम्पन** : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में एक्सपोर्ट इन्सपैक्शन ऐजेंसी स्टाफ ऐसोसिएशन, कोचीन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) इस संस्था ने बास्तविक तथा प्रशासकीय रूप से अग्राह्य मांगों की एक लम्बी सूची बनाई थी, जैसे कनिष्ठ तकनीकी अधिकारियों के पदों को समाप्त करना, वेतन में वृद्धि करना, विशेष वेतन, यात्रा भत्ते में वृद्धि, साइकिलों की खरीद के लिए पेशगी राशि में वृद्धि, मकान किराये भत्ते में वृद्धि, चिकित्सा लाभ के लिए न्यूनतम राशि 400 रु, संतान शिक्षा भत्ता, उच्च पदों पर कोई सीधी भर्त्ती न हो, कर्मचारियों की संतान हेतु पदों का आरक्षण, आदि आदि । इस प्रकार की मांगों को देखते हुए सरकार का कोई भी कार्यवाही करने का विचार नहीं हैं ।

केरल में ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण

2537. **श्रीमती भार्गवी तनकम्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण ने केरल के कुछ जिलों में सर्वेक्षण किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के क्या नाम हैं और सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण की स्कीम के अन्तर्गत कन्नौर जिले का सर्वेक्षण किया जायेगा जिसको राज्य सरकार द्वारा 1-4-1972 से कार्यान्वयन के लिए 15-3-1972 को स्वीकृत किया गया है ।

दक्षिण रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई

2538. **श्रीमती भार्गवी तनकम्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान दक्षिण रेलवे के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी और कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अभी भी जांच की जा रही है; और

(ख) उक्त अवधि में विभागीय कार्रवाई के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) (i) दक्षिण रेलवे के उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध पिछले दो वर्षों में विभागीय कार्यवाई की गई थी 2676

(ii) उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अभी हो रही है 811

(ख) 250

चीफ हैल्थ इंस्पैक्टर के पद का दिल्ली से अमृतसर को स्थानांतरण

2539. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीफ हैल्थ इंस्पैक्टर के पद को, जिसका वेतनमान रुपये 335-425 है, दिल्ली से अमृतर स्थानांतरित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). शुरू में प्रशासनिक हित में 335-425 रुपये के ग्रेड के मुख्य स्वस्थ्य निरीक्षण के पद को उस पर काम करने वाले कर्मचारी के साथ साथ दिल्ली से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन बाद में कर्मचारी के अनुरोध पर उसे अमृतसर स्थानांतरित कर दिया गया।

स्वास्थ्य मलेशिया निरीक्षकों का एक स्थान पर कार्य करने का कार्यकाल

2540. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में स्वास्थ्य निरीक्षकों/मलेरिया निरीक्षकों के एक स्थान पर कार्य करने के लिए कितनी अधिकतम अवधि निर्धारित है और उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए क्या कसौटी निर्धारित है;

(ख) उत्तर रेलवे के कितने स्वास्थ्य निरीक्षक/मलेरिया निरीक्षक पिछले दस वर्षों से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या ऐसे भी स्वास्थ्य निरीक्षक/मलेरिया निरीक्षक हैं जिन्हें पिछले दस वर्षों में दिल्ली क्षेत्र में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है परन्तु दिल्ली से बाहर नहीं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक स्थान पर कार्य करने के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है।

(ख) एक ।

(ग) जी हां ।

पावी रेलवे स्टेशन, गुजरात (पश्चिम रेलवे) पर पेय जल की व्यवस्था

2541. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गुजरात राज्य में पावी रेलवे स्टेशन पर वर्ष-भर पीने के पानी का उचित प्रबन्ध रहता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : पावी रेलवे स्टेशन पर पूरे वर्ष पर्याप्त पेय जल की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है ।

पावी स्टेशन (पश्चिम रेलवे) में गोदाम का निर्माण

2542. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल की रक्षा के लिए पावी रेलवे स्टेशन पर सरकार का विचार गोदाम बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय (श्री के. हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में अनकापल्ली के राव के व्यापारियों द्वारा वैगनों की मांग

2543. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** :

श्री के. सूर्यनारायण :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में अनकापल्ली राव के व्यापारियों से वहां जमा हो गये राव के भंडारों की ढुलाई के लिये और अधिक वैगन आबंटित करने के संबंध में रेलवे प्रशासन को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन पर रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) विजयवाडा मण्डल में प्राप्त होने वाले उच्चतर प्राथमिकता वाले यातायात की निकासी के लिए व्यक्तिता के आधार पर माल डिब्बों की सप्लाई के लिए दिये गये वचन के अनुसार अनकापल्ली से राब के प्रबन्ध में सुधार कर दिया गया है । तदानुसार जनवरी से मार्च 1972 की अवधि में इस स्टेशन से 1321 मालडिब्बों का लदान हुआ जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1083 माल डिब्बों का लदान हुआ था ।

Cost of DLW Engines supplied to Atomic Energy Commission

2544. SHRI MOHAN SWARUP : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Diesel Locomotive Works, Varanasi is manufacturing and supplying engines to the Atomic Energy Commission and certain industrial establishments;

(b) if so, the cost of each engine; and

(c) the number of engines supplied so far ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) The Diesel Locomotive Works, Varanasi, have received only one order for supply of two 2600 Hp Diesel Generating sets from Madras Atomic Power Plant of the Bhaba Atomic Research Centre.

(b) About Rs. 8.6 lakhs each.

(c) Nil.

केन्द्रीय सरकार की सहायता से बिहार के निकट बलिया नदी पर एक बांध का निर्माण

2545. **श्री शिवचण्डिका** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सहायता से जिला गोड्डा (बिहार) के बांका सबडिवीजन में बिहार के निकट बलिया नदी पर एक बांध बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के 25 वें वर्ष के उपलक्ष में सरकार का विचार स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए व्यक्तियों की स्मृति में उक्त बांध का नाम 'शहीद बांध' रखने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) सिंचाई एक राज्य विषय है । केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है न कि किसी विशिष्ट विकास शीर्ष अथवा परियोजना के लिए ।

(ख) सुझाव को बिहार सरकार के नोटिस में उनके विचारार्थ लाया जाएगा ।

निर्धन जिलों के विकास के लिए सर्वेक्षण

2546. **श्री पी. एम. मेहता** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के कुछ सब से निर्धन जिलों के विकास के लिए सर्वेक्षण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य क्या है; और

(ग) पहले-पहले कितने जिलों का सर्वेक्षण किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). ग्रामों में विकासात्मक कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए बुनियादी इंजनियरी और कृषि सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करना आवश्यक है जिससे कि विकास की वैज्ञानिक और व्यवहार्य स्कीमें तैयार करने में सहायता मिलेगी । इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, 550 सर्वेक्षण-दलों द्वारा 17 राज्यों के 25 जिलों में सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लेने के लिए ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षणों को एक स्कीम को मंजूरी दे दी गई है । सर्वेक्षण दल कृषि, जनसंख्या और आय के आंकड़े एकत्र करेंगे और सिंचाई पेयजल, सड़क-संचार और विद्युत सप्लाई के लिए मौजूदा सुविधाओं के बारे में सूचना एकत्र और संकलित करेंगे । एक-एक फुट के अंतरों पर समोच्च नक्शे तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया जाएगा । ग्रामों के हरिजन और अधिक निर्धन लोगों के लिए सड़क पर रोशनी के लिये विद्युत कूल और घर के लिए स्थलों का निश्चय जैसी आवश्कताओं के प्राक्कलन का कार्य भी किया जाएगा ।

इन सर्वेक्षणों के अन्तर्गत आने वाले जिले वे हैं, जहां चिर-सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए ग्राम निर्माण कार्य-क्रम की स्कीम पहले से चालू है और उन राज्यों में जहां यह स्कीम चालू नहीं है, वे जिले इसके अन्तर्गत आते हैं, जहां ग्राम विकास के लिए क्रैश स्कीम चालू है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

बंगला देश से बड़ी संख्या में बिहारी मुसलमानों के बिहार में आने का समाचार

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent Public importance and request that he may make a statement thereon. Reports regarding crossing over by a large number of Bihari Muslims to Purnia District of Bihar through 112 Kilometre long unsafe border area of Dinajpur District of Bangla Desh.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं कि गैर बंगाली मुसलमान काफी वड़ी संख्या में बंगलादेश से सीमा पार कर पश्चिम बंगाल तथा बिहार के भागों में प्रवेश कर रहे हैं। समाचार सही नहीं हैं। यद्यपि बंगला देश से गैर-बंगाली निवासियों के आने के छुट-पुट मामले हुए हैं तथापि ऐसे व्यक्तियों के भारी संख्या में आने की कोई घटना नहीं हुई है। बंगला देश की सरकार ने उस देश में गैर-बंगाली मुसलमानों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए सभी सम्भव उपाय किये हैं। हमारे सीमा प्राधिकारी भी पूरी तरह सतर्क हैं तथा उन्होंने पश्चिम दिनाजपुर जिले के साथ-साथ सीमा पर तथा अन्य स्थानों पर सीमा पार करने वाले व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने में लिए पर्याप्त उपाय किये हैं।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I am surprised at the statement given by hon. Minister. Our border with Bangla Desh is about 1300 mile long and we an not having check-posts all along the border. Unauthorised entry to our border is possible at any point. It has been stated in the "*Statesman*" published from Calcutta that a bout 150 persons are crossing over from Bangla Desh every month. They are crossing through the border of Murshidabad, Malda, West Dinajpur and other districts. Similar reports have been received from Bihar also. But inspite of this the hon. Minister has stated that only stray instances have been there. May I know the number of Bihari Muslimes who have crossed over to India so far ? Is it a fact that the people who are crossing over are bringing with them a certificate from their MLAs or MPs ? When our Prime Minister visited Bangla Desh, whether the issue of non-Bngali Muslims was discussed ? May I know if Government of India is making an effort that the issue of Bengalis in Pakistan and non-Bengali Muslims in Bangla Desh should be discussed and solved by Pakistan and Bangla Desh and India should not be aparty to this issue ?

SHRI K. C. PANT : According to the information available with me, from the end of March, 1971 upto 6 April, 1972 about 2000 Non-Bengalis have crossed over to India. Out of these 2000 people, 600 have gone back and 1400 are still in India.

As regards the second question, I have got no information wheather they are bringing a certificate from their M. L. As or not. I have already stated that the question of exchange of population is an issue concerning Pakistan and Bangla Desh only and that we have got nothing to do with it.

श्री वयालार रवि (चिर्रयिंकील) : अध्यक्ष महोदय, हमें यह सुन कर कुछ संतोष हुआ है कि हमारे क्षेत्र में घुसने वाले गैर-बंगाली मुसलमानों की संख्या अधिक नहीं है। यह भी हर्ष की बात है कि इस प्रकार की घुसपैंठ रोकने के लिए बंगला देश सरकार द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है। हम सभी को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि यह घुस-पैठिये वही लोग हैं जिनका बंगला देश के मुक्ति आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं था। ये लोग पाकिस्तान के विरुद्ध हैं और वह भारत में उसी देश के हितों के लिए ही कार्य करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि 1965 से 1971 तक निरन्तर घुसपैठिये सीमा पार करते रहे हैं। एक व्यक्ति को सीमा पार करने के लिए 500 रुपये से 1000 रुपया तक की रिश्वत देनी पड़ती है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह काफी गंभीर मामला है और सरकार को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये। सरकार को 220 किलोमीटर लम्बी सीमा पर और अधिक चौकियां बनानी चाहिये। बंगला देश सरकार के साथ विचार-बिमर्श करके इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? मैं

विवादास्पद मामलों का उल्लेख नहीं करना चाहता। पटना में हुई एक ग्राम सभा में कुछ राजनीतिक दलों ने बंगला देश के साथ जन सरकार के आदान-प्रदान का समर्थन किया था। ग्रत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब वही लोग इन घुसपैठियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ? क्या घुसपैठ रोकने के लिए सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कृष्णचंद्र पंत : सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और घुसपैंठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा गत कुछ महीनों में कड़े कदम उठाऐ गए हैं । मैंने इस सम्बन्ध में वर्ष 1965-71 तक के आंकड़े एकत्रित नहीं किये। प्रश्न के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए मैंने 1971-72 के ही ग्रांकड़े एकत्रित किये थे। बंगला देश ग्रौर भारत सरकार का ग्रापस में पूर्ण सहयोग है और इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही पर दोनों देशों द्वारा कड़ी नजर रखी जाती है।

ग्रब प्रश्न यह है बाहरी चौकियों पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्या ग्रतिरिक्त उपाय किये गये हैं ? विदेशियों संबंधी अधिनियम के ग्रन्तर्गत एक ग्रादेश जारी करके किसी भी विदेशी की सूचना निकटतम प्राधिकारी को देना लोगों के लिए ग्रनियार्य कर दिया गया है। जब शरणार्थी भारत आ रहे थे, उस समय यह ग्रादेश जारी किया गया था ग्रौर यह ग्रभी तक जारी है। मैं समझता हूं कि इस ग्रादेश का पालन करने से घुसपैठियों का तुरन्त पता लग जायेगा।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI (Morena) : First, I would like to know from the hon. Minister what arrangement is being made to send back the 1400 non-Bengali Muslims who are in India ? How far this statement of the Prime Minister is correct that if the aforesaid people are sent back to Bangla Desh, they will engineer riots in that Country ? Hastly, when the Prime Minster visited Bangla Desh, whether the issue of non-Bengali Muslims was discussed there; if so the outcome thereof ?

SHRI K. C. PANT : It is difficult to announce a definite date of return for 1400 people who are in India because much depends upon circumstances. As regards the issues discussed with the Prime Minister of Bangla Desh, Sheikh Mujibur Rehman by Prime Minister, shrimati Indira Gandhi, everything has appeared in the press. The joint Communique has also appeared in the Press.

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी (निजामबाद) : सम्पूर्ण राष्ट्र का श्री पंत पर पूर्ण विश्वास है क्योंकि वह जो भी बात कहते हैं उसे पूरा भी कर देते हैं। बंगला देश में जो 20 लाख बिहारी मुसलमान रह रहे हैं, बह वहां पूर्णतया सुरक्षित हैं। उनके भारत ग्राने के केवल दो ही उद्देश्य हैं। प्रथम तो यह कि वह बंगला देश सरकार को बदनाम करना चाहते हैं ग्रौर दूसरे वे भारत के लिए समस्याएं उत्पन्न करना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय के साथ इस बात पर सहमत नहीं हूं कि 1400 लोगों से कोई विशेष खतरा नही है, खतरा तो एक भी देशद्रोही से हो सकता है। यदि वह लोग बंगला देश में 25 वर्ष रहने के बाद भी अपने ग्रापको वहां के वातावरण के ग्रनुकूल नहीं ढाल सके तो वह भारत में ग्रपने ग्राप को कैसे ढाल सकते हैं ? मैं समझता हूं कि इन लोगों पर बिलकुल दया नहीं करनी चाहिये। ग्रपितु जिन लोगों के साथ ये लोग रह रहे हैं, सरकार को उन्हें भी ग्राश्रम प्रदान करने के लिए सजा देनी जाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : बंगला देश में जो कुछ लाख गैर-बंगाली मुसलमान रह रहे हैं उनके बारे में शेख मुजीब रहमान पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि जो लोग वहां के सच्चे नागरिक बन कर वहां बसना चाहते हैं, सरकार उनका स्वागत करेगी । उन लोगों की सुरक्षा के बारे में केवल कुछ निहित राजनीतिक स्वार्थी द्वारा रैडक्रास और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों को भ्रम में डालने के लिए गलत प्रचार किया जा रहा है । जहां तक भारत में रह रहे 1400 व्यक्तियों का प्रश्न है, उन लोगों को जमानत पर छोड़ा हुआ है और राज्य सरकारों को उनके रहने आदि के ठिकाने की पूर्ण जानकारी हैं तथा किसी वक्त भी उन्हें पकड़ा जा सकता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है इसी पर हमारी और बंगला देश के संबंध निर्भर करते हैं और किसी भी हालत में यह संबंध बिगड़ने नहीं दिए जाने चाहिएं । शेख मुजीब ने अनेक बार खुले आम कहा है कि जो गैर-बंगाली मुसलमान बंगला देश के बफादार नागरिक बनकर रहना चाहते हैं उनका बंगला देश में स्वागत है । इस वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि शेख मुजीब सभी 20 लाख गैर-बंगाली मुसलमानों को पाकिस्तान का सहयोगी नहीं मानते । विद्रोहियों को कोई भी देश बिना सजा दिए नहीं छोड़ सकता । इस सम्बन्ध में बंगला देश सरकार जो भी कुछ करना चाहे वह कर सकती है क्योंकि उसकी अपनी पृथक प्रभुसत्ता है ।

यद्यपि बंगला देश सरकार अपने देश वासियों के संरक्षण के लिए हर सम्भव यत्न कर रही है फिर भी न जाने वहां के लोगों के मन में यह भय क्यों बैठा हुआ है कि यदि भारत वहां से अपनी सेनाएं वापिस बुला लेगा तो उनके देश की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जाएगी और उन्हें फिर से उन्हीं यातनाओं का सामना करना पड़ेगा, उनका विचार हैं कि उनकी सुरक्षा मुख्यतः भारतीय सेना की मौजूदगी पर ही निर्भर है । यदि वहां से भारतीय सेना हटा ली जायेगी तो ऐसी अवस्था में काफी संख्या में वहां के लोगों की भारत आने की सम्भावना है ।

अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि बंगला देश से विभिन्न स्तरों पर हो रही वार्ताओं में क्या इस मामले पर भी विचार किया जाएगा कि एक व्यक्ति को देश छोड़ने से पहले किन आवश्यक कार्यवाहियों को पूरा करना पड़ेगा अर्थात यात्रा का प्रमाणिक दस्तावेज कौन सा होगा ?

समाचार-पत्रों के अनुसार, जिसका श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने भी उल्लेख किया हैं कि कोई भी गैर-बंगाली मुस्लिम व्यक्ति या परिवार देश को इस शर्त पर छोड़ सकता है यदि उसे बंगला देश की संविधान सभा के किसी भी सदस्य द्वारा यह प्रमाण-पत्र मिल जाता है कि उसने या उन्होंने युद्ध के दोरान पाकिस्तानियों को सहयोग नहीं दिया । मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह बात ठीक है ? यदि हां, तो क्या ऐसे प्रमाणपत्र-धारियों को देश में आने दिया जाएगा ? क्या इस प्रकार के प्रमाणपत्र को किसी प्रकार की मान्यता दी जाएगी ? इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन लोगों की नागरिकता क्या होगी जो भारत में आ चुके हैं और जिनके बारे में सरकार को भी जानकारी है ? स्पष्टतया वे पाकिस्तानी राष्ट्रिक हैं । वह बंगला देश के नागरिक नहीं बनना चाहते और वह इस देश में नाजायज तरीके से आ गए है । क्या

इन लोगों को बंगला देश वापिस जाने के लिए बाध्य किया जायेगा अथबा वह अनिश्चित काल के लिए यहीं रहेंगे ? आज इनकी संख्या 1400 है पर कुछ समय बाद इनकी संख्या 14,000 भी हो सकती है। अतः इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि बंगला देश में सहायता के नाम पर काम कर रही कुछ विदेशी एजंसियां दोनों देशों में सम्बन्ध खराब करने पर तुली हुई है ? वे बड़ी संख्या में वहां से लोगों को चोरी छिपे भारत भेज रहीं है। इस सम्बन्ध में क्या सावधानी बरती जा रही है ?

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि कल यदि समाचार-पत्र इस सम्बन्ध में कहानियां गढ़ना शुरू कर दें, तो सरकार तो इन्हें निराधार बताकर स्वीकार नहीं करेगी। इस स्थिति में क्या सरकार को चुप बैठा रहना चाहिए ? क्या उसका कर्तव्य यह नहीं है कि वह सदन को विश्वास में लेकर इन बातों का खंडन करे ? मेरे विचार में ऐसी समस्याओं से निपटने का यह उचित तरीका नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : गैर-बंगाली मुसलमानों की संख्या 20 लाख बताई गई है जबकि हमारे अनुमान के अनुसार यह लगभग 12 लाख है। श्री इन्द्रजीत गुप्त का कहना है कि यदि बंगला देश से भारतीय सेवा हटा ली जाएगी तो बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आ जायेंगे मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वहां से हमने अपनी सेनाएं बापिस बुला ली हैं और बड़ी संख्या में लोग वहां से भारत नहीं आए।

जहां तक यात्रा-प्रबंधों का सम्बन्ध है, इस बारे में स्थायी रूप से कुछ नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में कुछ अस्थायी प्रबन्ध किए गए हैं, जो कि 30 जून 1972 तक जारी रहेंगे। भारतीय राष्ट्रिक पासपोर्ट पर आबश्यक मुहर लगवा कर बंगला देश जा सकेंगे उन्हें इसके लिए बंगला देश सरकार से वीजा नहीं लेना पड़ेगा। इसी प्रकार बंगला देश के निबासी भी पासपोर्ट पर आवश्यक मुहर आदि लगवाकर भारत आ सकते हैं उन्हें भी भारत सरकार से बीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन व्यक्तियों के पास ये कागजात होंगे ये प्राधिकृत माने जायेंगे।

इसके अतिरिक्त सीमा पर व्यापार के सम्बन्ध में कुछ समझौते किए गए हैं।

जहां तक भारत में रहने वाले ऐसे लोगों की राष्ट्रीयता का सम्बन्ध है, इस पर बाद में बिचार किया जाएगा और तब तक मैं यह वताने की स्थिति में नहीं हूं कि इन्हें पाकिस्तानी राष्ट्रिक माना जाए अथवा बंगला देश के।

हमें इस वात की भी कोई जानकारी नहीं है कि कुछ विदेशी एजंसियां गैर-बंगाली मुसलमानों को चोरी छिपे भारत भेजने में लगी हैं।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

Papers Laid on the Table

अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति के बारे में सरकारी सूचना

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं समाचार पत्रों और सावधिक पत्र-पत्रिकाओं के सम्बन्ध में वर्ष 1972-73 के लिये अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति के बारे में दिनांक 11 अप्रेल, 1972 की सरकारी सूचना संख्या 53-आई टी. सी. (पी एन)/72 की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०** 1703/72)

निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) नियम के अन्तर्गत पत्र

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 16 के उप-नियम (3) के अन्तर्गत निम्यलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की —एक-एक प्रती :—

(एक) निर्यात निरीक्षण परीषद के वर्ष 1967-68 के प्रमाणित लेखे तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(दो) निर्यात निरीक्षण परीषद् के वर्ष 1968-69 के प्रमाणित लेखे तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) निर्यात निरीक्षण परिषद के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उर्पयुक्त लेखे को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०** 1704/72]

अन्तर्राज्यीय जल विवाद (संशोधन) नियम

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : मैं अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय जल विवाद (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रेल, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 924 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०** 1705/72]

राज्य-सभा से संदेश

Messages from Rajya Sabha

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने 6 अप्रेल, 1972 को अपनी बैठक में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1972 पास किया है।

(दो) कि राज्य सभा में 6 अप्रैल 1972 को अपनी बैठक में सिकन्दराबाद और औरंगाबाद छावनी गृह किराया नियंत्रण कानून (निरसन) विधेयक, 1972 पास किया है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 4 अप्रेल, 1972 को पास किये गये भारत की आकस्मिता निधि (संशोधन) विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक

Bill as Passed by Rajya Sabha

सचिव : श्रीमान, मैं निम्नलिखित दो विधेयकों को, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1972

(2) सिकन्दराबाद और औरंगाबाद छावनी गृह किराया नियंत्रण कानून (निरसन) विधेयक, 1972।

लोक लेखा समिति

Public Accounts Committee

32वां और 33वां प्रतिवेदन

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : मैं, लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं :

(1) नागर विमानन विभाग के सम्बन्ध में समिति के 124 वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

(2) निर्माण, आवास और नगरीय विकास विभाग के सम्बन्ध में समिति के 108वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

वैगनों की मामूली मरम्मत न किये जाने से कारण उनको न चलाये जाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 253 के उत्तर को शुरू करने वाला वक्तव्य

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO S.Q. NO. 253 RE : WAGON HELD UP FOR MINOR REPAIRS

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : भाग (क) के उत्तर निम्नलिखित जानकारी दी गई थी :—

लाईन	1970-71	1971-72
बड़ी लाईन	9193	2864
मीटर लाईन	2900	2558
छोटी लाईन	216	199

सही स्थिति निम्न प्रकार है :—

लाईन	1970-71	1971-72
बड़ी लाईन	9193	8264
मीटर लाईन	2900	2558
छोटी लाईन	216	199

सामान्य बजट-अनुदानों की मांगें 1972-73

General Budget—Demands for Crants, 1972-73

सिचाई और विद्युत मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 58 से 60, 122 तथा 123 पर विचार तथा मतदान करेगी। इस पर चर्चा के लिये चार घन्टे का समय रखा गया है।

जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें, वे क्रम संख्या तथा अन्य ब्यौरे सहित 15 मिनट के भीतर परची भेज दें।

SHRI KRISHNA CHANDRA PANDEY (Khalilabad) : This is an important subject. The period of four hours is not sufficient. It should be increased.

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रण समिति समय निर्धारित करती है। इसे कम अथवा अधिक नहीं किया जा सकता है।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की वर्ष 1972-73 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
58	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	8,40,96,000
59	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाएं	3,15,78,000
60	विद्युत योजनाएं	3,05,83,000
122	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	9,91,79,000
123	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	27,25,99,000

श्री विजय मोदक (हुगली) : सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का देश के आर्थिक विकास के लिए काफी उत्तरदायित्व है, परन्तु वह मांग को पूरा करने में असफल रहा हैं।

वार्षिक सिंचाई क्षमता की आवश्यकता का 50 प्रतिशत भाग भी पूरा नहीं किया गया है तथा विद्युत उत्पादन तो भारत में विश्व के देशों में सब से कम हैं। सिंचाई और विद्युत कार्यों से उच्चतम प्राथमिकता देने तथा अधिकाधिक धनराशी नियत करने के स्थान पर सरकार पुलिस तथा सेना के लिये अधिक राशि नियत कर रही है।

पश्चिम बंगाल में जल द्वारा पन-बिजली परियोजना असफल हो गई है। उत्तरी बंगाल में बिजली सप्लाई की व्यवस्था करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

कंसाबाटी परियोजना को 15 वर्ष हो गए है परन्तु उसका कार्य अभी भी अधूरा है। उसकी सिंचाई क्षमता केवल 3 लाख एकड़ है सरकार ने पश्चिम बंगाल में लोअर दामोदर क्षेत्र की बाढ़ की समस्या को हल करने की ओर ध्यान नहीं दिया है जिससे प्रति वर्ष इस क्षेत्र में जान तथा माल की अत्याधिक हानि होती है।

दामोदर घाटी निगम इस मंत्रालय के नियंत्रण में है तथा वह इस समस्या का समाधान करने में पूर्णतया असफल रहा है।

वहां पहले बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिये आठ बांध बनाए जाने थे, जिनके निर्माण का मूल आयोजनों ने सुझाव दिया था। परन्तु बाद में केवल चार बांध बनाये गये जो वर्षा ऋतु के दौरान

उपरि जल ग्रहण क्षेत्र के वर्षा के पानी को बांधे रखने में असमर्थ हैं। इसलिये जब भारी वर्षा होती हैं, तो बांधों में आये अतिरिक्त जल को बाहर निकालना पड़ता है जिससे दामोदर पार बेसिन में बाढ़ आती रहती है। इस प्रकार दामोदर घाटी निगम मे इस क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र बना दिया जहां हमेशा बाढ़ आती रहती हैं। श्री राव ने यह माना है कि मूल केन्द्रीय आयोजक इसके लिये उत्तरदायी हैं तथा जलाशय के साथ साथ नहरें निकालने से भी इस क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सकता है।

इस कार्य के लिये 4 करोड़ रुपये के स्थान पर गत वर्ष 75 लाख रुपये ही क्यों नियत किये गए ?

क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि मुन्देश्वरी पर तटबंध बना कर इस क्षेत्र में इस समस्या का समाधान किया जायेगा ? इसके प्रतिकूल मेरे पास अन्य जानकारी हैं। विशेषज्ञ इंजीनियरों ने मत व्यक्त किया है कि प्रथम चरण में जिन चार बांधों को बनाया गया हैं, उनकी अधिकतम क्षमता 6.50 लाख क्यूसेक तक की हैं जिसमें बांध के नीचे के अनियंत्रित जल ग्रहण क्षेत्र का 90,000 क्यूसेक पानी भी शामिल है। यह बाढ़ नियंत्रण क्षमता इतनी कम हैं कि इस से बाढ़ को रोकना असंभव हैं।

यदि इस पहलू पर विचार नहीं किया जाता तो अधिक खतरनाक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।

दामोदर घाटी निगम की बाढ़ नियंत्रण क्षमता के प्रश्न की जांच किये बिना इतनी अधिक धनराशी की व्यवस्था करने से पूर्व मंत्री महोदय को सोच विचार करना चाहिये। वहां भूमि का और अधिक अर्जन करके मैथीन तथा पांचेत बांध के बाढ़ रिजर्व में वृद्धि करने पर मंत्री महोदय क्यों नहीं विचार कर रहे हैं।

मांदेश्वरी के साथ-साथ तट बंध बना कर वह बड़ी भारी जोखिम उठा रहे हैं। यदि 2,50,000 क्यूसेक से अधिक बाढ़ का जल भी आयेगा तो उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी को खतरा पैदा हो जायेगा।

केरल में समुन्द्री कटाव की समस्या ऐसी है जो अन्य राज्यों में नहीं है। केरल के 560 किलोमीटर लम्बे समुन्द्र तट में से 320 किलोमीटर तट पर हमेशा कटाव होता रहता है। इस क्षेत्र को कटाव से बचाया जाना चाहिये। सरकार को इस समस्या की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

कावेरी जल विवाद की समस्या तामिलनाडु तथा मैसूर राज्यों की समस्या है। केरल का थोड़ा सा भाग भी इससे प्रभावित है। कावेरी के जल का न्यायपूर्वक तथा समान वितरण इन तीनों राज्यों में किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिये इन राज्यों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जानी चाहिये ताकि जल का समान वितरण करने के लिये कोई तरीका निकाला जा सके।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या 1	कटौती प्रस्ताव संख्या 2	प्रस्तावक का नाम 3	कटौती का आधार 4	कटौती का राशि 5
58	5	श्री योगेन्द्र झा	चौथी जोजना की अवधि के दौरान पश्चिमी कोसी, गंडक और राजस्थान नहर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूरी वित्तीय व्यवस्था करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
,,	6	,,	पश्चिमी कोसी, गण्डक और राजस्थान नहर को पूरा करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये जाने में असफलता।	,,
,,	7	,,	बिहार में अधवार समूह की नदियों में सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजना को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	8	,,	उत्तरी बिहार में बिजली सप्लाई को समस्त देश तथा दक्षिण बिहार के स्तर तक लाने में असफलता।	,,
,,	9	,,	दरभंगा के उत्तरी भागों और नेपाल की सीमा से लगने वाले बिहार के अन्य जिलों में विद्युतीकरण की आवश्यकता।	100 रुपये
,,	10	,,	बिहार में कमला नदी के तटबंधों का जय नगर के पार नेपाल में मिर्चैया तक विस्तार करने की आवश्यकता।	,,
,,	11	,,	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण योजना के भाग के रूप में बिहार के दरभंगा लिले में घौंस-बागमती नदी पर तटबंधों का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
,,	12	,,	बिहार में दरभंगा जिले के बिरौल, घनश्यामपुर प्रखण्डों में कोसी नदी के पश्चिम तटबंध का विस्तार करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
58	13	श्री भोगेन्द्र झा	नेपाल तथा भारतीत क्षेत्रों में पश्चिम कोसी नहर की खुदाई के लिये एक साथ तथा तुरन्त भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता।	100 रुपये
,,	14	,,	पश्चिम कोसी नहर को चौथी योजना की अवधि के दौरान पूरा करने के लिये पूरी वित्तीय व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	15	,,	पश्चिम कोसी नहर के भाग के रूप में पनबिजली परियोजना की व्यवस्था करने की आबश्यकता।	,,
,,	16	,,	बिहार में जोगियारा-कामसौल-विस्फी-औंसी-जोगियारा-भारवारा-अतरबेल-कामसोल-हरिहरपुर-दरभंगा से विद्युत लाइनों को जोड़ने की आवश्यकता।	,,
,,	17	,,	बिहार के दरभंगा जिले में वानीपट्टी-हरलखी-शहरघाट माधवपुर को विद्युत लाइनों से जोड़ने की आवश्यकता।	,,
,,	18	,,	बिहार के दरभंगा जिले में राजनगर बाबूराही लौकहार लदानियां को विद्युत लाइनों से जोड़ने की आवश्यकता।	,,
,	19	,,	बिहार में दरभंगा जिले में खिरोई नदी पर विद्युत लाइनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	
,,	20	,,	बिहार के दरभंगा जिले में हरलखी—जयनगर को विद्युत लाइनों से जोड़ने की आवश्यकता।	,,
,,	30	श्री पी. के. देव	रेंगाली में ब्राह्मणी नदी पर एक संचायक होज का अवांछनीय प्रस्ताव।	,,
,,	31	,,	देश के पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से उड़ीसा में, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने की बांछनीयता।	,,

1	2	3	4	5
58	32	श्री पी. के. देव	अपर इन्द्रावती परियोजना को स्वीकृति देने की बांछनीयता।	100 रुपये
,,	33	,,	तूफान का पता लगाने के लिये उड़ीसा के समुद्रतट पर मौसम की पूर्वसूचना देने के लिये एक राडार केन्द्र स्थापित करने की बांछनीयता।	,,
,,	34	,,	संविधान के अनुच्छेद 262 के स्थान पर अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों में केन्द्र को मध्यस्थता करने की शक्ति देने सम्बन्धी सिंचाई आयोग के सुझाव की अवांछनीयता।	,,
,,	35	,,	नाराज से धौलपुर तक महानदी को नौचालन के योग्य बनाने की बांछनीयता।	,,
,,	36	,,	बाढ़ के पानी को निर्बाध गति से बहने देने के लिये चिलका के मुहाने का शीघ्र तलकर्षण करने की आवश्यकता।	,,
,,	37	,,	ब्राह्मनी नदी के बाढ़ के पानी का निर्बाध गति से बहने देने के लिये धमरा के मुहाने का शीघ्र तलकर्षण करने की आवश्यकता।	,,
,,	38	,,	राजस्थान नहर को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।	,,
,,	39	,,	बंगला देश सरकार के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का एक संयुक्त आयोग स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
,,	40	श्री रामवतार शास्त्री	समस्त देश के लिये एक सम्यक सिंचाई योजना तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
,,	41	,,	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु राज्यों को पर्याप्त सहायता देने में असफलता।	,,
59	44	,,	समस्त देश के लिए एक सम्यक सिंचाई योजना तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
,,	45	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार के कटान-पीड़ित गांवों की रक्षा करने में असफलता।	1000 रुपये
,,	46	,,	बिहार के कटान-पीड़ित गांवों के निवासियों का पुनर्वास करने में असफलता।	,,
,,	47	,,	बिहार में स्वर्णरेखा परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब।	,,
,,	48	,,	बिहार में सकरी नदी परियोजना के कार्यान्वयन में सरकार की ढील।	,,
,,	49	,,	बिहार के पटना और गया जिलों में सिंचाई सुविधायें प्रदान करने हेतु पुनपुन नदी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	,,
,,	50	,,	पटना जिले की फतुहा-बख्तियारपुर मोकामेह ताल परियोजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	,,
,,	51	,,	पटना जिले में मनेर और दानापुर थानों के दियारा क्षेत्रों के कटान-पीड़ित ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए असन्तोषजनक प्रबन्ध।	,,
,,	52	,,	बिहार में मन्सी नामक स्थान का कटान से बचाव करने में असफलता।	,,
60	53	,,	समस्त देश के लिए बिजली की समान दरें निश्चित करने तथा वर्तमान दरों को कम करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर कर दी जाये।
59	54	,,	पश्चिमी कोसी नदी परियोजना की क्रियान्विति में विलम्ब।	100 रुपये
,,	55	,,	बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए एक कारगार बाढ़ नियंत्रण योजना लागू करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
59	56	श्री रामातार शास्त्री	बाढ़ से बिहार की रक्षा करने हेतु गंगा, पुन-पुन, गंडक, कोसी, कमला, बालान और सोन नदियों को बांधने की आवश्यकता।	100 रुपये
,,	57	,,	सिंचाई के लिए गंगा के पानी को काम में लाने हेतु एक योजना बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	58	,,	गंडक सिंचाई योजना को पूर्ण करने हेतु धन देने में सरकार की ढील।	,,
,,	59	,,	सोन और कोइल नदी योजनाओं के कार्यान्वियन में विलम्ब।	,,
60	60	,,	बिहार के गांवों के विद्युतीकरण की योजना की धीमी प्रगति।	,,
,,	61	,,	विद्युतीकरण योजना को बिहार के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लागू करने की आवश्यकता।	,,
,,	62	,,	बिहार बिजली बोर्ड को अपनी कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	,,
,,	63	,,	बिहार में विद्युत्-दर को कम करने की आवश्यकता।	,,
,,	64	,,	कटिहार में प्रस्तावित तापीय बिजलीघर स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
,,	65	,,	प्रस्तावित कटिहार तापीय बिजलीघर को पश्चिम बंगाल में मालदा नामक स्थान पर स्थानान्तरित करने और इन दोनों स्थानों पर अलग-अलग तापीय बिजलीघर स्थापित करने के निर्णय को रद्द करने की आवश्यकता।	,,
,,	66	,,	उत्तर बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि करने में असफलता।	,,

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : यह सच है कि सरकार देश की गरीवी को दूर करना चाहती है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा तथा गरीब क्षेत्र है। श्री सी. सुब्राह्मण्यम् ने कहा है कि योजना आयोग एक विशेष सिद्धान्त तैयार करेगा जिससे छठी योजना के अन्त तक गरीबी दूर हो जायेगी। इस कार्य के लिए जो सिद्धान्त तैयार किया गया है, उसका लक्ष्य सघन सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन द्वारा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना है। गरीबी से लड़ने के लिये विज्ञान तथा आधुनिक प्रौद्यागिरी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिये।

जहां तक देश में विद्युत का सम्बन्ध है, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अनुसार देश में कुल कमी प्रतिदिन दस लाख किलोवाट क्षमता की वास्तविक मांग पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है। प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग राष्ट्र की प्रगति के लिए लोकप्रिय सूचकांक माना जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये बिजली को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी है। देश की अधिष्ठापित- विद्युत उत्पादन क्षमता में से 1980-81 तक 1600 मेगावाट के लिये उत्तर प्रदेश का भी भाग है। इस कार्य के लिये सिंचाई और बिद्युत मंत्रालय को प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों से आग्रह करना पड़ता है तीसरी योजना आयोग से उन पर अनुमति ली जा सके।

मंत्री महोदय के गोरखपुर की योजना को शीघ्र कार्यान्वित करवाना चाहिये।

(इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म.प. तक के लिये स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा 2 बज कर 3 मिनट म.प. पर पुनः समवेत हुई)

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Three Minutes Past Fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
The Deputy-Speaker *in the Chair*]

श्री नर सिंह नारायण पांडे : सिंचाई के मामले में सौभाग्य-वश अभी हाल के वर्षों में हमारे देश में काफी प्रगति हुई है। वास्तविक और स्थायी कृषि की प्रगति के लिये सारे देश में सिंचाई का जाल बिछाया जाना चाहिये ताकि किरघन के उचित अवसर पर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सके। सिंचाई आयोग ने अपने तीन खंडों वाले प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रतिवेदन के पहले भाग में इस बात की बड़ी चर्चा है कि इस आवश्यक और भारी कार्य को किस प्रकार किया ज.ना चाहिये।

आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार देश की कुल सिंचाई आवश्यकता 810 लाख हैक्टेयर है। आयोग ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया है कि 30 वर्षों में सिंचाई सुविधाओं की प्रस्तावित वृद्धि पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निस्संदेह यह बहुत बड़ी धनराशि है लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में ढील ढालने से अंत में अधिक हानि पहुंच सकती है।

उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में एक आणविक बिजली घर की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके बारे में क्या कार्यवाही हुई ? इसकी स्थापना कहां होगी ? इस बारे में क्या कोई निर्णय लिया गया है ? पूर्वी उत्तर प्रदेश की सप्ती घाघरा तथा अन्य नदियों को बाढ़ से नियंत्रित करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

SHRI K. M. MADHUKAR (Kesaria) : The official figures indicate that Irrigation and Power Ministry has done a commendable job. Only one fourth of 38 crore acres of cultivable land in our country is under irrigation. It was estimated that Gandak project will irrigate ten lack acres of land after incurring an expenditure of Rs. 80 lacks, it is only irrigating 50,000 acres. Water works and field channel work is going on very slowly there.

Position of the Bagmati project also is the same. Similarly, the work of Kosi canal is going on with very low speed. The potentialities of irrigation schemes are not being utilised in full.

The surface and underground water is not being utilised fully in our country. No integrated plan has been drawn for this purpose for the last 25 years. The Government should formulate a joint scheme for the utilisation of both surface and underground water for the benefits of the prople.

Necessary attention should also be paid towards small irrigation schemes which will contribute towards solving the problems of unemployment. The Central Government should pay necessary attention towards such schemes as the State Governments have no funds to provide for these schemes.

The projects for linking big rivers are also under consideration. Such projects should be implemented with faster speed.

Some steps should be taken to settle the inter-state water disputes.

The flood cotrol measures have not so far proved successful. The proposals received from the various State Governments in this behalf should be given due consideration. Due attention should also be paid towards soil erosion schemes.

The progress made in the field of electrification is also slow. Some solid steps are needed to be taken for installing thermal power station in North Bihar.

The funds provided for rural electrification are inadequate. The rural electrification work needs to be speeded up.

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण) : यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 25 वर्ष बाद भी हमारा किसान अपने सूखे खेतों की सिंचाई के लिये आकाश की ओर देखता है।

देश में विद्युतीकरण की बात लीजिये। विभिन्न विभागों को विद्युतीकरण का काम सौंपा गया है। ये विभाग हैं—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड, ग्राम्य विद्युत निगम और राज्य विद्युत बोर्ड आदि आदि। किन्तु कार्यों को प्राथमिकता दिये बिना इन विभागों की

क्या आवश्यकता हैं। प्राथमिकता यह है कि ग्राम्य क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर उद्योगों तथा आधुनिक कृषि के लिये हमें तत्काल बिजली की आवश्यकता है। दूसरी प्राथमिकता आधुनिक उद्योगों के लिये बिजली की है। इन दो कार्यों के लिये हमें राज्य सरकारों के सहयोग, अनुसंधान कार्यों तथा अन्य बातों की आवश्यकता है। लेकिन हम प्राथमिकताओं का क्रम निर्धारित नहीं कर पाते। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

पश्चिम बंगाल में बिजली के कारण काफी कठिनाई हो रही है। समस्त कलकत्ता उद्योग समूह को पानी सप्लाई करने के लिए बुन्देल तापीय बिजली घर पर 120 मेगावाट का एक अतिरिक्त जनरेटर लगाया जाना चाहिए और इसी प्रकार हल्दिया उद्योग समूह को बिजली सप्लाई करने के लिये कोलाघाट में 2×200 मेगावाट का संयंत्र लगाया जाना चाहिये। इस मंत्रालय ने उत्तर बंगाल के लिये डलद्बला में संयंत्र स्थापित करने का जो निर्णय किया है, उसे तुरन्त क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

बंगाल में हजारों एकड़ खेती योग्य भूमि में खेती नहीं होती है। मुझे आशा है कि योजना आयोग लोयर दामोदर प्रोजेक्ट का शीघ्र अनुमोदन कर देगा और वह मंत्रालय उसको शीघ्र क्रियान्वित करेगा। पश्चिम मोगराहाट जलनिकासी योजना भी योजना आयोग के विचाराधीन है। इस योजना को भी क्रियान्वित करने से भूमि को खेती में पर्याप्त सहायता में मिलेगी। गोपीवल्लभपुर के दोनों ओर स्वर्ण रेखा नदी बहती है जिसमें जहाजरानी हो सकती है परन्तु उस क्षेत्र के किसानों को वर्षा पर निर्भर करना पड़ता है। यदि उपरोक्त नदी के पानी का खेती के लिए उपयोग किया जाये तो 5,000 से 10,000 एकड़ भूमि में खेती की जा सकती हो। अतः सरकार को सिंचाई योजनाओं के बारे में शीघ्र निर्णय करना चाहिये।

उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार को बाढ़ के कारणों की जांच करने लिए सर्वेक्षण करना चाहिये। बाढ़ नियन्त्र के लिये अलग योजनाएं बनानी चाहियें और अलग संगठन स्थापित करने चाहियें। इस मंत्रालय ने कुछ राज्यों में सराहनीय कार्य किया है। तथापि यदि सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने हमारे देश के सामाजिक उद्देश्यों को अपने सम्मुख रखकर कार्य न किया, तो किसान विद्रोह कर देगा। अतः मंत्री मदोदय को इन सुझावों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये।

श्री वी० मायावान (चिदाम्बरम) : प्रस्तुत प्रतिवेदन से पता चलता है कि सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए 10 वर्ष की योजना बनाई गई है। फिर बिजली सप्लाई करने के लिए 10 वर्ष की और योजना बनेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वर्ष 1972-73 की वार्षिक योजना में उक्त योजना का कोई भाग सम्मिलित किया गया है?

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 25 वर्ष वाद हम योजना बना रहे हैं कि हम 5 करोड़ रुपये की लागत पर 20,000 हरिजनों की गन्दी बस्तियों में बिजली लगायेंगे। इस रफ्तार से हम इस कार्य को कम से कम 20 वर्षों में पूरा कर सकेंगे।

इसी प्रकार ग्राम्य इंजीनियरी सर्वेक्षण योजना चलाई गई है जिसके अन्तर्गत 26,000 ग्रामों सर्वेक्षण करने के लिये 6.24 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है। क्या किसी व्यक्ति ने अनुमान लगाया है कि इस कार्य को करने में कितने वर्ष लगेंगे ? करोड़ों रुपए विदेशों का दौरा करने पर खर्च कर दिए जाते हैं। फिर वर्ष 1953 से 1970 तक औसतन, प्रतिवर्ष बाढ़ नियंत्रण पर 98 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाती रही है। वर्ष 1971 में इस राशि को बढ़ा कर 627.64 करोड़ रुपये कर दिया गया। गत वर्ष उड़ीसा में तूफान के कारण 7000 लोगों की जानें गईं। चौथी पंचवर्षीय योजना में केवल इस प्रयोजन के लिए 183.32 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है जो बहुत कम है। बाढ़ नियंत्रण के लिए यह राशि बहुत थोड़ी है। इसे तूफान की पहले से चेतावनी देने वाला कोई आधुनिक किस्म का इलैक्ट्रानिक उपकरण लगाना चाहिये। अन्त में मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह तिरुचेन्दूर और कन्याकुमारी के बीच समुद्र के कटाव को रोकने सम्बन्धी कार्य को शीघ्र आरम्भ करवायें। तूतीकोरिन में परमाणु बिजली घर स्थापित करने का काम भी शीघ्र किया जाना जाहिये।

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) : पानी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिये। नदियों का पानी एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाता है। सभी राज्य स्वामित्व अधिकारों का दावा करते हैं और इस कारण विवाद पैदा हो जाते हैं। फिर इन विवादों को सुलझाने के लिये काफी धन और समय खर्च किया जाता है। अतः मेरा अनुरोध यह है कि पानी को प्राकृतिक साधन समझना चाहिये और किसी राज्य या क्षेत्र अथवा किसी समुदाय विशेष को पानी का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिये। इस पर एकीकृत राष्ट्रीय नियंत्रण होना चाहिऐ अन्यथा इसके परिणामस्वरूप बड़ी कठिनाइयां पैदा होंगी। राष्ट्रीय नीति इस प्रकार बनाई जानी चाहिये कि उससे विभिन्न राज्यों में पानी के वितरण के लिये पथप्रदर्शन मिल सके। उत्तर भारत में पानी का बाहुल्य है और दक्षिण भारत में पानी की कमी है। इस लिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि गंगा और कावेरी नदी को मिलाने की योजना बनाई जानी चाहिये। तकनीकी विशेषज्ञों के विचार में भी यह प्रस्ताव बिल्कुल व्यावहारिक है और सम्भव भी है। मेरे विचार में इससे देश की समस्याएं हल करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। गंगा नदी का पानी रायलसीमा जिलों के मार्ग से और विशेषकर चित्तूर जिले में से ले जा कर दक्षिण भारत तक ले जाया जाना चाहिये।

सरकार ने भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दी हैं परन्तु जब भूमिहीन गरीब लोग अपने कुएं खोदने में असमर्थ है, तो सरकार सर्वसाधारण के प्रयोग के लिये नलकूप क्यों नहीं लगाती जिससे भूमिहीन किसानों को पानी उपलब्ध किया जा सके ? सरकार को भूमिहीन गरीब किसानों को, जिन्हें अब भूमि दी गई है, सिंचाई सुविधाएं देने के लिए इस प्रकार की योजना पर विचार करना चाहिए। इस समय पानी का कोई कुशल प्रबन्ध नहीं है और पानी बेकार जाता है और उसका उचित ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश में पानी की बहुत कमी है। इसी लिये राज्य सरकार ने नागार्जुनसागर परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है। नागार्जुनसागर परियोजना में

पानी का उचित स्तर बनायें रखने के लिए तुंगभद्रा परियोजना से पानी लाना पड़ता है । अतः हम चाहते हैं कि तुंगभद्रा बांध में पानी नियमित रूप से आता रहे । यदि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा तो हम दूसरी फसल भी उगा सकते हैं ।

केन्द्रीय सरकार को सिरिसैलम परियोजना को शीघ्र पूरा करना चाहिए । इस परियोजना को पन-बिजली और तापीय परियोजना का ही नहीं बल्कि बहुप्रयोजनीय परियोजना का रूप दिया जाना चाहिए जिससे इसका लाभ आन्ध्र प्रदेश के काफी बड़े और विशेषकर रायलसीमा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पहुंच सके । अन्त में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि हरिजन बस्तियों में बिजली सप्लाई करने के लिये उचित व्यवस्था की जानी चाहिये ।

SHRI R. R. SHARMA (Banda) : It has been observed that the schemes are not being implemented properly. In so far as the question of supply of power is concerned, Uttar Pradesh is very backward. The *per capita* consumption of power in U. P. was only 53.7 units in 1969-70 whereas it was 148 units in Maharashtra, 181 units in Punjab, 127 units in Gujarat 116 units, in West Bengal and 123 units in Tamil Nadu during the same period. The hon. Minister should pay his attention and do something in this regard so that our state gets adequate water and electricity and production can be increased. The Government should concentrate on minor and lift irrigation schemes instead of major irrigation schemes, because they are more useful and can be implemented with less expenditure. It may be astonishing to note that the water is not supplied through Chambal canal and Cane canal at the time of necessity. Severe action should be taken against the officials responsible for such omissions.

Industrial development has been hampered in Bundelkhand area due to inadequate supply of power. The hon. Minister should take necessary steps for the development of this area. The rates of supply of power to industrialists and agriculturists should be same. There should not be any disparity because agriculture is also an industry.

It is understood that State Government of Uttar Pradesh have forwarded some schemes for the approval of Central Government. They should approve them and help the State in their implementation.

श्री एन. शिवप्पा (हसन): सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की गई है । इसलिये लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं । केन्द्रीय सरकार ने 1870 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया है । इस लक्ष्य तक पहुंचने में सूखा, युद्ध आदि कई बाधाओं के बावजूद काफी हद तक सफलता मिली है । परन्तु सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सरकार जो धनराशि दे उसका उपयोग पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने पर किया जाये । क्या मंत्री महोदय इस आशय का आश्वासन सभा को देंगे ? धनवान और निर्धन व्यक्ति के बीच और इसी प्रकार विकसित और पिछड़े राज्यों के बीच बिषमताएं दूर की जानी चाहिये । सिंचाई मंत्रालय को भी इसी नीति का अनुसरण करना चाहिये । इस लिये मंत्री महोदय को मैसूर, केरल और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये उन्हें छोटी सिंचाई योजनाओ को अधिक प्रोत्साहित करना चाहिये क्योंकि उनका लाभ गरीब किसान तक पहुंच सकता है । इस प्रयोजन के लिये हमें देश की सभी नदियों के पानी का सदुपयोग करना चाहिये । इससे हमारी ग्राम्य अर्थव्यवस्था में भी सुधार

होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत सुधार बोर्ड स्थापित किये जाने चाहियें। अन्यथा इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकेगा।

मैसूर सरकार ने सिंचाई मंत्रालय को कई योजसाएं भेजी हैं। उन्हें उन योजनाओं की स्वीकृति दे देनी चाहिये जिससे उन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके और ग़रीबी दूर की जा सके। मैसूर से तुंगभद्रा का पानी आन्ध्र प्रदेश को दिया जा रहा है परन्तु मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि यदि वर्षा न होने के कारण मैसूर में फसल को हानि पहुंचने का ख़तरा हुआ, तो वह पानी आन्ध्र प्रदेश को नहीं दिया जायेगा।

कृषि और उद्योग को सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध करने के लिये सरकार को पन-बिजली परियोजनाएं आरम्भ करनी चाहिये। अतः सरकार को काली परियोजना की तुरन्त स्वीकृति दे देनी चाहिये। इस से देश को काफ़ी बिजली मिल सकेगी।

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : देश के और विशेषकर गुजरात में विद्युत सप्लाई की स्थिति काफ़ी खराब है। बिजली के सामयिक अभाव के कारण गुजरात के औद्योगिक विकास में बाधा पड़ती है। हमारी अधिष्ठापित क्षमता इस समय 872 मेगावाट है जबकि हमारी अधिकतम मांग 780 मेगावाट है। अतः अधिष्ठापित क्षमता से हमारी मांग पूरी हो सकती है। परन्तु यदि कोई खराबी हो जाये, तो गुजरात को हानि उठानी पड़ेगी। अगस्त से तारापुर स्थित एक एकक बन्द है और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अतिरिक्त गैस सप्लाई न किये जाने के कारण भी अधिक बिजली पैदा करने में बाधा पड़ रही है। बिजली की इस कमी के कारण गुजरात को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन कम हो रहा है, जिसका प्रभाव इन क्षेत्रों के श्रमिकों की मजूरी पर भी पड़ा है। अब कुछ व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत महाराष्ट्र ने गुजरात को कुछ बिजली सप्लाई की है। परन्तु यह एक अस्थायी व्यवस्था है और यदि तारापुर स्थित एकक को चालू करने में बिलम्ब हुआ तो स्थिति अधिक बिगड़ जायेगी। अतः इस समस्या को शीघ्र हल करना चाहिये।

नर्मदा परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना है। अन्तर्राज्यीय विवाद के कारण इसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। अब इस विवाद को एक न्यायाधिकरण को सौंपा गया है, परन्तु यदि कोई पक्ष न्यायाधिकरण के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये तैयार नहीं होता तो फिर क्या स्थिति होगी? यह कहा गया हैं कि दो राज्यों के मुख्य मंत्री इस विवाद के सम्बन्ध में बातचीत करेंगे। यदि बातचीत के माध्यम से यह विवाद हल हो जाये, तो कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं केन्द्रीय सिंचाई मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह दोनों मुख्य मंत्रियों की बातचीत में उनकी सहायता करें।

SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL (Samastipur): I support the Demands of Irrigation and Power Ministry and congratulate the hon. Minister for bringing forward the scheme of linking Yamuna river with Cauvery river. This department has done good work in the field of rural electrification but still there are thousands of villages where there are

much scope for work to be done. The year of 1971 had brought tremendous difficulties for Bihar. Floods etc. had created havoc in that state and many lives had to suffer. Bihar saw havocs in the years 1923 and 1954 but the devastating floods of 1971 has surpassed all. About one third of the population was affected by the wrath of the nature. Many houses were destroyed in the floods and rains. A number of embankments, bunds etc. were damaged and property worth crores of rupees was lost. The hon. Minister had paid a visit to that area and took interest in the plight of the people. But the provision of only four crores rupees for raising and strengthening the present embankments is too small. At least the work on repairing of breaches should be expedited. The rainy season will be coming after a month or two and if urgent repair works are not undertaken, then you can well imagine the consequences. The people of Bihar will have to suffer once more.

Bihar is a poor state and it needs relief from the Government. The Flood Forecasting Programme has done some good work otherwise the fate of the people would have doomed. The floods of the year 1971 played havoc on many villages. Although the Government has shown us rays of hope but I would like to urge that Rs. 27 crores is too meagre for Bihar because it is the only state where the nature has never been hepful. I am thankful to the hon. Minister for his sympathy to the problem of Bihar.

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन ने बहुत से चौकाने वाले तथ्य दिये है, मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों की संख्या बहुत अधिक है। वहां प्रति व्यक्ति बिजली की खपत देश में सबसे कम है। इसी प्रकार सिंचाई क्षमता का प्रतिशत भी बहुत कम है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से वहां सिंचाई के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रतिवेदन के अनुसार मध्य प्रदेश में आठ सिंचाई कार्यों को हाथ में लिया गया था, सिजमे से केवल एक ही पूरा हुआ और उससे भी पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती है। अन्य राज्यों की तुलना से मध्य प्रदेश में केन्द्र बहुत कम धन व्यय करता है।

मध्य प्रदेश को केवल एक उपनिवेश बना कर रखा हुआ है । यहां से निकलने वाली नदियों आदि का उपयोग उत्तर प्रदेश और बिहार में किया जाता है और इसके पास कुछ नहीं रहता है, बिहार ने बंद सागर परियोजना का विरोध किया और फिर अपनी परियोजना का विस्तार करने का कार्य आरंभ कर दिया। मध्य प्रदेश ने इसका विरोध किया, क्योंकि वह सोन नदी के जल का उपयोग करना चाहता था परन्तु इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, यद्यपि मध्य प्रदेश बंदसागर परियोजना में अपने जल का केवल 38 प्रतिशत उपयोग में लाना चाहता है। परन्तु वह सुविधा भी नहीं दी गई, दूसरी ओर बिहार उत्तरी कोयल नदी पर सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था कर रहा है जिसका जल मध्य प्रदेश से होकर बहता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बाद-विबाद न खड़ा करके अहने सुझाव रखिए ।

श्री रणबहादुर सिंह : मैं केवल प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों को बता रहा हूं । मध्य प्रदेश में हमारे लिए स्थिति बहुत कठिन हो गई है। वहां सिंचाई की कोई बड़ी योजना नहीं हैं, यदि वंद-सागर बांध का निर्माण किया जाता है तो इससे 60 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है। पर इस ओर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं

सिधी, सरगुजा और शहडोल के जिले आर० ई० सी०, योजनाओं के लिये शर्तों को पूरा करते हैं। सरकार को चाहिए कि उक्त जिलों में इन योजनाओं को लागू किया जाये।

मेरा यह भी अनुरोध है कि विमानों द्वारा राज्य में जल का सर्वेक्षण कराया जाये ताकि वहां सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग किया जा सके। छोटी उठाऊ सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश के कुओं में पानी शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। मध्य प्रदेश की भूमि ऐसी है कि वहां बड़े बांध तथा नहरें बनाना कठिन है। अतएव उठाऊ सिंचाई के लिए बिजली का प्रयोग किया जाये, तो छोटी नहरें बन सकती हैं।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है। परन्तु यह रेलवे के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका प्रयोग केवल तापीय संबंधी उद्देश्यों के लिए हो सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सिंगरौली में शीघ्र ही एक बड़ा तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाये।

देश में जल संसाधनों का राष्ट्रीक्षकरण एक उचित कदम है। मेरा अनुरोध है कि इस बारे में शीघ्र ही कानून लाना चाहिए क्योंकि तभी मध्यप्रदेश को उचित न्याय मिल सकेगा।

SHRI RAM SWARUP (Robertsganj) : I would like to draw the attention of the hon. Minister to the problems of Uttar Pradesh. The northern part of Uttar Pradesh is surrounded by the range of the Himalayas from where rivers emerge and cause heavy floods during rainy season. The southern part consists mostly of plateau and hills. The Central part is plains having rivers like Ganga, Jamuna, Ghagra etc. The water of these rivers is still to be tapped for which the Uttar Pradesh Government has submitted many schemes to the Centre. I hope the hon. Minister will take these into consideration.

I am thank ful for the assurance of setting up Atomic Power Station. Matatila in Jhanshi will be suitable site for this because it abounds in Granites. Also there will be no need of evicting people. Moreover it will be convenient to supply power to the backward areas.

The scheme of electrification of about 20 thousand villages by the Government is most welcome. The supply of electricity to the Harijan Colonies is a progressive step.

I would like to remind that while preparing anti-flood schemes of Ganga river, provision of funds should also be made for repairing and strengthening the embankments and bunds of Mirzapur. Such steps may also be taken for Jaunpur and other cities.

Mirzapur, Allahabad and Varanasi are such districts where droughts often take place. It experiences great shortage of foodgrains and water. For giving releif to this area the Government had prepared Bansagar Scheme but it has not been materialised. The Government should take up this scheme for implementation. Alternatively the Government can ask the U. P. Government to utilize the water of Sone river to give it to Mirzapur. If the U. P. Government does not take up this scheme, then the Centre can take over it. With these words, I support the Demands of the Ministry.

श्री पी. के. देव (कालाहांडी) : वर्ष 1901 में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया था। इसने अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर देश में सिंचाई योजनाएं बनाई गई थी। लगभग 70 वर्ष पश्चात डा० के० एल० राव ने 1969 में सिंचाई आयोग नियुक्त किया जिसने अपने प्रतिवेदन में तीस वर्ष की योजना अवधि में लगभग 10,000 करोड़ रुपये व्यय करने की सिफारिश की थी जिससे 50 प्रतिशत फसल वाली भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सके। परंतु इसमें भी कुछ दोष थे।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

अन्तर-राज्य विवादों को सुझलाने के लिए आयोग ने सर्वप्रथम नदी बेसिन आयोग के स्तर पर बातचीत करने का सुझाव दिया है। इसके असफल होने पर दोनों पक्षों को समझाया जा सकता है। तीसरा विकल्प राजनैतिक दबाव को उपयोग में लाना है। यह राजनैतिक दवाब जल-संसाधन परिषद से आ सकता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करती हैं।

जहां तक इस्पात का कारखाना लगाने का संबंध है, उड़ीसा इसकी सब शर्तों को पूरा करता है। इसका समर्थन डा. एम. एन. दस्तूर ने भी किया है। उनके अनुसार उड़ीसा में इस्पात का कारखाना लगाने से इस्पात की उत्पादन लागत में बहुत कमी आयेगी, परन्तु इसके बावजूद भी इस तथ्य की उपेक्षा की जा रही है। हमें इस बात का भय है कि अन्य राज्य, जिनका प्रभाब है, जल संसाधन परिषद से अपनी बात को मनवाने की स्थिति में हैं।

इस आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि अन्य उपाओं के असफल हो जाने से अनुच्छेद 262 का आश्रय लिया जा सकता है। अनुच्छेद 262 के अनुसार इस उद्देश्य के लिए न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जा सकती है जिसके निर्वाण के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। कृष्णा-गोदावरी न्यायाधिकरण तथा नर्मदा न्यायाधिकरण पर बहुत समय धन तथा शक्ति व्यय की गई। अब एक नया विचार प्रस्तुत किया गया है कि इस संबंध में प्रधान मंत्री को मध्यस्थता करने को कहा जायेगा और इन विवादों को राजनीतिक दवाब से सुलझाया जायेगा। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को राजनीतिक दवाब से सुलझाया जाये, ब्राह्मणी नदी में बाढ़ के पानी रोकने के लिए उड़ीसा सरकार ने सिंचाई आयोग को विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत की थी, बे ब्राह्मिणी नदी से जल का मोड़ इस प्रकार ले जाना चाहते थे जिससे इस नदी के दोनों ओर की उपजाऊ भूमि जलमग्न न हो। यदि यह क्षेत्र जलमग्न होता है तो यहां के विस्थापितों का पुनर्वास करना कठिन हो जायेगा। रंगाली बांध से केवल 100 वर्ग मील के क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सकता है, केवल इतने क्षेत्र को बचाने के लिये 120 वर्ग मील की भूमि, जो अत्यन्त उपजाऊ है, को जलमग्न किया जा रहा है। इससे वहां के निवासियों में भय की भावना फैल गई है, मैं मंत्री महोदय को बता देना चाहता हूं कि रंगाली बांध से समुद्री तूफान, बाढ़ से रक्षा नहीं की जा सकती है। उड़ीसा सरकार ने अन्य बांध बनाने की जो योजनाएं भेजी है, यदि इसको क्रियान्वित किया जाये तो रंगाली बांध की आवश्यकता

नहीं होगी, मैं यहां मंत्री महोदय से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि रंगाली बांध की योजना क्रियान्वित नहीं की जायेगी, जिससे कि वहां के लोगों में व्याप्त आशंका तथा भय को दूर किया जा सके। आज भूमि पर इतना भार बढ़ता जा रहा है कि अन्य देशों में समुद्र को भी कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न चल रहा है और यहां सरकार भूमि को जलमग्न करने जा रही है।

मेरा यह सुझाव है कि धम्र मुहाने का, जहां ब्राह्मणी और वैतारिणी समुद्र में मिलने से पूर्व आपस में मिलती है, तलकर्णपा किया जाये ताकि जल का प्रवाह ठीक रहे और बन्द पड़े हुए चन्द-बाली बंदरगाह को चालू किया जा सके।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि उड़ीसा में फालतू विद्युत की समस्या है परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। राज्य में विभिन्न ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं, इलेक्ट्रो-कैमिकल्स उद्योग आदि स्थापित करने के उपरान्त यहां विद्युत की कमी पड़ जायेगी। इसलिए इन्द्रवती परियोजना पर कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए, जिससे राज्य में बिजली पैदा की जा सके तथा भूमि की सिंचाई की भी व्यवस्था हो सके।

SHRI R. S. PANDEY (Rajnandgaon) : The question of irrigation has economic aspect. It is related to our economic policy, farmer, foodgrains *etc*. As such it should be given highest priority. No other country in the world has so many rivers as ours.

It was envisaged that about 158 million hectares of land would be brought under irrigation but only 82 million hectares of land could be irrigated. It is my submission that work on the irrigation projects must be carried on war level or on massive scale. This will need the provision of 500 crores of rupees. If this is not made available then all the irrigation projects will remain on papers only. We have given slogan of '*Garibi Hatao*' and this can only be achieved if proper attention is given to irrigation projects. To-day the farmer is no more ignorant. He wants water. Had these been desert here, then we would have blamed the nature. But there is abundance of water resources in our Country.

May I ask from the hon. Minister whether it is not a fact that Madhya Pradesh has one fifth of the whole water in the country and the rivers are full of water ? Is it not true that many irrigation projects for this state are lying incomplete. The Narmada river project has been with the tribunal and the matter is still unresolved. It should be withdrawn from the tribunal and transferred to the Prime Minister for her verdict. All these tribunals, Courts, witnesses and reports are of no use. Only our Prime Minister is capable of resolving this impasse.

So far as the power is concerned, Korba thermal plant can supply power to many States. We are in abundance of natural resources. Efforts should be made to exploit coal. Madhya Pradesh has vast resources of water. For the exploitation of this water, provision of Rs. 200 crores should be made. It is my submission that a special Commission should be appointed for the purpose of surveying the water potentiality in the state.

To-day Madhya Pradesh is not getting fair deal from the Government. The hon. Minister should do something for Madhya Pradesh. Given proper consideration it can serve the country in a big way. I urge the Government to make provision of funds to execute schemes in Madhya Pradesh.

DR. GOVIND DAS RICHHARIYA (Jhansi) : Last year, the country faced two challenges. One of the challenges was sent by nature in the form of floods *etc*. and the other was from Pakistan.

The great impediment in the way of improving irrigation is that all the states claim on water of their respective areas. Water is a national property and the whole nation has a right to utilize it.

The rivers which flow in two or more States, may be surveyed by Central Government which should distribute the water and power among the States. This would end the disputes of Narmada valley, Cauvery etc.

The plans to link Ganga with Cauvery and Brahamputra with Ganga may be surveyed by 15th August.

Of the plans sent by U. P. Government, the orders for Tehri-Garhwal dam have not been issued.

We are gratful that you are convening a meeting of Chief Ministers of U. P. and Madhya Pradesh.

I congratulate you and your staff for arranging more facilities for irrigation and power.

SHRI NATHU RAM MIRDHA (Nagaur) : In the sphere of irrigation and power ample developments have been made. Still there is much scope for the work to be done.

With all the irrigation facilities, we are able to irrigate 810 lakh hectares of land. In the last 20 years we were able to arrange for irrigation facilities for 188 lakh hectares of land at a cost of 2000 crores of rupees. It is sad that we are not able to utilize this potential in 38 lakh acres. This means that we are incurring a loss of 350 crores of rupees every year. This is a very serious matter. Our policy of development of irrigation facilities deserves appreciation. If the people of Madhya Pradesh wanted to utilize Narmda water, the dispute between Maharashtra and Gujarat would not have arisen. The Planning Commission and Central Government agreed to give water to Rajasthan after the development of Narmada, but the tribunal has not accepted it. The Government should see if it can be changed. This State is dry in itself. It can get water from other States.

The first phase of Rajasthan Canal will be completed by 1974 and it will irrigate areas upto Chhattisgarh.

There has been ample development in rural electrification. In the sphere of irrigation from ground water our progress is ahead of targets fixed. But the areas which are still ignored in respect of rural electrification and irrigation deserves more attention.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION & POWER (SHRI B. N. KUREEL) : The hon. Members have given many valuable suggestions which will receive our due attention.

It is true that there is shortage of power but it is not because there has been decline in production of power. The fact is that the consumption of power is on the increase and

it is attributed to the farmers who use it for their tube wells. The installed generated capacity of power in this country 17 million Kilowatt which was planned to enhanced to be 23 million Kilowatt during the fourth plan. By the end of fourth plan it is likely to be 20 million Kilowatt. In the fifth plan period there is a proposal to enhance the capacity by further 20 million Killowatts.

The electricity Boards are not able to meet the growing demand of electricity due to shortage of funds.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI (Morena) : There is no quorum in the House.

MR. CHAIRMAN : The quarum bell is ringing. Now there is quorum.

SHRI B. N. KUREEL : In the sephere of rural electrifications, rural electrification compensation given about 133 crores of rupees for 211 schemes in backward areas.

SHRI K. M. MADHUKAR : To what percentage you have given? Have your observed the slow progress?

SHRI B. N. KUREEL : I have complete statistics. I shall pass them on to you.

Shri Mayavan has said that the amount sanctioned for electrification of 1200 villages is insufficient. There is some misunderstanding in this regard. The amount is intended to give facilities to Harijans who have not been given the facility even after electrification of their villages. Though small, this is a step towards socialisation. There are various difficulties in underdeveloped villages, such as absence of roads, non-availability of drinking water, absence of drains and accumulation of rain water. Our Engineering Deptt. is surveying at these matters in 25 districts of 17 States. There would be 550 teams comprising of nine persons, two graduate engineers, one surveyor, one tracer and two unskilled persons. These teams would submit their reports for the betterment of villages to the Central Government.

There were grave floods in 1954 and thereafter we have lost property worth 2370 crores of rupees in floods and 13976 lives were lost. We are trying to make our forecasting system more powerful, by equiping them with modern equipments and also to have new centres. In Bihar, a number of lives were saved due to this forecasting.

How do the floods come? It is because of embankments are overflooded and secondly due to lack of drains. Priority works have been sanctioned for this; schemes worth 27 crores of rupees in Bihar, worth 38 crore of rupees in Orissa, worth 21.5 crores of rupees in U. P. and worth 24.8 crores of rupees in West Bengal.

The U. P. Government has sent us ten schemes for electrification worth 741.95 crores of rupees. Two of them have been cleared. These have to go to Planning Commission.

SHRI K. M. MADHUKAR : Regarding North Bihar thermal power project . . .

MR. CHAIRMAN : Please do not interrupt and take minimum possible time so that others may have an opportunity to speak about their constituency.

SHRI B. N. KUREEL : The remaining eight schemes are being examined.

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे (सांगली) : इस लाइन में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय जल योजनाएं एक देश व्यापी वितरण पद्धति के अनुसार जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सिंधु जल को मीठा बनाने में भी प्रगति की है।

क्या हम अपने देश में ऐसी योजनाएं नही चालू कर सकते हैं ?

[श्री आर. डी. भंडारे पीठासीन हुए
Shsi R. D. Bhandari *in the Chair*]

सिंचाई प्राकृतिक प्रतिकूलताओं का सबल मुकाबला करता है।

पिछले दो वर्ष में सिंचाई क्षमताएं दुगुनी हो गई हैं। बिजली की क्षमता 20.3 लाख किलोवाट से बढ़कर 167.0 लाख किलोवाट हो गई है।

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 1950-51 में 18 युनिट से बढ़कर 90 युनिट हो गई है। ग्रामीण विद्युतीखरण कार्यक्रम में गतिशीलता आई है। विद्युतीकृत गांवों की संख्या 3600 से बढ़कर 1,14,000 हो गई है।

मेरा चुनाव-क्षेत्र सांगली सूखा-ग्रस्त क्षेत्र का एक-तिहाई भाग है। मंत्रालय के इस वर्ष की रिपोर्ट में सिंचाई परियोजना का एक विवरण दिया है जिसमें सांगली जिले का कोई उल्लेख नहीं है। जनता उसका कारण जानना चाहती है।

देश में विभिन्न विद्युत पद्धतियों का परस्पर संम्बध किया जा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में बिजली की कमी के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मेरे चुनाव-क्षेत्र मजार्डे में खुदाई करते समय एक पानी का फब्वारा मिला है जो कि एक चमत्कारी वस्तु है। वहां पर पानी खोजने के लिये विशेषज्ञ जायें। सिंचाई आयोग ने सूखा क्षेत्रों के लिये जो मानदण्ड रखे हैं, वह क्या हैं ?

प्रधान मंत्री ने बंगला देश के प्रधान मंत्री के साथ संयुक्त नदी आयोग का उल्लेख किया है। हमारे देश में अन्यर्राजीय जल विवाद वर्षों से चले आ रहे हैं।

कावेरी विबाद से सम्बद्ध सभी मुख्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। क्या हम अपने जल-स्रोतों को राष्ट्रीय सम्पत्ति मानेंगे ?

क्या प्रधान मंत्री सभी मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर जल-बिवादों का हल करेंगी ?

श्री गजाधर माझी (सुन्दरगढ़) : सिंचाई और बिजली का राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। हमने अपने किसानों को न तो सिंचाई सुविधाएं दी हैं और न ही उन्हें आधुनिक कृषि उपकरण दिये हैं। इसी लिये शिक्षित वर्ग कृषि कार्यों में भाग नहीं लेते।

उड़ीसा के 46000 गांवों में से 1300 में ही बिजली लगी हैं। सुन्दरगढ़ जिले में बिजली की व्यवस्था अपार्याप्न है। पर्वतीय आदिवासी क्षेत्रो में बिजली है ही नहीं। मेरे जिले के किसानों

को हर वर्ष सूखे का सामना करना पड़ता है। उनके लिये हरित क्रांति एक स्वप्न है। सुन्दरगढ़ क्योझर और कोरापुर जिलों में अभी तक भी कोई लघु सिंचाई योजना आरम्भ नहीं की गई। वहां पर भूमिगत जल के विकास का भी कोई कार्य नहीं हुआ।

सुन्दरगढ़ जिले में घोघर लघु सिंचाई परियोजना को चोथी केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत लिया जाये और सुन्दरगढ़ नगर को इस वर्ष नगर संरक्षण योजना क आधीन लिया जाये।

श्री निहार लास्कर (करीमगंज) : इस मंत्रालय का कार्य तो अत्तन्त महत्वपूर्ण है परन्तु इसके लिये समय और धन दोनों ही कम दिये जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में इसके लिए अधिक धन देगी।

मेरे राज्य में बाढ़ों की समस्या है। यदि आप इस संकट का मुकाबला करना चाहते हैं, तो ध्यान से करें। यह आप बड़ी नदी घाटी योजनाओं द्वारा कर सकते हैं।

असम में हर वर्ष बाढ़ आती है जिससे 4-5 करोड़ रुपये की क्षति होती है। हमारी मांगों पर ध्यान देते हुए दिसम्बर, 1969 में ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन हुआ था। परन्तु अब तक कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। केन्द्र को इस परियोजना का उत्तारदायित्व लेना चाहिये और जनता की बाढ़ों से रक्षा करनी चाहिये।

मुझे खेद है कि बाढ़ की भयानक समस्या की चारों पंच-वर्षीय योजनाओं में अवहेलना की गई है। मेरे जिले में एक छोटी सी योजना का कार्य आरम्भ किया गया था। परन्तु उसकी भी कुछ प्रगति नहीं हुई है।

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार मनीपुर में कुछ परियोजना आरम्भ करने जा रही है। मेरा सुझाव है कि लकटोक परियोजना तथा बेटेक परियोजना के साथ साथ आरम्भ किया जाये।

सिंचाई परियोजना इस प्रकार बनाई जाये जिससे देश की 75 प्रतिशत कृषि योग्य भूनि की सिंचाई की जा सके। गत वर्ष चार योजना अवधि में सरकार ने अतिरक्ति सिंचाई क्षमता उत्पन्न करने के लिए कोई सराहनीय कार्य नहीं किया है। सरकार को उन राज्यों के लिये कुछ करना चाहिये जिनके लिये गत वर्षों में कुछ भी नहीं किया गया है।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि एक चौथाई पन बिजली क्षमता असम में विद्यमान है किन्तु खेद है कि इस सम्बन्ध में संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया। केवल असम से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकता पूरी हो सकती है। किन्तु राष्ट्रीय ग्रिड के बारे में प्रगति बहुत धीमी है। इस कार्य के लिये केवल 40 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है जो बहुत कम हैं। यह आशा है कि आगामी वर्ष में असस के लिए उपयुक्त धनराशि दी जायेगी तथा बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं को आरम्भ कर दिया जायेगा।

SHRI VEKARIA (Junagarh) : It seems that Government would give due importance to the irrigation programmes as they did last year. The Government have given understanding that they would accept the recommendation made by the Commission regarding the utilization of hydro-power potential.

It has been observed that the industrial growth in the country is going downward due to the inadequate irrigation facilities available in the country. Our economy can be promoted only with the proper development in the field of agriculture.

Gujarat is a chronically drought affected State and the most backward area so far as the irrigation facilities are concerned. The hon. Deputy Minister has not said anything regarding the Narmada-project, the most important project for the State. The case is pending with the tribunal for a very long time. I request that early decision should be take in this matter.

The agricultural land in Gujarat is very fertile. But I am sorry to say that only 2 per cent of this land can yield two crops in year, while in other States this percentage varies from 20 to 70. In spite of the fact that adequate irrigation facilities are not available in Gujarat, the State produced 54,55 thousand tonnes of wheet.

We have to import cotton every year involving a heavy amount of Rs. 100 crores. Government can save the foreign exchange by increasing the production of cotton in Gujarat which is capable of it. In this cotext, I would like to urge upon the Prime Minister that she should take up the matter of Narmada project with the Chief Ministers of Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. I hope an amicable agreement could be reached on this issue. Therefore, the case should be withdrawn from the tribunal.

Due to the defective machinery supplied by an American Company for Tarapore Atomic Plant, it cannot work regularly causing power interruption to the Gujarat State. I demand that the said defects in the machinery should be removed. It should also be ensured that in future all such proposed plants are saved from such defects.

I would like to know from the hon. Minister the time by which the work on proposed atomic plant in Gujarat would be started. I am strictly opposed to the proposal of selling the Porbander Thermal Power Station to the Birlas. Government should look into this matter and cancel the deal if any, in this regard. With there words, I support the demands of the Ministry.

SHRI M. C. DAGA (Pali) : It has been observed that most of the dams constructed under the irrigation schemes give way due to the substandard material used in them because of the fact that fifty per cent of the amount allotted for these works goes in the pockets of the engineers.

The distribution of water is unfair. Small farmers are getting no benefits from the dams and reserves made by the Government. Actaully, they are made for big agriculturists. Thousands of engineers employed by your department are sitting idle. Several schemes regarding soil testing, survey *etc.* are made by the Government but they are never implemented properly. I may say that these schemes are implemented only in the constituencies of the Ministeries while the interest of the needy persons in other areas are ignored badly. I would also like to point out that the major portion of the amount is incurred on the engineers and not on the actual work.

श्री बी. वी. नायक (कनारा) : क्या यह सच है कि छोटी सिंचाई परियोजनाओं और बड़ी परियोजनाओं की लागत में भारी अन्तर है ? मेरा सुझाव है कि सरकार को अब छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक बल देना चाहिये ।

मेरा यह भी सुझाव है कि सभी राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में समान कदम उठाये जायें तथा सभी क्षेत्रों में समान रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण करना चाहिये ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

सिचाई सुविधाओं के बारे में आंकड़ों से पता चलता है कि तमिल नाडु में प्रति हजार व्यक्ति 75 हैकटेयर, आंध्र में 105 हैकटेयर तथा भौरा में 53 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता है । इस स्थिति में मैसूर राज्य से तुंगभद्रा परियोजना से पड़ौसी राज्यों को जल दिये जाने का अनुरोध किया जाना अनुचित है क्योंकि उन राज्यों के अधिकार में पहले ही भारी क्षमता है । ऐसा करने से राज्यों के बीच भारी भेदभाव उत्पन्न हो जायेगा ।

माननीय मंत्री के अनुसार महाराष्ट्र, मैसूर और केरल में पश्चिम की ओर बढ़ने वाली नदियों की सिंचाई क्षमता 58 लाख एकड़ है जब कि उसमें से केवल 18 लाख एकड़ की क्षमता का उपयोग किया गया है । शेष 40 लाख एकड़ की सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिए सरकार को तेजी से कार्य करना चाहिये जिससे असिंचित भूमि को पानी मिल सके ।

बेलगांव जिले में तत्री नल्लाह परियोजना अभी तक आरम्भ नहीं हो पाई है क्योंकि उसमें कुछ राजनीतिक नेताओं के दिलों को धक्का लगता था । मेरा निवेदन है कि सरकार को इस योजना की ओर ध्यान देना चाहिये ।

काली नदी परियोजना के कार्य की प्रगति धीमी होती जा रही है तथा उसके लिए पर्याप्त धन राशि भी नहीं दी गई । इस परियोजना से 209 पैसे की दर से बिजली मिल सकती है । अतः यह परियोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए ।

SHRI BHAGIRATH BHANWAR (Jhabua) : Sir, the case of Narmada Project should be withdrawn from the tribunal and the dispute should be solved by the Chief Minister of the concerned States so that the farmers may get benefits from this project at an early date.

I also suggest that the necessary equipments for boring the Tube-wells in the hill areas should be provided by the Government to the farmers of those areas. It has been observed that in most of the cases people do not get water from the wells dug by the farmers.

In certain areas such as Jhabua, Ratlam, Khargone *etc.*, power is not available to farmers causing continuous backwardness in those areas. I again request that the Narmada Project should be implemented as soon as possible. With these words I support the demands.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Sir, the water of the canal in Chambal velley is not available to the farmers as it goes under the ground causing marsh. We received the complaint that engineers divert the flow of the water towards rivers.

I suggest that Government should undertake plantation programme ro check the soil erosion. Government should also check sadimentation in rivers to minimise the flood havoc. Small reservoirs should also be constructed in the rural areas for irrigation purposes.

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : आंध्र प्रदेश सरकार ने परियोजना रिपोर्ट तथा 33.52 करोड़ रुपये की लागत वाली सोमसिला परियोजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में स्वर्ण रेखा परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है। क्या इस परियोजना को अगली पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने की कोई संभावना है और क्या यह कार्य दामोदर घाटी निगम की तरह किसी एक केन्द्रीय अधिकरण को सौंपा जायेगा ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अब पुनर्वन्यकरण के कारण इन परियोजनाओं को दबाया जा रहा है। मंत्री महोदय का इस वारे में क्या कहना है ?

सिंचाई और बिद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

स्वाधीनता की रजत जंयती वर्ष में हम सिंचाई और ग्राम्य विद्युतीकरण सम्बन्धी उपलब्धियों के क्षेत्र में गर्व के स्वथ पीछे मुड़कर देख सकते हैं। आजादी के समय की तुलना में हमने अपनी सिंचाई व्यवस्था को दुगुना कर दिया है । जिसके फलस्वरूप हम अपने कृषि उत्पादन को भी दुगुना कर सके हैं। लेकिन हमारी जनसंख्या भी बड़ी है । और समस्याएँ भी बड़ी हैं। हमें सावधान रहना है। हमें अपनी सिंचाई क्षमता को हर हालत में दुगुणा करना है। हमने राजस्थान नहर, सरजू, उपरी कृष्णा, गंदक, नाग्यर्जुनरसागर आदि आदि परियोजनायें चलाई हैं। इन पर काफी धन लगाया गया है लेकिन इनका लाभ हम अभी नहीं उठा सके हैं। पांचवी परियोजना के प्रारूप में हमने कहा है कि इन परियोजजाओं को पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जाये।

वर्ष 1973-74 तक पश्चिम बंगाल में 38 प्रतिशत सिंचाई व्यवस्था हो जायेगी जबकि समूचे भारत का औसत प्रतिशत 27 है। तस्ता परियोजना पर भी हम विचार कर रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में हम बंगला देश सरकार से भी समझौता कर सकते हैं। गंडक परियोजना पर योजना के अन्त तक हम लगभग 160 करोड़ रुपये व्यय कर चुकेंगे। लेकिन इस परियोजना का उचित ढंग से उपयोग नहीं किया गया।

पर्वतीय क्षेत्रों की सिंचाई के बारे में भी सुझाव आये हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर के पहाड़ी क्षेक्षों की सुन्दर ढलानों को मैंने देखा है। एक या दो हजार फीट नीचे सरिता बहती जाती है और ऊपर वहां के निवासी पीने और सिंचाई के पानी के लिये तरसते हैं। हमने इन क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। वहां कोई बांध नहीं बनाये जा सकते। केवल पम्प द्वारा पानी उठाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरीखे राज्य में बिजली की कमी नहीं है। वहां बिजली द्वारा पानी उठाया जा सकता है और लोगों की कठिनाईयों को दूर किया जा सकता है। खेद है कि यहां की राज्य सरकारों ने इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया। इन राज्यों से हमारे

पास सिंचाई सम्बन्धी कोई भी योजनायें नहीं आयीं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य सरकारों से इन योजनाओं को इधर भिजवायें ताकि हम उन पर विचार कर सकें।

घेगाची परियोजना के बारे में भी चर्चा हुई है। सरकार इस परियोजना को स्वीकृति दे देगी क्योंकि यह एक अनुसूचित परियोजना नहीं है। सब से अच्छा यह होता कि इसका लाभ इस नदी घाटी के क्षेत्रों के लिए ही सीमित रखा जाता क्योंकि ऐसा करना आसान भी होता। अतः केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग ने अपने विचार व्यक्त किये और मैसूर सरकार ने उत्तर देने में एक वर्ष का समय लगाया। केन्द्रीय जल एवं शक्ति आयोग ने पुनः अपने विचार मैसूर सरकार को भेज दिये हैं, जहां से अन्तिम उत्तर अभी तक नहीं आया। चूंकि यह नदी-विवाद में है, इस लिए लोगों को नई समस्यायें पैदा नहीं करनी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने तुंगभद्रा की चर्चा की। मैं भी वहां गया था, इस लिये नहीं कि मैं उस राज्य का निवासी हूं बल्कि इस लिए कि यह विभाग मेरे पास है। यहां पर लाखों एकड़ जमीन में सूखा पड़ रहा था और नागार्जुनसागर का जल स्तर छट चुका था। नहरों में बहुत कम पानी आ रहा था। हैदराबाद जाकर मैंने वहां की सरकार और मुख्यमंत्री से बातचीत की, जिस के फलस्वरूप दायें किनारे की नहर का गेट बन्द कर दिया गया।

इसके पश्चात बंगलौर जाकर मैंने मुख्यमंत्री से बातचीत की और पता चला कि मैसूर को किसी प्रकार का नुकसान नही हुआ। तालाब में अब भी पानी इतनी मात्रा में था जो नागार्जुन-सागर के जल स्तर के बनाये रखने के लिये पर्याप्त था। इसके अतिरिक्त पानी की सप्लाई को भी 15 से हटा कर 10 दिन कर दिया गया। इस प्रश्न पर मैं इस कारण इतना कुछ बोल गया कि अनेक माननीय सदस्यों ने इस बारे में कुछ आशंकाऐं व्यक्त कीं। हमने यह सब तेलंगाना क्षेत्र की फसलों की रक्षा के लिये किया।

कुछ माननीय सदस्यों ने नर्वदा परियोजना की चर्चा भी की। खेद है कि इस नदी के एक बूंद जल का भी उपयोग नहीं हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने एकमत होकर नर्मदा परियोजना विवाद को निपटाने की इच्छा प्रकट की है।

मध्य प्रदेश की सिंचाई सम्बन्धी चर्चा भी हुई है। मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि मध्य प्रदेश को अब तक सिंचाई की विश्व में पूर्णतः उपेक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश की सिंचाई सम्भावनाऐं पर्याप्त हैं। हमें वहां बहुत शीघ्र सिंचाई सुविधाऐं प्रदान करनी हैं। सिंचाई के लिये पांचवी या छटी परियोजना पर निर्भर नहीं होना चाहिये। इसके लिये हमें विशेष सहायता प्रदान करनी है। रंगाली के बारे में भी चर्चा हुई है। रंगाली बांध के अस्तित्व का मुझे कोई पता नहीं था। उड़ीसा के इन्जीनियरों ने मुझे इसकी जानकारी दी। ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा नदियों के बारे में भी हमें इसी प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : वर्ष 1937 में श्री विश्‍वेसरिया द्वारा ब्राह्मणी बाढ़ समस्या का अध्ययन किया गया था और उन्हीं के कहने पर, पानी को इकठ्ठा होने से रोकने के लिए जनपुर स्थित बांध को उड़ा दिया गया था।

डा० के० एल० राव : बहुत सारे इंजीनियरों ने इकट्ठे होकर यह निर्णय किया था कि स्थिति से निपटने का यही एक रास्ता है । यही कार्यवाही सुवर्ण रेखा के बारे में भी की गई है । मैं श्री देव के साथ इस बात पर पूर्णतया सहमत हूं कि इस का प्रभाव बहुत से गांवों और उपजाऊ भूमि पर पड़ने बाला है । परन्तु हमारे पास इसके सिवा और चारा ही क्या है ? हमारा प्रमुख उद्देश्य लोगों को कम से कम हानि पहुंचाकर, उन्हें अधिक से अधिक लाभ देना है ।

श्री रामस्वरूप द्वारा बनसागर परियोजना का उल्लेख किया था । सोन नदी के लिए बनसागर परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है । मध्य प्रदेश के रीवा और मिरजापुर जैसे ऊंचे क्षेत्रों के लिए यह बहुत लाभकारी हो सकती है परन्तु कठिनाई यह है कि वह यह भी चाहते हैं कि बिजली पैदा करने के लिए गंगा नदी में कुछ पानी डालना चाहिये । परन्तु मैं समझता हूं कि बिजली पैदा करने की अपेक्षा सिंचाई का कार्य अधिक महत्व पूर्ण है । परन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि मैं मध्य प्रदेश के साथ किसी प्रकार का भेदभाव कर रहा हूं । हमें तो प्रत्येक समस्या को सम्पूर्ण राष्ट्र की भलाई में देखना पड़ता है ।

श्री मिर्धा द्वारा नागौर से जल उपलब्ध करवाने के बारे भी एक सुझाव दिया गया है । नागौर एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । अब राजस्थान नहर उस स्थान के नजदीक पहुंच गई है । अतः अब यह सुझाव हम राजस्थान सरकार को भेज देगें ।

बहुत से सदस्यों ने बाढ़ की समस्या का उल्लेख किया है । बाढ़ें निश्चय ही हमारे देश को भारी हानि पहुंचा रही हैं । सरकार इस बात का अनुभव कर रही है । इस समस्या को उचित महत्व दिया जाना चाहिए । इसीलिए बाढ़-ग्रस्त चार राज्यों के लिये कई प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है । इसके साथ ही राज्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त अब भी दिया जायेगा । ब्रह्मपुत्र नदी के कार्य को अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर भी सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है हम एक ऐसी योजना बना रहे हैं जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार इस पर कार्य कर सके । **(व्यवधान)**···

मैं अभी गंगा-कावेरी को जोड़ने के प्रश्न को भी लूंगा । अभी इंजीनियरों के अभाव के कारण गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने कार्य करना आरम्भ नहीं किया है । इसके लिऐ अभी उपयुक्त योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं । अतः इस कार्य को पूरा होने में दो या तीन वर्ष का समय लग जायेगा ।

दक्षिण और बिशेषतया तमिलनाडु के हमारे कुछ सदस्य गंगा-कावेरी लिंक के बारे में जानने के इच्छुक हैं । यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी नदियां पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और उत्तर-पूर्व की ओर बहने वाली एक भी नदी नहीं है । इसीलिए अब हम देश में एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इससे नौवहन तथा पानी की सप्लाई सम्बन्धी सुबिधाएं प्राप्त हो सकती थी । परन्तु इस कार्य को आरम्भ करने से पहले बहुत बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कार्य करना आवश्यक है । अतः इसी कार्य के लिए हमने अमरीका से विशेषज्ञों

का एक दल बुलवाया है। आशा है कि ये लोग जुलाई तक अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे। इसके पश्चात अपने इंजीनियरों के साथ विचार-विमर्श करके हम आगे के लिये अपेक्षित कदम उठायेंगे ।;

ग्राम्य विद्युतीकरण के सम्बन्ध में निश्चय ही हमने सराहनीय प्रगति की है। चौथी योजना के दौरान हमारा लक्ष्य 50,000 ग्रामों को बिजली देने और 12.5 लाख पम्पिंग सेट लगाने का था, परन्तु इस क्षेत्र में हमारी प्रगति इतनी संतोषजनक रही हैं कि हमने अपने इन लक्ष्यों का पुनरीक्षण कर उन्हें 75,000 ग्राम और 15 लाख पम्पिंग सेट कर दिया है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में यह कार्य बहुत सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है। इन तीनों ही राज्यों में मुख्य मंत्रियों को मैंने प त्र लिखे हैं, जिनमें इस दिशा में और अधिक प्रयत्न करने का अनुरोध किया गया है।

हरिजन बस्तियों के बारे में कुछ भ्रामक धारण बन गई है। अब तक 1,18,000 गांवों को बिजली दी गई है परन्तु इनमें से कुछ हरिजन गांवों को बिजली नहीं दी गई है। प्रधान मंत्री द्वारा भी इस मामले का कुछ उल्लेख किया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसा केवल अनजाने में ही हो गया है। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि भविष्य में किसी गांव में किसी भी हरिजन बस्ती को नहीं छोड़ा जायेगा।

देश में बिजली का उत्पादन प्रत्येक योजना में 40 लाख किलोवाट से 50 लाख किलोवाट की दर से बढ़ता रहा है। इस समय देश में 1 करोड़ 70 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और वर्ष 1974 में यह उत्पादन बढ़कर 2 करोड़ किलोवाट हो जायेगा। हमारे देश में बिजली की बहुत कमी है। इसलिए हमने पांचवीं योजना में बिजली के उत्पादन को दुगुना करने का कार्यक्रम बनाया है। उसके अनुसार यह उत्पादन 2 करोड़ किलोवाट के स्थान पर 4 किलोवाट हो जायेगा। सैद्धान्तिक रूप से हमारी यह योजना, योजना आयोग द्वारा भी स्वीकार की जा चुकी है।

यह खेद की बात है कि हमारी कार्य प्रणाली ही कुछ दोषपूर्ण है। एक राज्य में यदि बिजली का अभाव है, तो दूसरे में उसकी बहुलता। परन्तु यह बहुलता वाला राज्य किसी अन्य राज्य को बिजली देने को तत्पर नहीं है और यदि है भी, तो वह उसके लिए अधिक मूल्य लेना चाहता है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में यह बात महत्वपूर्ण है कि बिजली का उत्पादन और उसके नियन्त्रण का सम्पूर्ण कार्य केन्द्र के हाथ में हो। मेरा विचार इस मामले को सिंचाई और विद्युत मंत्रियों के आगामी सम्मेलन के समस्त प्रस्तुत करने का है। उनके साथ तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ इस मामले पर बातचीत की जायेगी।

मैंने विद्युत प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच की है। इसके लिए मैं दो-तीन बातें आवश्यक समझता हूं। इनमें प्रथम यह है डिजाइन, आयोजन तथा जांच। यह कार्य तो केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा ठीक ढंग से किया जा रहा है। इसे हम और सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करेंगे

ताकि हम बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग कर सकें। इनका दूसरा पहलू कार्यान्वियन का है। इसके रास्ते में निश्चय ही कुछ कठिनाईयां होती हैं। इस सम्बन्ध में हमारा विचार क्षेत्रीय बोर्डों का पुर्नगठन करने का है। इन बोर्डों का सांविधिक बोर्ड बनाने के लिए एक बिधेयक लाया जायेगा ताकि यह अधिक कारगर ढंग से अपना कार्य कर सके। तीसरा पहलू देश में बनाये जाने वाले सामान का है। इस कार्य को करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक कक्ष बनाया जा रहा है जो कि मशीनों आदि के मूल्य तथा अन्य सम्बद्ध समस्याओं का निपटारा करने का प्रयत्न करेगा।

मेरे माननीय मित्र ने कालन्दी का उल्लेख किया है। हम इसके महत्व को पूर्णतया समझते हैं। यह ठीक है कि मैसूर के पास कुछ फालतू बिजली है, परन्तु वह बिजली इतनी ज्यादा नहीं है। मेरे अनुरोध पर मैसूर सरकार ने महाराष्ट्र और गुजरात को कुछ विजली दे दी है। मैसूर सरकार का योगदान निश्चय ही सराहनीय है। यदि इस प्रकार की भावना सभी राज्यों में हो जाये, तो बहुत सी समस्यायें स्वयं ही समाप्त हो जायें। वैसे तो यह जो कमी है, यह अस्थायी है, क्योंकि ज्योंही तारापुर एकक चालू हो जायेगा, यह कमी दूर हो जायेगी। इसी प्रकार ध्रुवरन एकक के कार्य आरम्भ करते ही गुजरात की कमी भी शीघ्र ही दूर हो जायेगी। कालन्दी परियोजना के सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस परियोजना के दूसरे चरण पर परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में केवल धन की कठिनाई ही हमारे समक्ष है। इस योजना पर 165 करोड़ रुपया खर्च होने की सम्भावना है जबकि मैसूर सरकार के पास इसके लिए केवल 15 करोड़ रुपया ही उपलब्ध है।

मैं समझता हूं कि मैंने अधिकांश प्रश्नों का उत्तार दे दिया है। हां उत्तार बिहार तथा उत्तार बंगाल का प्रश्न भी उठाया गया था। इन क्षेत्रों में जनसंख्या तो बहुत घनी है परन्तु बिजली बहुत कम है। उत्तार बिहार के लिए बरोनी ही एक बिजली घर है। इसलिए हम मुजफ्फरपुर में एक बिजली घर स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार उत्तर बिहार में दकौला में एक अन्य बिजली घर बनाया जा रहा है जो कि उत्तर बिहार तथा उत्तार बंगाल के पूर्वी भाग की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तकनीकी सलाहकार समिति की आगामी बैठक में इन परियनाओं को पास कर दिया जायेगा।

श्रीमान जी, मैं समझता हूं कि मैंने काफी समय ले लिया है। पिछले 25 वर्ष तो हमने पिछड़े हुए भारतवर्ष की सेवा करने में लगा दिये हैं। परन्तु आगामी वर्षों में भारत के 100 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये आगामी 25 वर्षों के लिए अपनी योजनायें बनायेंगे। अन्त में, मैं सभी उपस्थित साथियों से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे मंत्रालय की मांगों का समर्थन करें।

सभापति महोदय : अब मैं एक साथ सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए सभा के समक्ष रखता हूं।

सभापति द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The cut motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की वर्ष 1972-73 की निम्नलिखित मागें सभा में मतदान के लिए रखी गईं तथा पूरी पूरी स्वीकृत हुई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
58	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	8,40,96,000
59	सिचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाएं	3,15,78,000
60	विद्युत योजनाएं	3,05,83,000
122	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	9,91,79,000
123	सिंचाई विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	27,25,99,000

इसके पश्चात लोक-सभा 12 अप्रैल 1972/ 23 चैत्र 1894 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 12th April, 1972/23 Chaitra, 1894 (Saka)

———

Printed at The Bengal Press, Delhi-6